R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 I अंक : 06
16 से 31 दिसम्बर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मोहन 'राज' का एक साल
विकास-सुशासन का कमाल

सीएम डॉ. मोहन यादव के फैसलों ने बदली मप्र की सूरत

विकसित मप्र और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय

सेवा सुशासन और जनकल्याण का अडिग संकल्प

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नागरिक सुविधा और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तकनीकी सुधार डिजिटलाइजेशन, ई-रिकॉर्ड के माध्यम से आम-जन के कार्यों को आसान बनाना और हितधारकों को सीधा लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

सरकार ने सुशासन और नागरिक सेवा को प्राथमिकता देकर हर वर्ग का लाभ सुनिश्चित किया है। इन अभूतपूर्व प्रयासों से मध्यप्रदेश अब उन्नति के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

- नामांतरण, बंटवारा जैसे विभिन्न राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए सभी 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य।
- संपदा 2.0 रजिस्ट्री के लिए ई-पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग की नवीन प्रणाली। दस्तावेजों के ऑनलाइन निष्पादन, वीडियो वेरिफिकेशन आदि कार्य होंगे आसान।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन। कानून व्यवस्था के साथ बड़े पैमाने पर किए गए विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण।
- राजस्व महाअभियान के दोनों चरणों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने का निर्णय।
- मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री अब स्वयं भरेंगे अपना इनकम टैक्स।
- प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर 1 जुलाई, 2024 से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट की व्यवस्था शुरू।
- वॉरंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।
- प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% माता-पिता को देने का निर्णय।
- 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर डीम्ड अनुज्ञा प्राप्त करने और 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों पर त्वरित अनुज्ञा प्रदान करने की व्यवस्था लागू।
- बालाघाट के कमकोदादर में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को धूल चटाने वाले 24 शासकीय पुलिस सेवकों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
- प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य तेजी से जारी।
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% आरक्षण।
- भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण।

इस अंक में

तैयारी

8 | अब लगेगी 10 गुना पेनाल्टी

मप्र सरकार अब जनविश्वास कानून बनाने जा रही है। इसमें उद्योग, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कानूनों की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा समय...

डायरी

10-11 | बड़ी-बड़ी बैठकें...

मप्र में जबसे अनुराग जैन ने प्रशासनिक मुखिया की कमान संभाली है, व्यवस्था में अनुशासन दिखने लगा है। मुख्य सचिव स्वयं तो सक्रिय रहते ही हैं, अफसरों को भी सक्रिय रखते हैं। इसके लिए अफसरों के साथ लंबी-लंबी...

इंदौर

15 | फर्जी बिल घोटाला...

8 माह पहले नगर निगम में फर्जी बिल महाघोटाले की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। अब नगर निगम अपने स्तर पर इस महाघोटाले की जांच कर रहा है और उस जांच के मुताबिक 692 बोगस फाइलों के जरिए 91 करोड़ का फर्जी भुगतान ठगोरी फर्मों ने निगम खजाने...

खेती किसानी

18 | समय पर चावल नहीं दिया तो...

मप्र में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदी 2 दिसंबर से शुरू हो गई है। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 और धान ग्रेड-ए का 2,320 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जा रही है। वहीं सरकार ने धान...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 13 दिसंबर को एक साल पूरा कर लिया। मप्र में 2003 से लेकर अब तक के मुख्यमंत्रियों के शासनकाल का आंकलन किया जाए तो एक साल में मोहन 'राज' (मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शासनकाल) में जितना नवाचार, विकास हुआ है और कानून व्यवस्था सुधरी है, उतना पहले कभी नहीं देखा गया। मोहन 'राज' के एक साल में विकास और सुशासन का कमाल देखने को मिला है।

32-33

34

44

45

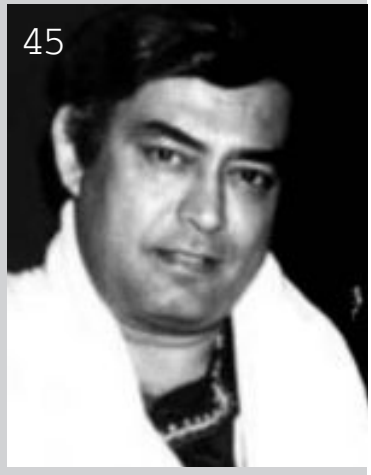

राजनीति

30-31 | अब दिल्ली फतह की जंग

दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही अभी चुनाव आयोग ने कोई घोषणा न की हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से चुनावी घोषणाएं करने लगे हैं। हर राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर दिल्ली जीतना चाहता है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पहले ही कह चुके हैं...

महाराष्ट्र

35 | दो सियासी खानदानों...

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महायुति की शानदार जीत ने दो सियासी खानदानों का सूपड़ा साफ कर डाला है- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेता शरद पवार और शिवसेना के उद्धव बालासाहब ठाकरे। दोनों नेताओं ने सूबे की उथल-पुथल भरी...

उप्र

37 | मुलायम वाले तेवर में...

समाजवादी पार्टी (सपा) ने साल 2012 के उप्र चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर सूबे में सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही थे। मुलायम की बात करने के पीछे दो कारण हैं।

6-7 अंदर की बात
39 पड़ोस
40 विदेश
42 महिला जगत
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-06, पृष्ठ-48
16 से 31 दिसंबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

गारंटी पीरियड की सड़क... गारंटी नहीं

म प्र की राजधानी सहित प्रदेशभर में सड़कों का बुरा हाल है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा ही एक मीम है...

गारंटी अवधि की सड़कें हुई बदहाल
ठेकेदार और अफसर दोनों मालामाल

मप्र में ऐतिहासिक रूप से सड़कों का जाल बिछाया गया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार अरबों रुपए व्यय कर रही है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की कर्तव्यहीनता व गुणवत्ताहीन निर्माण, सड़कों की दशा बयां कर रहा है। आलम यह है कि निर्माण के चंद दिनों में ही कई सड़कें जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। इन सड़कों पर चलना, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उक्त सड़क किस विभाग ने, किस ठेकेदार ने, किस इंजीनियर ने बनाई है। इसकी वजह यह है कि सड़कों पर निर्माण से संबंधित बोर्ड लगाए ही नहीं गए हैं। ऐसे में जनता भी दुर्दशा का दंश झेलने को मजबूर है। गौरतलब है कि कोई भी निर्मित सड़क ठेकेदार द्वारा विभाग को हैंडओवर करने की अवधि से तीन साल की गारंटी होती है, इस अवधि में सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित ठेकेदार को उस सड़क की मरम्मत करनी होती है। इसके लिए संबंधित ठेकेदार की कुल भुगतान की करीब 5 प्रतिशत राशि अमानत के रूप में विभाग के पास जमा रहती है, जहां सड़क की गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात ठेकेदार को अमानत राशि वापस की जाती है। यही नहीं निर्मित सड़कों का विभाग के सब इंजीनियर द्वारा जायजा लेकर समय-समय पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन दूरदराज की बात कौन कहे, राजधानी भोपाल में ही इसका पालन नहीं होता है। स्पष्ट है कि ठेकेदार को संरक्षण देने के चक्कर में सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट नहीं बनाई या कहें छिपाई जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि गारंटी अवधि के सड़कों की मरम्मत को लेकर अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गए हैं। इस स्थिति पर कहा जा रहा है कि गारंटी पीरियड की सड़कों की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल देश में सड़क निर्माण परियोजनाएं अलग-अलग तरीके से चलती हैं। सबसे प्रचलित तरीका ईपीसी है यानी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। ऐसी परियोजना में सरकार पैसा लगाती है और ठेकेदार इंजीनियरिंग, सामग्री खरीद और निर्माण करवाता है। इन परियोजनाओं में ठेकेदारों के लिए किसी प्रकार की कमी या खराबी को ठीक करने की गारंटी केवल 3 साल रहती है। उसके बाद रखरखाव और मरम्मत का जिम्मा सरकार के पास आ जाता है। सरकारी सिस्टम में ज्यादातर सड़कें ईपीसी के आधार पर ही बनाई जाती हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना है कि ईपीसी की सड़कों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। सामान्यतः बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल यानी टोल वाली सड़कों की गुणवत्ता अन्य सड़कों के मुकाबले ठीक रहती है। इन परियोजनाओं में सड़कों के रखरखाव की स्थाई जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है लेकिन सरकारी अधिकारियों की पर्याप्त मॉनीटरिंग और जरूरी कार्रवाई के अभाव में इन सड़कों के टूटने बावजूद मरम्मत और सुधार नहीं होता। जनता टूटी सड़कों पर चलने के बावजूद टोल देने को मजबूर होती है। वहीं देश में तेज रफ्तार के अलावा खराब सड़कें या हाईवे की गलत डिजाइन दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में सड़कों की गुणवत्ता सुधारकर हादसों को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। माना जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश की जीडीपी का करीब 3 प्रतिशत नुकसान होता है। लेकिन इससे सरकार और अफसरों का क्या लेना। जनता की कमाई पर सभी मालामाल हो रहे हैं और टैक्स देने वाली आबादी को जर्जर और गड्ढे वाली सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

– राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

नहीं थम रहा भ्रष्टाचार

देशभर में भ्रष्टाचार अब भी थम नहीं रहा है। मनरेगा में फर्जीवाड़े का आलम यह है कि कागजों पर जिन लोगों को मजदूरी करते दिखाया गया है उसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनका उसी दिन प्रसव हुआ है। यानी जब प्रसूता उठ-बैठ नहीं सकती, उन दिनों में मजदूरी करना बताया गया है।

● **राजविंदर सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

बदलाव की ओर कांग्रेस

मप्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने अब गांव स्तर तक पहुंचेगी। कांग्रेस प्रदेश में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करेगी। फील्ड में जाकर स्थिति देखने के बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी, समीक्षा के बाद नियुक्ति दी जाएगी।

● **गोपाल सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

कानून बनाने की जरूरत

डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर अपराध से जुड़ी दूसरी तकनीकों के जरिए लोगों से फर्जी फंड नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत विभिन्न शेल कंपनियों में भारी धनराशि हस्तांतरित की गई। आरोपियों ने फर्जी शेयर बाजार, निवेश और डिजिटल गिरफ्तारी, आदि का इस्तेमाल किया है। इसके लिए कानून बनाने होंगे।

● **मुकेश नानकानी,** मंदसौर (म.प्र.)

सड़कों की सुध ले सरकार

राजधानी में कई जगह विकास कार्यों के लिए सड़क की खुदाई तो कर दी, लेकिन सड़क नहीं बनाई। अब नीचे से उठने वाली धूल मिट्टी पुल के ऊपर से गुजरने वाले वाहन चालकों की आंखों में किरकिरी बन रही है। साथ ही नाक के रास्ते यही धूल शरीर में भी पहुंच रही है। राजधानी भोपाल में एक विडंबना यह भी है कि यहां सबसे अधिक विकास वीआईपी क्षेत्रों में होता है। इसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों में मंत्री, विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस के सरकारी आवास हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार जिन अफसरों के आवास पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनमें से 70 फीसदी के अपने मकान भोपाल में हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

● **अनुराग सेन,** भोपाल (म.प्र.)

चिंता में मप्र सरकार

वर्तमान समय में अगर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का आंकलन करें तो मप्र के 73 फीसदी क्लास-वन अधिकारी और 53 फीसदी क्लास-टू अफसरों की उम्र 45 साल से ज्यादा है। इसके अनुपात में क्लास-वन युवा अफसरों की संख्या 27 प्रतिशत तो क्लास-टू कैटेगरी के अधिकारी 47 प्रतिशत हैं। आने वाले 5 साल में सभी कैटेगरी के एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। इस स्थिति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है।

● **परशुराम मिश्रा,** इंदौर (म.प्र.)

ठोस कार्रवाई करे सरकार

हाल ही में राजधानी भोपाल से 1814 करोड़ की ड्रग्स और उसे बनाने वाले पदार्थ को जब्त किए जाने के साथ ही नशे के खिलाफ मप्र पुलिस का अभियान लगातार जारी है। मप्र पुलिस ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक पूरे प्रदेश में 6161 प्रकरणों में अवैध मादक पदार्थ के व्यापार में शामिल 7886 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **आनंद पुरोहित,** बैतूल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

भजनलाल शर्मा का बढ़ा कद

पिछले महीने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के साथ हुए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 में से 5 सीटों पर भाजपा को बड़ी जीत मिली। जबकि कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई। इस उपचुनाव में जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा वहीं भाजपा ने अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन किया। उपचुनावों से पहले कहा जा रहा था कि अगर भाजपा अपेक्षा अनुसार सीट नहीं जीत पाएगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में इस परिणाम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सियासी कद को बढ़ाया है, वहीं आगे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री के इतर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी इन नतीजों के बाद सियासी रुतबा बढ़ा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसका असर संगठन में भी देखने को मिल सकता है। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। ऐसे में इस परिणाम से मुख्यमंत्री को संजीवनी मिली है। इन नतीजों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सियासी कद को बढ़ाने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री बदलने के कयासों पर भी विराम लगाने के साथ ही अब माना जा रहा है कि पूरे पांच सालों तक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

ओवैसी बढ़ाएंगे आप की मुश्किलें

अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल अभी से गरमाने लगा है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने अपने कई सीटिंग विधायकों के टिकट काटकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जामई ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक का छोटा रिचार्ज कहते हुए निशाना साधा है और उनकी नीतियों को मुस्लिम-विरोधी बताया है। शोएब जामई ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को भारी समर्थन दिया, लेकिन उन्हें बदले में केवल धोखा मिला। उन्होंने दिल्ली दंगों और मरकज मामले में केजरीवाल पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई खास विकास का काम नहीं हुआ है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के बयान और उनकी रणनीति मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की ओर इशारा कर रहे हैं। एआईएमआईएम की रणनीति दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीनी स्तर पर काम करने और आम आदमी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की है। पार्टी का लक्ष्य इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर केजरीवाल को चुनौती देना है।

ब्याज दर में कटौती समाधान नहीं है

भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कामकाज संभाल लिया है। उनको भी उसी तरह वित्त मंत्रालय का अनुभव है, जैसे उनके पूर्ववर्ती शक्तिकांत दास को था। उन्होंने छह साल तक केंद्रीय बैंक के प्रमुख का पद संभाला। उनसे पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे। इन दोनों का कार्यकाल बहुत उतार-चढ़ाव का रहा। उर्जित पटेल के समय नोटबंदी हुई थी। सरकार ने 2016 के नवंबर में पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए थे। इस तरह एक झटके में देश की 85 फीसदी मुद्रा अवैध हो गई थी। उस झटके से उबरने में अर्थव्यवस्था को बहुत समय लगा था। इसी तरह शक्तिकांत दास के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा कोरोना महामारी में बीता। दोनों के कार्यकाल में यानी पिछले आठ साल में यह संकट बना रहा कि महंगाई काबू में करते हैं तो ब्याज दर को ऊंचा रखना पड़ रहा है और उसकी वजह से विकास दर में तेजी नहीं आ रही है। अंत में स्थिति यह है कि न खुदा मिला न विसाले सनम। महंगाई पर तो काबू नहीं ही पाया जा सका, विकास दर भी गिर रही है और भारतीय मुद्रा यानी रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर है। एक डॉलर की कीमत 85 रुपए तक पहुंच गई है।

नसीहत पर गौर करें

इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस से अलगाव का रुझान और आगे बढ़ा है। अब नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन का नेता बने रहना चाहती है, तो उसे यह स्थान मेहनत से कमाना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने ईवीएम में हेरफेर को लेकर रोने की प्रवृत्ति से कांग्रेस को बाहर आने की सलाह भी दी और कहा कि उसे चुनाव नतीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसके पहले गठबंधन के नेता के रूप में कांग्रेस या राहुल गांधी की हैसियत को ममता बनर्जी, शरद पवार और लालू प्रसाद यादव से प्रत्यक्ष एवं शिवसेना (उद्धव) और डीएमके से परोक्ष चुनौती मिल चुकी है। मुमकिन है कि इस प्रवृत्ति के पीछे प्रमुख कारण अडानी ग्रुप के खिलाफ राहुल गांधी के लगातार हमले और उनकी कुछ दूसरी नीतियां रही हों। इसके बावजूद वह वक्त अब निर्णायक मोड़ पर है, जब पार्टी को बन रहीं विपरीत परिस्थितियों पर गहन विचार-विमर्श करना चाहिए। यह तथ्य है कि कांग्रेस गठबंधन के अघोषित नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई।

महाराष्ट्र में ईडी के मारे मंत्री

महाराष्ट्र में आखिरकार मंत्रिमंडल का गठन हुआ। नतीजे आने के 22 दिन बाद और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के शपथ लेने के 10 दिन बाद 39 मंत्रियों की शपथ कराई गई। हालांकि विभाग अब भी नहीं बंटे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ के बाद कहा कि दो दिन में विभाग बंट जाएंगे। 39 नए मंत्रियों की शपथ के बाद सरकार में मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री सहित 42 मंत्री हो गए हैं। इन 42 में से अनेक मंत्री ऐसे हैं, जो केंद्रीय एजेंसियों के मारे हैं और एक समय जान बचाने को परेशान थे। लेकिन अब सभी के मुकदमे स्थगित हो गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिस पार्टी ने यानी जिस भाजपा ने इनके खिलाफ अभियान छेड़ा ये सभी लोग उसी की सरकार में मंत्री हैं। आइंस्टीन जिंदा होते तो इसके जरिए भी वे सापेक्षता का सिद्धांत समझा सकते थे। जाहिर है भाजपा के लिए भ्रष्टाचार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि पार्टी सापेक्षिक है। जो व्यक्ति भाजपा विरोधी पार्टी में रहकर भ्रष्ट होता है वह भाजपा के साथ आने पर ईमानदार हो सकता है।

खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है रंग

उपरोक्त कहावत को विंध्य क्षेत्र के एक जिले में साकार किया जा रहा है। दरअसल, खनिज संपदा से परिपूर्ण इस जिले में अवैध कारोबार जोरों पर चलता है। इसलिए इस जिले में जिस भी अधिकारी को पदस्थ किया जाता है, वह वसूली में जुट जाता है। ऐसा ही जिले के नए कप्तान कर रहे हैं। साहब की कार्यप्रणाली को देखकर स्थानीय लोग यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दरअसल, इस जिले में पूर्व में पुलिस की कप्तानी एक महिला आईपीएस अधिकारी कर रही थीं। उन्होंने तो अवैध कमाई के सारे रिकार्ड तोड़ दिए थे। ऊपर तक पहुंची शिकायतों के बाद मैडम को तो चलता कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले ही जिले की कप्तानी संभालने वाले साहब भी पहले वाली कप्तान के रंग-ढंग में आ चुके हैं। हालांकि साहब ने अपने कमाई के लिए छापेमारी को सहारा बनाया है। सूत्र बताते हैं कि पहले तो साहब छापा डलवाकर अवैध रूप से शराब बेचने वालों को पकड़वाते हैं फिर शुरू होता है लेनदेन का कारोबार। बताया जाता है कि रकम देने के बाद उक्त कालाबाजारी को फ्रीहैंड कर दिया जाता है। बताया जाता है कि काले कारोबार करने वालों को उनके द्वारा जितना चढ़ावा दिया जाता है, उनको उतनी ही छूट दी जाती है। सूत्र बताते हैं कि साहब के इस फॉर्मूले का अवैध धंधा करने वाले जमकर फायदा उठा रहे हैं।

धंधेबाज मंत्रीपुत्र को किसका समर्थन ?

प्रदेश के सबसे कमाऊ विभागों में से एक तथा खजाने को संभालने वाले एक मंत्रीजी का पुत्र इन दिनों अपने एक अनैतिक धंधे के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्रीजी हाव-भाव और स्वभाव से काफी शांत और सरल हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि मंत्रीजी के इस धंधेबाज पुत्र को किसका समर्थन मिल रहा है। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी का पुत्र ड्रग्स के गोरखधंधे में लगा हुआ है। मंत्रीपुत्र होने के कारण वह अपने काले कारोबार को बेधड़क होकर अंजाम दे रहा है। आलम यह है कि मंत्रीपुत्र द्वारा किए जा रहे गलत धंधे की खबर अब शासन और प्रशासन में उच्च स्तर तक पहुंचने लगी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मंत्रीजी एक बार फिर लपेटे में न आ जाएं। गौरतलब है कि विगत दिनों राजधानी भोपाल में ड्रग्स के काले कारोबार पर जब गुजरात की एजेंसियों ने छापा मारा था तो उसका सरगना मंत्रीजी का करीबी निकला था। हालांकि मंत्रीजी इस बात से इंकार करते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर उक्त सरगना के साथ मंत्रीजी की तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी के करीबी कुछ अफसरों की शह पर उनका पुत्र ड्रग्स का अवैध कारोबार कर रहा है।

तिवारी जी जो कहें वही सही...

प्रदेश में काली कमाई के लिए कुख्यात कमाऊ विभाग पर सरकार ने कागजी तौर पर नकेल कस दी है। यानि सरकार की नजर में वाहनों से होने वाली अवैध वसूली रुक गई है। लेकिन गोरखधंधा अब भी बेरोकटोक चल रहा है। बताया जाता है कि इसके लिए पर्दे के पीछे ताना-बाना बुना गया है और इसके कर्ताधर्ता हैं तिवारी जी, जो विभागीय मंत्री के पीए हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी के पीए ने वाहनों से अवैध वसूली के लिए कटर तैनात कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि तिवारी जी ने बकायदा इसके लिए कटर की भर्ती की है। प्रदेशभर में बिना नाको के हो रही अवैध वसूली को लेकर जब मोटर एसोसिएशन के लोग विभागीय अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें टका सा जवाब मिलता है कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही यह भी संकेत दे दिया जाता है कि जाकर तिवारी जी से मिलें। दरअसल, इस विभाग में तिवारी जी जो कहें वही सही माना जाता है। विभाग में चल रहे इस घपलेबाजी की खबर मंत्रीजी को है कि नहीं, यह तो वही जानें। लेकिन जानकारों का कहना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा है। बता दें कि प्रदेश में वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें दिल्ली दरबार तक पहुंचने और संबंधित मंत्रालय के मंत्री के बार-बार हस्तक्षेप के बाद प्रदेश में नाको की प्रथा को जैसे-तैसे बंद किया गया है। लेकिन वसूली अभी भी चल रही है।

सरकार नहीं, साहब की चली

प्रदेश सरकार ने बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व को एक साथ शुरू करने की योजना बनाई थी। सरकार की मंशा थी कि दोनों रिजर्व को एक साथ एक ही दिन शुरू किया जाए, ताकि दोहरी उपलब्धि एक ही खर्च पर मिल सके। लेकिन वन विभाग के बड़े साहब के आगे सरकार की योजना धरी की धरी रह गई। सूत्रों का कहना है कि जब इन दोनों योजनाओं को अमली जामा पहनाना था, उस समय साहब छुट्टी पर थे। इस दौरान उनको सरकार ने कहा कि दोनों रिजर्व को एक साथ शुरू करने की योजना पर काम करें। तो साहब ने कहा- मैं छुट्टी पर हूं और छुट्टी के दौरान कोई काम नहीं करता। साहब ने सरकार की तनिक भी नहीं सुनी, उन्होंने इस मामले में अपनी ही मनमानी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले माधव टाइगर रिजर्व को शुरू किया गया, फिर उसके कई दिन बाद रातापानी टाइगर रिजर्व को। यानि इस बहुप्रतीक्षित योजना को शुरू करने में सरकार की नहीं बल्कि साहब की ही चली। अब देखना यह है कि साहब की इस मनमानी को सरकार किस नजरिए से देखती है।

सरकार की कृपा बनी रहे...

मंत्री हों, अधिकारी हों या आम आदमी, सबकी कोशिश यही रहती है कि उन पर सरकार की कृपा बनी रहे। सरकार की कृपा पाने के लिए अफसरों का भी पूरा ध्यान इन दिनों सिंहस्थ की तैयारियों पर है। इसलिए वहां अधिक से अधिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से एक ही क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जा रही है, उससे उसी अंचल से आने वाले एक कद्दावर मंत्रीजी भी नाखुश हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के कृपापात्र पानी से जुड़े विभाग के चर्चित प्रमुख अभियंता का सारा ध्यान सिर्फ सरकार के शहर पर है। यहां बता दें कि कुछ वर्ष पहले प्रमुख अभियंता वहां अधीक्षण यंत्री थे। ऐसे में सरकार से उनकी निकटता पुरानी है। अब इस निकटता का फायदा उठाने में प्रमुख अभियंता का पूरा ध्यान लगा हुआ है। यही नहीं उन्होंने सरकार के करीबी खबरचियों को भी साध लिया है। इन खबरचियों के माध्यम से सरकार के पास अपना पॉजिटिव फीडबैक पहुंचा रहे हैं और जमकर कमाई कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए खबरचियों को भी लक्ष्मीजी से उपकृत किया जा रहा है।

अब लगेगी 10 गुना पेनाल्टी

मप्र सरकार अब जनविश्वास कानून बनाने जा रही है। इसमें उद्योग, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कानूनों की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा समय में इन धाराओं के उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना भी कोर्ट जाकर भरना पड़ता है। जनविश्वास कानून में कई धाराओं में सजा का प्रावधान हटाने की तैयारी है। जुर्माना भरने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि संबंधित विभाग के कार्यपालक अधिकारी पेनाल्टी लगा सकेंगे। इस कानून को लाने का मकसद ये भी है कि अदालतों पर केस का बोझ कम हो और आम लोगों को राहत मिले।

जानकारी के अनुसार नए कानून के मसौदे पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों के साथ चर्चा कर ली है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि जनविश्वास बिल का मुख्य उद्देश्य उद्योग और बिजनेस सिस्टम में सहजता लाना यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। व्यापार के लिए कई विभागों से लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। अब इसमें बदलाव होगा। उद्योग और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई) विभाग के एक्ट के कानूनी प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। सजा का प्रावधान हटाया जा सकता है। जुर्माने की जगह पेनाल्टी का प्रावधान किया जा सकता है।

नए नियमों के अनुसार राजधानी सहित प्रदेश के 16 शहरों (नगर निगम) में सार्वजनिक स्थान, नहर या ड्रेनेज में गंदा पानी छोड़ने पर पांच हजार रुपए पेनाल्टी चुकाना पड़ सकती है। यह मौजूदा के मुकाबले दस गुना ज्यादा है। इसी तरह अवैध नल कनेक्शन लेने पर भी 500 की जगह पांच हजार रुपए पेनाल्टी देना होगी। निगमों के साथ नगर पालिकाओं में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मप्र नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मप्र नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्र सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए राज्य के सभी विभागों को जनविश्वास बिल लाने के लिए कहा गया है। मौजूदा नियमों या एक्ट में गैर जरूरी प्रावधानों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर प्रदेश के उद्योग, सहकारिता और नगरीय विकास विभाग ने काम किया है। नगरीय विकास विभाग के दोनों एक्ट में संशोधन कर अर्थदंड या फाइन के स्थान पर शास्ति या पेनाल्टी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।

बिल को लेकर कुछ समय पहले उच्च स्तर पर बैठक हुई थी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नगर निगम और नगरपालिका से जुड़े एक्ट पर चर्चा के दौरान कहा गया कि इनमें पेनाल्टी की राशि कई साल पहले तय की गई थी। काफी समय से कोई वृद्धि भी नहीं की गई। इसके मद्देनजर विभाग के अफसरों को पेनाल्टी की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर अमल करते हुए नियम तोड़ने पर दस गुना या उससे अधिक जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव बन चुका है। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने की वजह से आयात पर पथकर या उपकर भुगतान वसूली से जुड़ी धाराओं को विलोपित कर दिया है। संशोधनों का प्रारूप बनाकर औद्योगिक निवेश विभाग को भेज दिया है।

राजधानी सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों में कमिश्नर की अनुमति के बिना नल कनेक्शन लेने, मेन रोड पर ड्रेनेज को जोड़ने पर 500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपए पेनाल्टी देनी होगी। बिना परमिशन ड्रेन का निर्माण या उसमें बदलाव करने पर 500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपए की पेनाल्टी के साथ फिर से निर्माण की क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। कारखानों या कहीं और वाष्प सिटी का उपयोग होने पर 500 की जगह 5000 रुपए पेनाल्टी लगेगी। दिशा सूचक बोर्ड को तोड़ने पर 500 के स्थान पर 5000 रुपए शास्ति की जाएगी। वहीं नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रास्ता रोकना, अन्य उपयोग करने पर 500 के स्थान पर 5000 की पेनाल्टी लगेगी। नए भवनों की सूचना, एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार किया गया है। बिल्डिंग की छत या बाहरी दीवारों का ज्वलनशील सामग्री से न बनाया जाना, पेनाल्टी 25 रुपए की जगह 500 रुपए, भवनों को विरूपित करने पर 25 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए, नालियों पर अतिक्रमण करने पर दस गुना अधिक यानि 250 रुपए, बिना अनुमति रास्ते पर गड्ढा करना या सामग्री इकट्ठा करना, जुर्माना 25 के स्थान पर 250 रुपए गंदगी न हटाने पर 500 रुपए, अभी 50 रुपए और एक्ट पर अमल का विरोध करने पर पांच सौ रुपए की पेनाल्टी लगेगी।

जो कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए नए बिल में प्रावधान किए जा रहे हैं। सीपीपी से उत्पादित होने वाली बिजली का इस्तेमाल प्लांट का मालिक या उत्पादक ही करता है। मौजूदा प्रावधान ये है कि सीपीपी का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन न करने पर 2 हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जिसे कोर्ट में भरना पड़ता है। नए प्रावधान में 5 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसी तरह श्रम सहित राजस्व से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा के प्रावधान को पेनाल्टी में बदला जा रहा है। नगरीय विकास विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर केके श्रीवास्तव कहते हैं कि इस नए कानून से दो फायदे नजर आ रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि जनता का विश्वास सरकारी सिस्टम के प्रति बढ़ सके। अभी कई कानून में जेल और अर्थदंड का प्रावधान है।

● **प्रवीण सक्सेना**

केंद्र सरकार 2023 में लागू कर चुकी जनविश्वास कानून

संसद में जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2022 पारित हो चुका है। इसमें 19 मंत्रालयों से संबंधित 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में बदलाव किया है। जनविश्वास विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने इस प्रक्रिया को अन्य अधिनियमों तक विस्तारित करने की सिफारिश की है। केंद्र के इस कानून में मामूली तकनीकी और प्रक्रियागत गलतियों के लिए दीवानी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिससे आपराधिक दंड का भय कम होगा और देश में व्यापार करने और रहने में आसानी होगी।

बे-काम हुए नामधारी नेता

कभी मप्र कांग्रेस की राजनीति में कद्दावर राजनीतिज्ञों में शुमार रहे नेताओं ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भाजपा का दामन थामा, तो उन्हें उम्मीद थी कि भगवा दल में उन्हें बड़ा पद मिलेगा, जिससे उनका कद और बढ़ेगा। लेकिन विडंबना यह है कि करीब एक साल बाद भी ये नामधारी नेता बे-काम भटक रहे हैं। इन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अलावा पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, दीपक सक्सेना, विधायक कमलेश शाह, संजय शुक्ला, शशांक भार्गव, इमरती देवी, रघुराज कंसाना, गिर्राज दंडोतिया, रणवीर जाटव, जसवंत जाटव, मुन्ना लाल गोयल, प्रदीप जायसवाल, राहुल लोधी, जबलपुर मेयर जगतप्रकाश अन्नू, शशांक शेखर सिंह, विदिशा जिलाध्यक्ष राकेश कटारे, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, दिनेश अहिरवार, कमलापत आर्य सहित तमाम नामचीन नेता शामिल हैं। आज इन नेताओं में सुरेश पचौरी कभी-कभार नजर आ जाते हैं, लेकिन बाकी लापता हैं।

मप्र की नई सरकार में भले ही कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री पद मिल गया हो, लेकिन अब उनकी ज्यादा दाल नहीं गलने वाली है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते अब वे पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं। ऐसे में पार्टी नए सिरे से विचार-विमर्श कर रही है। पार्टी संगठन ने सरकार से साफ कह दिया है कि अब सिर्फ मूल भाजपा कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाना चाहिए। दरअसल, मप्र में निगम और मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस से आए दूसरे नेताओं से भाजपा दूरी बनाती दिख रही है। गौरतलब है कि पिछली सरकार में सिंधिया समर्थकों को निगम और मंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और मंत्री दर्जा देकर बड़ी संख्या में कुर्सी पर बैठाया गया था, लेकिन नई सरकार में अभी अधिकांश हाशिए पर हैं। भाजपा को लग रहा है कि पिछली सरकार में बाहर से आए लोगों को कुर्सियों पर बैठाने से भाजपा के मूल कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले कई जिलों में टिकट वितरण व अन्य कारणों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी थी। इससे निपटने के लिए पार्टी ने कई बड़े नेताओं को जिलों में भेजकर जैसे-तैसे कार्यकर्ताओं को मनाया था।

बता दें कि वर्ष 2020 में तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ भाजपा में आ गए थे। त्यागपत्र देने के कारण सभी सीटों पर उपचुनाव हुए, भाजपा ने उन सभी कांग्रेसी विधायकों को टिकट दे दिया। इनमें से जो जीते, वे सभी मंत्री पद पर बरकरार रहे, जबकि जो हार गए थे, उन्हें निगम और मंडल में अध्यक्ष बनाकर मंत्री दर्जा दे दिया गया था। तब इमरती देवी, रघुराज कंसाना, गिर्राज दंडोतिया, रणवीर जाटव, जसवंत जाटव, मुन्ना लाल गोयल को फ्री में सत्ता का सुख मिल गया था। वहीं, कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए प्रदीप जायसवाल, प्रद्युम्न सिंह लोधी और राहुल लोधी को भी महत्वपूर्ण निगम में अध्यक्ष बनाया गया था। इन नियुक्तियों के कारण भाजपा कार्यकर्ता दरकिनार हो गए थे और पार्टी को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। प्रदेश की राजनीति में बीते कुछ सालों में दल-बदल का खेल जोरों पर चला है और बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, वे सत्ता में हिस्सेदारी की आस लगाए हैं, मगर उनकी आस अब तक अधूरी है। गौरतलब है कि जब राज्य में सबसे बड़ा दल बदल वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में वर्ष 2020 में हुआ था, जब 22 विधायकों ने एक साथ पाला बदला था और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उसके बाद तो कांग्रेस के कई नेताओं ने पाला बदला। सिंधिया के साथ जिन नेताओं ने दल बदल किया, उनमें से कई नेता तो सत्ता में हिस्सेदार बने हुए हैं, तो वहीं अन्य अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दल बदल किया। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के अलावा कमलनाथ के करीबियों में गिने जाने वाले दीपक सक्सेना और अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह प्रमुख हैं। वहीं कई पूर्व विधायक भी भाजपा में शामिल हुए हैं। यह ऐसे नेता हैं, जो भाजपा में आने के बाद बड़ी जिम्मेदारी हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

ज्ञात हो कि राज्य में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार को 12 माह का वक्त बीत गया है। इस दौरान कुछ मंडल और निगमों में ही नियुक्तियां हुई हैं। पार्टी की कोर कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आगामी समय में निगम और मंडल में नियुक्तियां होने वाली हैं, इनमें पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दिए जाने के साथ दल बदल करने वालों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके लिए सत्ता और संगठन में मंथन का दौर जारी है। आने वाले दिनों में फैसला होने की भी संभावना है।

● **अरविंद नारद**

मोहन कैबिनेट में कांग्रेस से आए नेताओं का अच्छा प्रभाव

कांग्रेस से आए नेताओं का डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट में भी दबदबा है। इनमें इंदौर से तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं। सागर जिले से गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। मुरैना से एदल सिंह कंषाना कृषि मंत्री है। कंषाना को छोड़कर बाकी सभी तत्कालीन शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे हैं। इनके अलावा छह बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। इसके बाद वे उपचुनाव हार गए और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। वहीं, उदय प्रताप सिंह भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। अब वे मोहन कैबिनेट में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। कैबिनेट में अभी 4 पद खाली हैं।

बड़ी-बड़ी बैठकें... निर्णय अधर में

मप्र में जबसे अनुराग जैन ने प्रशासनिक मुखिया की कमान संभाली है, व्यवस्था में अनुशासन दिखने लगा है। मुख्य सचिव स्वयं तो सक्रिय रहते ही हैं, अफसरों को भी सक्रिय रखते हैं। इसके लिए अफसरों के साथ लंबी-लंबी बैठकें हो रही हैं। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो मुख्य सचिव अफसरों के साथ बड़ी-बड़ी बैठकें तो कर रहे हैं, इन बैठकों में लंबे समय तक चर्चा भी होती रहती है। लेकिन अभी तक कोई बड़े निर्णय नहीं लिए गए हैं। मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि अभी मुख्य सचिव अधिकारियों की कार्यप्रणाली समझने में लगे हुए हैं। हालांकि अपने अभी तक के छोटे कार्यकाल में उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना की केंद्र से अनुमति दिलवाई है, वहीं कई और मामलों पर तत्परता से काम कर रहे हैं।

मंडलोई पर जताया भरोसा

प्रदेश में विगत दिवस बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसमें कई सीनियर अफसर भी हैं। इन तबादलों के बाद सबसे अधिक चर्चा पीडब्ल्यूडी विभाग की हो रही है। इस विभाग के मुखिया केसी गुप्ता को हटाकर राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया। यह 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव की सरकार बनने के बाद पीडब्ल्यूडी का तीसरा बदलाव है। दरअसल, नई सरकार में पहले सुखवीर सिंह, डीपी आहूजा और अब केसी गुप्ता, तीनों को कुछ ही महीनों में इस पद से हटाया गया। अब सरकार ने ऊर्जा विभाग के एसीएस नीरज मंडलोई पर विश्वास जताया है और उनको पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 13 दिसंबर 2023 को मोहन सरकार बनने के बाद से पीडब्ल्यूडी विभाग में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले सुखवीर सिंह पीडब्ल्यूडी के प्रमुख थे। उन्हें सरकार बनने के केवल 48 दिन बाद ही हटा दिया गया। उनके बाद डीपी आहूजा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। आहूजा 186 दिन, यानी लगभग छह महीने इस पद पर रहे। अब केसी गुप्ता के तबादले के बाद पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त प्रभार एसीएस ऊर्जा नीरज मंडलोई को दिया गया है। लगातार बदलते मुखिया से पीडब्ल्यूडी विभाग में स्थिरता का अभाव दिखाई देता है। यह देखना होगा कि नीरज मंडलोई कब तक इस पद पर बने रहते हैं।

चार अधिकारी बनेंगे आईपीएस

प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड देने के लिए 16 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में रापुसे के 12 अधिकारियों के नाम पर विचार-विमर्श के बाद चार अधिकारियों को आईपीएस के लिए प्रमोट किया जाएगा। बता दें कि इन पदों के लिए पहले इसी वर्ष मार्च में डीपीसी कराने की तैयारी थी, पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसे टाल दिया गया था। इस बार राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों की आईपीएस के रूप में पदोन्नति के लिए 16 दिसंबर को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय में बैठक होगी। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारी आईपीएस में पदोन्नत होंगे। वरिष्ठता के अनुसार जिनके नाम भेजे गए हैं, उनमें 1995 बैच के प्रकाश चंद्र परिहार, 1997 बैच के दिलीप कुमार सोनी, सीताराम सत्या, अवधेश प्रताप सिंह बागरी, राजेंद्र कुमार वर्मा, अमृत मीणा और विक्रांत मुराब। 1998 बैच के सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे, राजेश रघुवंशी, निमिषा पांडेय और राजेश कुमार मिश्रा का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को आईएएस अवार्ड करने के लिए डीपीसी होने वाली है। इसमें 2007 और 2008 बैच के अधिकारियों को शामिल किया गया है। प्रदेश में विशेष पुलिस महानिदेशक (एसडीजीपी) के 12 में से दो पद कम हो सकते हैं। इसकी वजह यह कि केंद्र ने अस्थायी तौर पर विशेष डीजी के दो पद दिए थे। दिसंबर 2024 में यह अवधि पूरी हो रही है। शासन ने केंद्र को इन पदों को यथावत रखने प्रस्ताव भेजा है, पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। बता दें कि प्रदेश में डीजीपी सहित डीजी के काडर पद पांच हैं। इतने ही यानी पांच नान काडर पद सरकार बना सकती है। इस तरह 10 से अधिक पद नहीं हो सकते। केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार ने लगभग पांच वर्ष पहले 10 की जगह 12 पद कर लिए थे।

नए साल में प्रमोशन-तबादले

नए साल यानि जनवरी 2025 में बड़े स्तर पर तबादले होंगे। इसके लिए अभी से कागजी खाका तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी तबादलों पर बैन है। प्रदेश में तबादलों पर बैन की एक वजह यह भी है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन के मद्देनजर मैदानी अफसरों के तबादले पर रोक लगा रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जनवरी में तबादलों पर से बैन हटाया जा सकता है। उसी दौरान पुलिस विभाग में आईपीएस अफसरों का प्रमोशन भी होना है। ऐसे में प्रमोशन के साथ ही उनके तबादले किए जाएंगे। नए साल में जिन आईपीएस अफसरों के प्रमोशन होंगे, उनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद के आईपीएस अधिकारी स्पेशल डीजी बनेंगे। इसमें 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी स्पेशल डीजी बनाए जाएंगे। जिन अधिकारियों को स्पेशल डीजी बनाया जाएगा, उनमें पंकज कुमार श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, पवन कुमार श्रीवास्तव, मनीष शंकर शर्मा, जी अखेतो सेमा, डीसी सागर आदि का नाम शामिल है। इसी तरह 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजी बन जाएंगे। इसमें संतोष सिंह और एसपी सिंह का नाम शामिल है। वहीं 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी डीआईजी से आईजी बनेंगे। इनमें सचिन कुमार अतुलकर, रूचिका जैन, कुमार सौरभ, कृष्णा वेनी देसावतु आदि शामिल हैं। इसी तरह 2010-11 बैच के आईपीएस अधिकारी डीआईजी हो जाएंगे। इन अधिकारियों की पदस्थापना के साथ ही पीएचक्यू में भी सर्जरी होगी।

प्रोफेशनल पुलिसिंग पर जोर...

पुलिस महानिदेशक का पद संभालते ही कैलाश मकवाना ने अपना टारगेट सेट कर दिया है। पदभार संभालने के अगले दिन ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा है कि हमें प्रोफेशनल पुलिसिंग की ओर बढ़ना है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म सर्विस अनिवार्य रूप से कायम रखना है। हमारे लिए रूल-ऑफ-लॉ अर्थात् कानून सर्वोपरि है, इसको ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्य करना है। बैठक में डीजीपी ने कहा कि हमें प्रोफेशनल पुलिसिंग की ओर बढ़ना है। हमारा आचरण निष्ठा और ईमानदारी युक्त हो और किसी भी तरह की नशाखोरी, भ्रष्टाचार से दूर रहें। डीजीपी ने कहा कि सिंहस्थ-2028 मेगा इवेंट है। इसकी तैयारी में और गतिशीलता लाने की जरूरत है। उज्जैन के सराउंडिंग जिलों में भी पर्याप्त व्यवस्था करना है। समय पर प्लान बनाकर शासन को भेजना है, ताकि सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हो सकें। अफसरों ने डीजीपी के दिशा-निर्देशों का पालन करने की हामी भर दी है। बताया जाता है कि इस दौरान मैदानी अफसरों से भी अपनी बात खुलकर कहने को बोला गया। कुछ अफसरों ने अपनी बात भी रखी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि पहले से ही यह होते आया है कि जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षकों को सुनने की बजाय उन्हें अपना टारगेट थमाया जाता है।

डीजीपी की प्राथमिकताएं

डीजीपी ने निर्देशित किया कि साइबर क्राइम, अवैध नशे के कारोबार और यातायात सुरक्षा पर तत्काल प्रभावशाली कार्य करें। हमारा कर्तव्य है कि हम युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से रोकें। इसलिए सभी स्कूल, कॉलेज में पुलिस अधिकारी पहुंचें और व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। इसके लिए मीडिया के सभी माध्यम, शॉर्ट वीडियो, पंपलेट, संगोष्ठी आदि का प्रयोग करें। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का समाज में प्रभाव दृष्टिगोचर होना चाहिए। गुप्त सूचना तंत्र को मजबूत करें और अवैध नशे के कारोबार के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर नेस्तनाबूद करें। पुलिस का कर्त्तव्य है कि आमजन को सुरक्षित और सुगम यातायात सुलभ कराएं। हेलमेट पहनने को लेकर व्यापक जनजागरूकता निर्मित करें। आमजन से संवेदनशील सद्व्यवहार और बदमाशों पर सख्ती रखें।

अफसरों को नहीं भा रहा महामहिम का घर

किसी भी प्रदेश में महामहिम यानि राज्यपाल का दर्जा सबसे ऊपर होता है। महामहिम का रुतबा देखकर हर कोई उनका सानिध्य पाने की कोशिश करता है। लेकिन मप्र में देखा जा रहा है कि यहां के अफसरों को महामहिम का घर तनिक भी नहीं भा रहा है। सरकार जिस अफसर को राजभवन में पदस्थ करती है, वह वहां से विदाई की कोशिश में लग जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि कोई भी अधिकारी राजभवन में काम करना नहीं चाहता है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी डीपी आहूजा को प्रमुख सचिव के पद पर वहां पदस्थ किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ दिन में ही वहां से तबादला करवा लिया। उनके बाद 1994 बैच के संजय शुक्ला को प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ किया गया, लेकिन वे भी वहां टिक नहीं पाए। उसके बाद 1998 बैच के मुकेश गुप्ता को वहां पदस्थ किया गया, लेकिन वे भी वहां टिक नहीं पाए और वहां से झगड़ा करके आए और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग में सेवाएं दे रहे हैं।

धारा-16 के 53 आवेदन

मप्र में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के बड़े शहरों के मास्टर प्लान अधर में लटके हुए हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद दावा किया गया था कि मार्च 2024 में शहरों के मास्टर प्लान लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक मास्टर प्लान अधर में लटके हुए हैं। उधर, बिना मास्टर प्लान लागू हुए ही धारा-16 के तहत जमीनों को कब्जाने की कारस्तानी शुरू हो गई है। इसके लिए अभी तक 53 आवेदन आ चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके यह खेल खेला जा रहा है, ताकि दांव लगते ही अनुमतियां दे दी जाएंगी। वहीं भोपाल का मास्टर प्लान जो अब तक वर्ष 2031 के हिसाब से तैयार होना था, अब वर्ष 2047 के हिसाब से बनेगा। वहीं इंदौर का मास्टर प्लान वर्ष 2041 तक के हिसाब से आएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव की सहमति के बाद इसका प्रकाशन होगा। प्लान एरिया में अब तक दोनों शहरों में दस प्रतिशत ग्रीन एरिया का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 से 17 प्रतिशत तक करने पर किया जाएगा। मालूम हो कि भोपाल में पहले जो 2031 तक का प्लान बना था, उसमें तालाब का कैचमेंट एरिया आने से विरोध शुरू हो गया था, उसके बाद ये बदलाव किया गया है। भोपाल में मास्टर प्लान 2031 में जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी उनमें 32 पंचायतों को शामिल करने, बड़े तालाब का कैचमेंट क्षेत्र बिना किस मुआवजे एवं नोटिफिकेशन के 2800 हेक्टेयर से 3872 हेक्टेयर करने पर तालाब के नजदीक के गांवों के किसान लगातार आपत्ति ले रहे हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दोनों शहरों के लिए प्लान है कि पुराने शहरों में हाईराइज भवन नहीं बनाए जा सकेंगे। इसके बदले में वहां के भवन स्वामियों को हेरिटेज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट टीडीआर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे वे बेच सकेंगे। जिन किसानों की जमीन ग्रीन कॉरिडोर में आएगी, उसे ग्रीन टीडीआर दिया जाएगा। वहीं बड़े तालाब को बचाने के लिए भी मास्टर प्लान में बिंदु शामिल किए गए हैं। यह एरिया ग्रीन टीडीआर में शामिल होगा लेकिन भूमि स्वामी को हरियाली दिखानी होगी। हर निकाय का अब अपना एक स्टेंडर्ड डेवलपमेंट फंड होगा। कॉलोनाइजरों को दी जाने वाली सुविधा फीस को इस फंड में रखा जाएगा। निकाय कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

● राजेंद्र आगाल

केंद्र में अटका योजनाओं का पैसा

मप्र में पेयजल के लिए चल रही जल जीवन मिशन, रोजगार गारंटी सहित कई विकास योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार में अटक गए हैं। केंद्र से अनुदान प्राप्त योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के चलते यह राशि मप्र को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि कई विभागों ने केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृत राशि का उपयोग होने का प्रमाण-पत्र तय समय पर नहीं भेजा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बार-बार निर्देश के बावजूद विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को नहीं भेजा जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि केंद्रीय योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं।

गौरतलब है कि केंद्र और राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित राशि का बड़ा हिस्सा अब तब मप्र को नहीं मिला है। वर्ष 2024-25 में 37 हजार 652 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं में मिलना है, लेकिन नवंबर अंत तक 16,194 करोड़ रुपए ही मिले हैं। कई योजनाओं में तो बिल्कुल भी राशि नहीं दी गई। जल जीवन मिशन में 4,571 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसमें से 2,400 करोड़ मिले। छात्रवृत्ति भी राशि न मिलने के कारण अटकी हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करके योजनाओं को स्वीकृति दिलाने के साथ राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी मंत्रियों और अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे भी केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों से संपर्क में रहें। यही बात मुख्य सचिव अनुराग जैन भी वरिष्ठ अधिकारियों से कह चुके हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में सभी विभागों को 37,652 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है। फरवरी में 2025-26 का आम बजट संसद में प्रस्तुत होगा और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हो जाएगा। इस अवधि के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक राशि समय पर उपलब्ध न होने के कारण काम प्रभावित हो रहे हैं। जिन योजनाओं की राशि प्रदेश को नहीं मिली है, उसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी शामिल है। इसमें 2,625 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसके विरूद्ध 25 नवंबर तक 841 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। इसी तरह छात्रवृत्ति की राशि भी अटकी हुई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के 375 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसमें से 250 करोड़ रुपए ही अब तक मिले हैं। इसी तरह केंद्रीय सड़क निधि में 1,150 करोड़ रुपए में से 23.13, समग्र शिक्षा अभियान में 3,060 करोड़ रुपए में से 1,823 करोड़, पीएमश्री में 135 करोड़ रुपए में से 39.81 करोड़, न्यायालय भवनों के निर्माण में 180 करोड़ रुपए में 36 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 159 करोड़ रुपए में 105 करोड़, आयुष्मान भारत में 588 करोड़ रुपए में से 106 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं।

वित्त विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 में 37 हजार 652 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं में मिलना है, लेकिन नवंबर अंत तक 16,194 करोड़ रुपए ही मिले हैं। कई योजनाओं में तो बिल्कुल भी राशि नहीं दी गई। जल जीवन मिशन में 4,571 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसमें से 2,400 करोड़ मिले। कुछ राशि विभागों को सीधी दी गई तो कुछ बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। हितग्राहीमूलक योजनाओं की राशि सीधे खातों में जमा कराई गई। इसके बाद भी केंद्रांश कई योजना में प्राप्त नहीं हुआ। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी घर-घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन राशि की कमी का सामना कर रहा है। इसमें वर्ष 2024-25 में 4,571 करोड़ रुपए मिलने थे लेकिन दो बार में 2,400 करोड़ रुपए ही मिले। इसका ब्यौरा भी वित्त विभाग के पोर्टल पर नहीं है।

● **लोकेश शर्मा**

मप्र को नहीं मिल रही केंद्र से योजना की राशि

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य में निजी निवेश आने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि निजी निवेश आना दूर की बात है, राज्य को तो केंद्र की योजनाओं का पैसा ही प्राप्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आए दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के वादों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निजी क्षेत्र से आने वाला यह निवेश तो दूर, केंद्र सरकार से प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए आने वाले पैसे को ही अब तक राज्य सरकार प्राप्त नहीं कर सकी है। कमलनाथ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मप्र को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 37,652 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 16,194 करोड़ रुपए ही मिले हैं। कांग्रेस नेता का दावा है कि जिन महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिली है उनमें आयुष्मान योजना, आदिवासी समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि, पीएमश्री स्कूल और अदालत के भवन निर्माण की राशि भी अटकी हुई है। कमलनाथ ने कहा कि यह सारी रकम मप्र की जनता का अधिकार है और केंद्र यह पैसा देकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। प्रदेश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई से केंद्र सरकार को जो टैक्स देती है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा केंद्रीय मदद के रूप में प्रदेश को वापस मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार पर मप्र को उसका अधिकार देने के लिए दबाव बनाएं।

मंत्रियों की कमेटी तय करेगी आबकारी नीति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण और आवश्यक नीतिगत निर्णयों के लिए एक मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया। इस समिति में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया के साथ ही इस बार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया। यह समिति आबकारी नीति को फाइनल करेगी। गौरतलब है कि मप्र में आबकारी विभाग के अधिकारी नहीं आबकारी नीति का खाका तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर शराब दुकानों के बंद अहाते चालू करने की तैयारी की जा रही है। नई शराब नीति को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है उसे कैबिनेट में रखने के बाद हरी झंडी मिली तो 2025-26 में शराब की दुकानें 10 फीसदी ज्यादा में नीलाम होंगी। प्रदेशभर में शराब दुकान के अहाते बंद होने से राजस्व का भारी नुकसान सरकार को हो रहा है।

नई शराब नीति को लेकर अफसरों ने आय बढ़ाने के जो सुझाव दिए हैं उसमें बताया गया है कि अगले साल शराब दुकानों की नीलामी 10 फीसदी ज्यादा में की जाए। इसके लिए उप्र समेत तीन राज्यों की शराब नीति का अध्ययन मप्र शासन के आबकारी विभाग ने कर मसौदा तैयार किया है। दिसंबर में होने वाली बैठक में शराब नीति का प्रस्ताव रखा जाएगा, हरी झंडी मिलने के बाद नई शराब नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि यदि अहाते चालू होंगे तो शराब दुकान के सामने सड़क पर लगने वाली भीड़ कम होगी जिससे आने-जाने वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने अहाते बंद करा दिए थे। जानकारी के अनुसार उप्र समेत तीन राज्यों की शराब नीति का अध्ययन कर मप्र शासन के आबकारी विभाग ने नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया है। पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शराब नीति को फाइनल करने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई है। यह समिति नई आबकारी नीति तय करेगी। बताया जाता है कि प्रस्ताव में अहाते बंद होने से शराब दुकानों के आसपास सड़कों पर भीड़ बढ़ने से होने वाली परेशानी और राजस्व के नुकसान का जिक्र किया गया है। अहाते फिर से शुरू करने या न करने का फैसला सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। पिछले साल फरवरी में तत्कालीन शिवराज सरकार ने अहाते बंद करने का निर्णय लिया था। करीब 2600 अहाते बंद किए गए थे।

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शराब नीति का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीम ने उप्र के शराब मॉडल का अध्ययन किया। इसमें सामने आया कि उप्र में लॉटरी सिस्टम से शराब दुकानों का आवंटन होता है। वहां शराब दुकानों की संख्या करीब 30,0177 है, जो मप्र के मुकाबले नौ गुना ज्यादा है। नई शराब नीति में उप्र की शराब नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। मप्र में शराब दुकानों की कुल संख्या 3605 है। मप्र में ई-टेंडर के जरिए शराब दुकानें नीलाम होती हैं। देश में कर्नाटक के बाद मप्र में शराब की कीमत सबसे ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार शराब के उप्र के शराब नीति के मॉडल को अपनाती है, तो मप्र में शराब दुकानों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाएगी। जबकि मप्र सरकार की नीति शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं करने की रही है। प्रस्ताव में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की शराब नीति के चुनिंदा बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में शराब के विक्रेता स्थाई हैं। वहां हर साल शराब दुकानों की बिक्री की एक निश्चित राशि बढ़ा दी जाती है। तमिलनाडु में शराब दुकानों का संचालन सरकार स्वयं करती है।

● **कुमार विनोद**

सरकार की कमाई का बड़ा स्रोत शराब

राज्य सरकार के आबकारी विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मप्र में इस साल आबकारी राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। राज्य की 3600 कंपोजिट शराब दुकानों के लिए 931 समूह बनाकर ठेके दिए गए थे। इससे शासन को 13,914 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। ये पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 12,353 करोड़ रुपए से 12.63 फीसदी ज्यादा है। इस तरह इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1561 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व मिलेगा। मप्र सरकार को कोरोना काल में राजस्व पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। शराब ठेकेदारों ने लॉकडाउन में दुकानें बंद होने से ठेके नहीं उठाए थे। इसके चलते शराब की दुकानों पर साल 2023-24 में केवल 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि साल 2022-23 में 11.5 प्रतिशत एवं साल 2021-22 में 9.06 प्रतिशत रही। इस बार साल 2024-25 की प्राप्त 12.6 प्रतिशत की वृद्धि पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। मप्र में सरकार के सबसे कमाऊ विभागों में से एक आबकारी विभाग के अधिकारी नई शराब नीति को बनाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि नई शराब नीति में प्रदेश में अहाते फिर से खोलने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अहाते खुलेंगे कि नहीं यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ही तय करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार ने 2023 में अहातों को बंद कर दिया था। उसके बाद से अहाते बंद हैं। ऐसे में लोग दुकानों से शराब खरीदकर सुनसान स्थानों पर बैठकर पीते हैं। जानकारों का कहना है कि इससे आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में नई शराब नीति में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि अहातों को फिर से चालू किया जाएगा। आबकारी विभाग ने प्रस्ताव में नर्मदा किनारे 5 किमी की परिधि में शराब दुकानें नहीं खोले जाने की बंदिश पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया है। नई नीति में शराब दुकानों की नीलामी 10 प्रतिशत बढ़ी हुई दरों पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व की तरह कुल दुकानों का 75 प्रतिशत शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर फिर से शराब दुकान आवंटित की जाएगी, नहीं तो शराब दुकान के लिए नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे। प्रस्ताव में धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से शराब दुकानों की दूरी पूर्व की तरह 100 मीटर निर्धारित रखी गई है।

फ्लाई ऐश के जहर से बढ़ा संकट

उड़न राख यानी फ्लाई ऐश। ऐसी जहरीली राख जो कोयले को जलाने पर मिलती है और हवा के संपर्क में आने पर उड़ सकती है। यह पर्यावरण के लिए खतरा बन गई है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने वाली फ्लाई ऐश को खत्म करने के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। राखड़ का स्टॉक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। यह राख नदी-नालों के जरिए तालाबों और हवा के जरिए इंसानों के लिए खतरा बन रही है। केंद्र सरकार 1999 से फ्लाई ऐश को लेकर चेता रही है। 2003, 2007, 2009, 2016 में केंद्र ने इसे राष्ट्रीय समस्या माना और स्टॉक खत्म करने की रूपरेखा बताई, लेकिन मप्र में इसका ठीक से पालन नहीं किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जुलाई 2011 में फ्लाई ऐश के स्टॉक को खत्म करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई। पर्यावरण विभाग के पीएस को अध्यक्ष, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, खनिज व आयुक्त गृह निर्माण को सदस्य और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को संयोजक बनाया गया। समिति ने गिने-चुने मौकों पर खानापूर्ति करने वाली बैठकें जरूर कीं।

गौरतलब है कि मप्र के 15 थर्मल पावर प्लाट सालाना औसतन 2.85 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश उग रहे हैं। सरकारी दावा है कि इसमें से 62 फीसदी का उपयोग किया जा रहा है। यानी 38 फीसदी फ्लाई ऐश अभी भी जल, जंगल और जमीन को जकड़ रही है। फ्लाई ऐश की वजह से सिंगरौली बांध फूटने की सबसे बड़ी घटना सामने आ चुकी है। सारणी जैसे कई बांध राख से गले तक भर गए हैं। नदी-नालों में फ्लाई ऐश जमा होने के कारण इनकी जल संग्रहण क्षमता कम होती जा रही है। हवा के साथ उड़ने और पानी के साथ बहने वाली राख जमीन को बंजर बना रही है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को तो गिना ही नहीं जा रहा। यह सबकुछ होने के बावजूद जिम्मेदार कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं।

थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाकर बिजली बनाने से राख निकलती है। यही फ्लाई ऐश है। मप्र समेत देश के पावर प्लांट बिजली की 70-75 प्रतिशत जरूरत पूरी करते हैं। जम्मू-कश्मीर को छोड़ दें तो सभी राज्यों में ये प्लांट है। वैश्विक स्तर पर बिजली पैदा करने के इस पैटर्न को सोलर समेत अन्य माध्यमों से बदलने की जरूरत है। ऐसा करके कई समस्याओं से निपटा जा सकता है। प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के 15 थर्मल पावर प्लांट हैं। बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 22,730 मेगावाट है। सालाना 2 करोड़ 85 लाख 17 हजार 588 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश निकलती है। इनमें से सारणी, अनूपपुर, नरसिंहपुर में ही फ्लाई ऐश का 80 से 95 प्रतिशत उपयोग हो रहा है, बाकी के प्लांटों में ढेर लगा है। सिंगरौली का महान और नरसिंहपुर के गाडरवारा का आधा भी उपयोग नहीं करवा पा रहे। सारणी में 11 एमबी पावर लिमिटेड अनूपपुर में 100 प्रतिशत, निवारी गाडरवारा का बीएलए पावर प्लांट 100 प्रतिशत नई ऐश के उपयोग का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी फ्लाई ऐश के उपयोग में कमी नहीं आ रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार एक मेगावाट बिजली उत्पादन में 1800 से 2000 टन फ्लाई ऐश प्रतिदिन निकलती है। इसमें 18-20 प्रतिशत बालू जैसी मोटी राख और 80 प्रतिशत हवा में फैलने योग्य फ्लाई ऐश रहती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास के बांध, नदी, नाली में सिल्ट जमा हो गई है। जल, जंगल, जमीन को खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार कोई अध्ययन नहीं करवा रही है। फ्लाई ऐश के उपयोग को लेकर कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हकीकत में स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है। एनजीटी में याचिका भी लगाई गई है।

बात 2020 की है। रिलायंस सासन पावर फ्लाई ऐश डैम फूटने से जल, जंगल, जमीन और जानमाल की भारी तबाही हुई थी। इसके बाद भी सासन पावर के लापरवाह अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। जिले के हर्रहवा से लेकर रिहंद नदी तक फैली हजारों टन राख और इसके नीचे मकान दब गए थे। इसी राख के ढेर के नीचे से पांच शव बरामद किए गए थे। अनूपपुर जिले में फ्लाई ऐश परिवहन का कार्य जैतहरी स्थित मोजरवेयर पावर प्लांट एवं चचाई स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह से किया जा रहा है। वर्तमान में ग्राम हरद के पास जमुना कोतमा क्षेत्र के एसईसीएल के बंद ओपन कास्ट कोयला खदान के गड्ढ़े में राख डम्प की जा रही है।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

नदी, नाले और तालाब होते जा रहे जहरीले

फ्लाई ऐश से उत्पन्न खतरों से चिंतित केंद्र सरकार एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली और फ्लाई ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को करीब तीन साल पहले ही लॉन्च कर चुकी है। दरअसल, फ्लाई ऐश की बढ़ती मात्रा भूमि उपयोग, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे के रूप में सामने आ रही है। फ्लाई ऐश में मौजूद घटक पानी को विषैला बना देते हैं। इसमें भारी धातु, सिलिका, एल्यूमीनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड, आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा, पॉर्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 और ब्लैक कार्बन होते हैं, जो हवा के साथ उड़ते हुए 20 किमी तक फैल जाते हैं। नदी, नाले और तालाबों का पानी भी इससे जहरीला हो रहा है। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट है। मप्र में सरकारी संस्थाओं की मानें तो फ्लाई ऐश के 100 फीसदी प्रबंधन के लिए प्रयास जारी हैं। अभी करीब 40-50 फीसदी का उपयोग किया जा रहा है। जानकारों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश से बनी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के प्रदूषण से बचाने के लिए एमआईटी के प्रोफेसर घोष के नेतृत्व में हुए शोध के अनुसार फ्लाई ऐश के घातक प्रभावों को रोकने में पानी की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था और स्थिरता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाना होगा। वहीं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि फ्लाई ऐश में पाई जाने वाली भारी धातुओं की लिचिंग के कारण भू-जल के प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है।

फर्जी बिल घोटाला...भुगतान रोका

8 माह पहले नगर निगम में फर्जी बिल महाघोटाले की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। अब नगर निगम अपने स्तर पर इस महाघोटाले की जांच कर रहा है और उस जांच के मुताबिक 692 बोगस फाइलों के जरिए 91 करोड़ का फर्जी भुगतान ठगोरी फर्मों ने निगम खजाने से हासिल कर लिया, जिसके चलते ऑडिट विभाग का भी पांच सालों का लगभग 130 करोड़ का भुगतान निगम ने रोक दिया। दूसरी तरफ शासन ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस पूरे महाघोटाले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी, वह भी खामोश बैठ गई। दूसरी तरफ कुछ आरोपी जमानत पा गए, तो कुछ अभी जेल में बंद हैं, वहीं पुलिसिया जांच की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई।

शुरुआत में नगर निगम का यह फर्जी बिल घोटाला 150 करोड़ रुपए से भी अधिक का बताया जा रहा था, जिसके चलते एक हजार से अधिक फाइलों की भी जांच-पड़ताल की गई। दरअसल, नगर निगम ने ही एमजी रोड थाने पर शुरुआत में पांच फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि इन फर्मों ने बोगस फाइलों के जरिए करोड़ों रुपए का भुगतान हासिल कर लिया। उसके बाद इस महाघोटाले की परत-दर-परत उजागर की गई, जिसके आधार पर शासन और यहां तक कि पुलिस महकमे को भी मदद मिली। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड निगम का ही इंजीनियर अभय राठौर निकला, जो फिलहाल जेल में बंद है। न्यू कंस्ट्रक्शन, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, क्षितिज और जाह्नवी इन्टरप्राइजेस व अन्य के बाद जब एमजी रोड थाने ने जांच शुरू की तो और भी बोगस फर्में और उनसे जुड़ी फाइलें और आरोपी सामने आए। दूसरी तरफ जब इस महाघोटाले का हल्ला भोपाल तक मचा तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी भी गठित की गई और उसने भी इंदौर नगर निगम पहुंचकर मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए, वहीं निगमायुक्त शिवम वर्मा ने भी अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई, जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 100 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ियां पकड़ीं। फिलहाल निगम के लेखा विभाग का कहना है कि उसने 1 हजार से अधिक फाइलों की जांच की, जिनमें सर्वाधिक ड्रेनेज विभाग की थी। उसके अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड, जनकार्य सहित अन्य विभागों की भी फाइलें सामने आईं।

नगर निगम ने सभी फाइलों की जांच के बाद जो निष्कर्ष निकाला, उसके मुताबिक 692 बोगस फाइलों के जरिए 91 करोड़ रुपए का भुगतान निगम खजाने से इन ठगोरी फर्मों ने हासिल किया। अब उनकी वसूली किस तरह होगी, यह तो कोर्ट द्वारा ही तय होगा। मगर चूंकि इस पूरे मामले में ऑडिट विभाग की लापरवाही और मिलीभगत भी उजागर हुई, जिसके चलते ऑडिट विभाग के भी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ अभी जेल में बंद भी हैं। नतीजतन निगम ने ऑडिट विभाग का 2020 से लेकर अभी तक का भुगतान रोक दिया, जो कि लगभग 130 करोड़ रुपए होता है। दूसरी तरफ एमजी रोड थाना प्रभारी विजयसिंह सिसोदिया का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, वहीं 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, तो कुछ आरोपी जेल में भी बंद हैं। पूर्व में 1200 पेज का चालान पेश किया गया था। अब पूरक चालान भी पेश होंगे और इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए गए हैं और सजा होना तय है।

निगम के इस फर्जी बिल महाघोटाले का एक मुख्य आरोपी एहतेशाम खान उर्फ काकू, जो पहले तो फरार रहा और बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। दरअसल, उसने 1.18 करोड़ रुपए जमा कराने के आधार पर जमानत ली है। दूसरी तरफ ईडी ने भी इस मामले में 21 ठिकानों पर कुछ समय पूर्व छापे मारे, जो कि 18 आरोपियों से जुड़े रहे। ईडी के इस छापे में 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद और साढ़े 3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के अलावा एफडी और अन्य दस्तावेज पाए गए। महालक्ष्मी नगर, मदीना नगर, सुखलिया, माणिकबाग, आशीष नगर सहित मुख्य आरोपी अभय राठौर के घर भी ईडी की टीम पहुंची, साथ ही ऑडिट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर समर सिंह, असिस्टेंट ऑडिटर रामेश्वर परमार सहित ठेकेदार असलम खान, एहतेशाम, इमरान, मोहम्मद जाकिर सिद्दीकी, मोहम्मद साजिद, रेणु वडेरा, राहुल वडेरा के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। हालांकि उसके बाद ईडी की कार्रवाई फिलहाल किस मोड पर है, उसकी अधिकृत जानकारी ईडी द्वारा भी नहीं दी गई। पिछले दिनों नगर निगम के कर्ताधर्ताओं ने अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए प्रिया इवेंट कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया और 3.18 करोड़ के इस ठेके की खबरें जब मीडिया में आई तो ऐन वक्त पर महापौर परिषद् पीछे हट गई। इसी प्रिया इवेंट कंपनी पर अभी जीएसटी चोरी के मामले में छापा पड़ा और 1 करोड़ से अधिक का टैक्स स्टेट जीएसटी ने जमा भी करवा लिया। प्रिया इवेंट के कर्ताधर्ता निमेश पिटालिया हैं, जो कि सरकारी ठेके अफसरों और जनप्रतिनिधियों की मदद से लेते रहे हैं और अब छापे के बाद बड़े टैक्स चोर भी साबित हुए। गनीमत रही कि निगम ने इस कंपनी को ठेका नहीं दिया, अन्यथा और भी फजीते होते।

● **सुनील सिंह**

किसी बड़े अधिकारी की नहीं मिली लिप्तता... बोगस निकले आरोप

विभागीय मंत्री से लेकर महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने महाघोटाला उजागर होने के बाद कुछ बड़े अधिकारियों को घेरने के प्रयास भी किए और मीडिया के जरिए उनके नाम भी उछाले गए। यहां तक कि मुख्य सरगना अभय राठौर की पत्नी का भी बयान चलाया गया। मगर अब तक किसी भी जांच में किसी बड़े अधिकारी की कोई लिप्तता सामने नहीं आई। यहां तक कि पुलिस विभाग ने हस्ताक्षरों के जो नमूने लिए थे, उनकी भी रिपोर्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर बोगस ही निकले और पूछताछ में भी ठेकेदार आरोपियों ने यही कबूल किया कि ये फाइलें उन्होंने खुद तैयार कीं, जिसमें नकली सील-सिक्के और हस्ताक्षर भी उन्हीं के द्वारा किए गए, जिसके चलते अभय राठौर सहित निगम के कुछ निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारी, ठेकेदार और ऑडिट विभाग के अधिकारी इस पूरे महाघोटाले के सरगना साबित हुए।

करीब दो दशक पहले तक मप्र विधानसभा को अन्य राज्यों में आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। क्योंकि सत्र पूरे समय चलते थे और काम भी खूब होते थे। लेकिन अब सत्र छोटे तो हो ही रहे हैं, पूरे समय चल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शीतकालीन सत्र से मप्र की आदर्श तस्वीर फिर लौटेगी।

लगातार सिमट रहा विधानसभा सत्र

मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिनों के इस सत्र के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह सत्र कितने दिन चलेगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि प्रदेश में विधानसभा सत्र की बैठकों की संख्या लगातार सिमटती जा रही है। उस पर स्थिति यह है कि विधायकों की निष्क्रियता के कारण जनहित के मुद्दे सदन में उठ नहीं पाते हैं। यहां बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान एक दिन के प्रश्नकाल पर तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन प्रश्नकाल हंगामें की भेंट चढ़ जाते हैं। एक दिन के प्रश्नकाल पर औसतन 50 लाख रुपए तक व्यय आता है। ये राशि विधानसभा की एक दिन की बाकी कार्यवाही के कुल खर्च से भी ज्यादा है, क्योंकि सदन की हर घंटे की कार्यवाही 2.50 लाख रुपए की पड़ती है। यदि 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च 12.50 लाख तक आता है। गौरतलब है कि मप्र विधानसभा के सत्र में बैठकों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस बार 16 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र भी 5 दिनों का है। पिछले सत्रों में बैठकों की कम संख्या को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सत्र भी पूरा चलेगा? उल्लेखनीय है कि मप्र विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को बजट पेश किया। दो दिन बाद 5 जुलाई को बजट सत्र खत्म हो गया। इस दौरान बजट भी पास हो गया और बिना चर्चा के 6 विधेयक भी पारित हो गए, जबकि सत्र की अवधि 14 दिनों की तय हुई थी। इसे 19 जुलाई तक चलना था।

मप्र की विधानसभा को सबसे अच्छी विधानसभा माना जाता था, क्योंकि प्रदेश के विधायक पूरे मनोयोग के साथ न केवल सवाल पूछते थे, बल्कि एक-एक मुद्दे पर चर्चा भी करते थे, लेकिन यह परंपरा धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1998 से लेकर जुलाई 2024 तक इन 26 सालों में बैठकों की संख्या 93 प्रतिशत घट गई है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है। विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी का कहना है कि बैठकों का कम होना सबसे बड़ी चिंता की वजह है। विधानसभा जनहित के मुद्दे उठाने का सबसे प्रभावी मंच है। इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। इसी जगह लोगों की बात नहीं रखी जाएगी तो उनका पहले से जो भरोसा कम हुआ है वो और कम होगा। इसरानी कहते हैं कि विधानसभा की बैठकों की कम होती संख्या का मुद्दा कई बार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उठ चुका है। वे कहते हैं कि साल 2003 में लोकसभा में ऐसा ही सम्मेलन हुआ था। जिसमें सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और सचिवों ने हिस्सा लिया था। इसमें सुझाव आया कि संसद में 100 दिन की बैठकें होना चाहिए। मप्र, उप्र, राजस्थान जैसी बड़ी विधानसभाओं के लिए 75 बैठकों का सुझाव दिया गया। ये सब तय हुआ, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इसरानी कहते हैं कि संविधान में तीन सत्र आहूत करने का प्रावधान है, लेकिन बैठकों को लेकर संविधान साइलेंट है। संविधान की इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। मप्र का शासन, प्रशासन और यहां की विधानसभा अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल मानी जाती हैं, लेकिन पिछले दो दशक से मप्र के माननीयों का मन लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा में नहीं लग रहा है। शायद यही वजह है कि पिछले दो दशक से मप्र विधानसभा का कोई भी सत्र पूरा नहीं चला। हालांकि सत्र भले ही अधूरे रह गए, लेकिन उनमें काम पूरा हुआ।

1998 से लेकर जुलाई 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह तथ्य सामने आता है कि सत्र के दौरान केवल 10 फीसदी विधायक ही सवाल पूछ पाते हैं। पिछले मानसून सत्र में 14 बैठकें होनी थीं, लेकिन सिर्फ 5 हुईं। इन पांच

सत्र अधूरा...काम पूरा

वर्ष 2004 से लेकर 2024 के मानसून सत्र तक पिछले 20 साल में मप्र विधानसभा की 105 बैठकें आयोजित की गईं। लेकिन विडंबना यह है कि इनमें से मात्र 65 दिन ही विधानसभा चल सकी। हालांकि इस दौरान विधानसभा के सारे कामकाज निपटते रहे। ऐसा ही कुछ हाल ही में संपन्न इसी मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में भी देखने को मिला। ये सत्र 1 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलने वाला था, लेकिन अपने तय वक्त से 14 दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। इस मानसून सत्र के दौरान मोहन सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट को पेश किया गया। तो वहीं नर्सिंग घोटाले की गूंज भी इस विधानसभा सत्र में सुनाई दी है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब तय वक्त से पहले सत्र को स्थगित कर दिया गया हो, ऐसा पिछले 20 सालों से चला आ रहा है। इस सत्र में भी कई विधायकों के प्रश्न अधूरे रह गए हैं, जो प्रश्न विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र को लेकर लगाए गए थे। इस विधानसभा सत्र में 4 हजार से अधिक प्रश्न लगाए गए थे, जिनमें से आधे भी प्रश्नों पर चर्चा नहीं की गई है। 5 दिन चले मानसून सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों, मंत्रियों, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव को अब खुद ही इनकम टैक्स भरना होगा, जिसे पहले सरकार भरा करती थी।

दिनों में तीन दिन प्रश्नकाल हुआ। एक दिन बजट और एक दिन पूर्व विधायकों के निधन के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ था। तीन दिनों में 75 विधायक अपने सवालों का जवाब मंत्रियों से ले सकते थे, लेकिन 38 विधायकों ने मंत्रियों से सवाल-जवाब किए। यदि इस सत्र के दौरान निर्धारित 14 बैठकें होतीं और बिना व्यवधान के प्रश्नकाल होता तो 350 विधायक सवाल के जवाब मंत्रियों से ले सकते थे। यानी सिर्फ 10 फीसदी को ही जवाब मिला। आंकड़ें इस बात के भी संकेत देते हैं कि बजट सत्र को लेकर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं हैं। मप्र की 11वीं विधानसभा में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने फरवरी-मार्च 1999 में बजट पेश किया था जो 52 दिन के सत्र का था। यह अब तक की पांच विधानसभाओं का सबसे ज्यादा बैठकों का बजट सत्र रहा है। इस सत्र की 31 बैठकों में बजट पर विधायकों ने चर्चा की और तब मप्र का बजट पारित हुआ था। इसके बाद से आज तक कभी भी 31 बैठकों का बजट सत्र नहीं रहा। दिग्विजय सरकार के इसके बाद के चार बजट सत्र भी 25 से 28 बैठकों वाले रहे। 15वीं विधानसभा आते-आते 22 साल में बजट जैसे गंभीर मामले में बैठकों की संख्या 8 से 13 के बीच रह गई। डॉ. मोहन सरकार ने मानसून सत्र (1 से 5 जुलाई) के दौरान मप्र का वर्ष 2024-25 का बजट (3 लाख 65 हजार करोड़) सदन में पेश किया था। इस दौरान सिर्फ पांच बैठकें हुईं।

विधानसभा में इस बार 230 में से 70 नए विधायक हैं। इनमें से कांग्रेस के 24, भारत आदिवासी पार्टी का एक और भाजपा के 45 विधायक हैं। नए विधायक ज्यादा से ज्यादा सवाल करें इसके लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि सत्र में एक दिन ऐसा होगा जब प्रश्नकाल के दौरान केवल नए विधायक ही सवाल पूछेंगे। साल 2023 के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को ऐसा पहली बार किया भी गया था। विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी कहते हैं कि जब सत्र की अवधि और बैठकों की संख्या कम होगी तो नए विधायकों को मौका कहां से मिलेगा। वे कहते हैं कि विधायक जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब तैयार करने में विधायक, उसका स्टाफ,

विधानसभा के स्टाफ का वेतन, संभाग और जिला स्तर पर होने वाला खर्च शामिल होता है। इस तरह एक सवाल का जवाब तैयार करने में औसत 50 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। कुछ सवालों के जवाब जुटाने में गांवों से भी जानकारी मंगाई जाती है। इनका खर्च 75 हजार से एक लाख रुपए तक चला जाता है।

शीतकालीन सत्र की तैयारियों से जुड़े रिव्यू में सामने आया है कि विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। यदि दिए भी हैं तो वह भी अधूरे हैं। शून्यकाल में यदि किसी विधायक ने कुछ पूछा है तो वह भी पेंडिंग है। हैरान करने वाली बात है कि विधायकों के सवालों पर मंत्रियों की ओर से जो वादे-आश्वासन दिए जाते हैं और सिफारिशें होती हैं, वह भी सैकड़ों की संख्या में धूल खा रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विधानसभा से जुड़े मसलों को लेकर गत दिनों मंत्रालय में मीटिंग की। इसमें विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जैन ने कहा कि मैं दिल्ली में रहा हूं। वहां काफी एक्सरसाइज होती थी, तत्परता से काम करते थे। यहां तो शून्यकाल की सूचनाओं के जवाब भी पेंडिंग हैं। जैन ने यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र में काफी विधेयक आने वाले हैं। इसकी तैयारी जल्द से जल्द हो। 10 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में बिल को हरी झंडी मिल चुकी है। इस पर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि 14-15 बिल आने हैं और तैयार 203 बिल ही हैं। आखिरी समय में बिल आते हैं तो उनके प्रकाशन के दौरान तथ्यों में गड़बड़ हो जाती है। सरकार चाहे तो विधानसभा को पहले बता दे कि वह कितने बिल ला रही है। मुख्य सचिव ने कहा, विधानसभा भी बड़े प्रश्नों से जुड़े मामलों को देखे। अनावश्यक उत्तर के चक्कर में लंबा वक्त और समय लगता है। सिंह ने कहा, इसका ध्यान रखेंगे। मप्र में शून्यकाल के जवाब भी सरकार में पेडिंग हैं। कुल 43 मामले हैं। सर्वाधिक 12 केस राजस्व महकमे के हैं। फिर पीडब्ल्यूडी की 6, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व स्कूल शिक्षा की क्रमश: 4-4 शिकायतें हैं।

अगर आंकलन किया जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि विधानसभा के सत्रों के दौरान जनहित के मुद्दों पर विधायक ठीक से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा के इसी मानसून सत्र में मप्र में खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024 पारित हुआ। इस विधेयक में नलकूप की ड्रिलिंग की जिम्मेदारी तय करने के साथ भूमि स्वामी और ड्रिलिंग एजेंसी पर कार्रवाई तय करने का प्रावधान है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

अनुपूरक बजट के साथ आधा दर्जन विभागों के विधेयक भी होंगे पेश

विधानसभा का शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद दूसरे दिन चालू वित्त वर्ष का अनुपूरक बजट पेश होगा। इस बजट को मोहन सरकार सत्र शुरू होने के पहले मंजूरी देगी। विधानसभा सचिवालय ने पांच दिन तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए कार्ययोजना घोषित कर दी है। इसमें कहा गया है कि, पहले दिन सत्र शुरू होने पर प्रश्नोत्तर काल होगा और इसके बाद अलग-अलग विभागों के आधा दर्जन विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद 17 दिसंबर को सुबह प्रश्नोत्तर काल होगा और इसके बाद वर्ष 2024-25 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य शासकीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा तीसरे दिन होगी और इसी दिन एमपी विनियोग विधेयक 2024 पेश होगा। इसके अलावा सत्र के बाकी दिनों में प्रश्नोत्तर काल, शून्य काल, ध्यानाकर्षण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

समय पर चावल नहीं दिया तो जुर्माना

मप्र में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदी 2 दिसंबर से शुरू हो गई है। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 और धान ग्रेड-ए का 2,320 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जा रही है। वहीं सरकार ने धान की मिलिंग के लिए गाइडलाइन भी तय कर दी है। इस बार मिलिंग 30 जून तक होगी यानी इस अवधि में मिलर्स को चावल निकालकर देना होगा। जब मिलर उपार्जन केंद्र या गोदाम से धान उठाएगा, तबसे उसे 20 दिन के भीतर मिलिंग करके चावल जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर दो रुपए प्रतिदिन प्रति क्विंटल के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रविधान देश की मिलिंग नीति में पहली बार किया गया है। इसकी वजह समय से मिलिंग करने के साथ भारतीय खाद्य निगम को चावल देकर राशि प्राप्त करना है कि सरकार पर ब्याज का भार न बढ़े।

इस बार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन की जाएगी। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जाएगा। परिवहनकर्ता द्वारा उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन समय-सीमा में नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केंद्र पर लाई जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं। नमी जांचने के बाद धान लेकर सीधे उपार्जन केंद्र से ही मिलिंग के लिए मिलर्स को दी जाएगी। इससे परिवहन और भंडारण व्यय में कमी आने के साथ मिलिंग भी समय पर होगी। भारतीय खाद्य निगम ने मिलिंग के लिए अंतिम सीमा जून रखी है। प्रदेश में लगभग 900 मिलर है। कोई भी मिलर मिलिंग करने से सरकार को इनकार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसका पंजीयन और शासन की भूमि पर यूनिट लगी है तो लीज निरस्त की जा सकती है। मिलर को एक क्विंटल धान के बदले में 67 किलोग्राम चावल निकालकर देना होगा। इसके अलावा जो टूटन या कनकी बचेगी, वह मिलर की होगी। इसके अतिरिक्त प्रति क्विंटल 10 रुपए मिलिंग चार्ज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 50 रुपए प्रति क्विंटल अलग से प्रोत्साहन राशि देगी।

उपार्जन के लिए 14 लाख 12 हजार 857 लाख हेक्टेयर धान का क्षेत्र (रकबा) पंजीकृत हुआ है। प्रदेश को प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के लिए लगभग 15 लाख टन चावल लगता है। इसे बचाने के बाद लगभग 13 लाख टन चावाल होगा, जो सेंट्रल मूल में भारतीय खाद्य निगम को दिया जाएगा। मिलिंग के लिए केंद्र सरकार ने अवधि 30 जून निर्धारित की है। यह अभी तक सितंबर-अक्टूबर रहती थी। अवधि कम होने का मतलब यह हुआ कि कम समय में मिलिंग पूरी कराना होगी। इसके लिए मिलिंग नीति 2024-25 में कई प्रविधान किए गए हैं। मिलर को धान लेने के बाद निर्धारित अवधि में चावल निकालकर देना होगा। यदि नियत अवधि, जो 20 दिन होगा, में आपूर्ति नहीं की जाती है तो फिर जुर्माना लगेगा। यह प्रतिदिन प्रति क्विंटल दो रुपए रहेगा। इतना ही नहीं, एक माह में चावल जमा न कराने पर मिलर की 2,300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लगने वाली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले चावल की मात्रा 60 प्रतिशत से कम रहती है तो प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी जाएगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रविधान इसलिए किए गए हैं ताकि समयसीमा में मिलिंग पूरी हो जाए। उपार्जन केंद्र से सीधे मिलर को धान दी जाएगी। इससे परिवहन और भंडारण का व्यय तो बचेगा ही सूखत की समस्या भी नहीं होगी। यह व्यवस्था अन्य राज्यों में भी लागू है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य किस्म की धान 2,300 और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। गुणवत्तायुक्त उपज का ही उपार्जन हो, इसके लिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। राज्य और जिला स्तर पर उपार्जन पोर्टल पर दर्ज होने वाली उपज संबंधी जानकारी के आधार पर आंकलन किया जाएगा। यदि उपज में कचरा, टूटन या नमी अधिक होती है तो उसे लौटा दिया जाएगा। जब किसान उपज ठीक कराकर निर्धारित मापदंड के अनुसार लाएगा, तब ही उसे स्वीकार किया जाएगा। दरअसल, धान किसान से लेने के बाद उसे चावल बनाने के लिए मिलर्स को दी जाती है। उस समय कई बार नमी, कचरा और टूटन अधिक होने की शिकायत सामने आती है। ऐसी उपज मिलर्स नहीं लेते हैं क्योंकि प्रति क्विंटल धान से 67 किलोग्राम चावल लिया जाता है। जब यह मात्रा नहीं मिलती है तो मिलर्स को नुकसान होता है। यही कारण है कि इस बार गुणवत्तायुक्त उपज की खरीदी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

● **जितेंद्र तिवारी**

मोटे अनाज खरीदे बिना बोनस देगी सरकार

मप्र सरकार ने किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार मिलेट्स (कोदो-कुटकी) खरीदे बगैर ही किसानों को बोनस का भुगतान करेगी। किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए बोनस दिया जाएगा। सरकार इस साल किसानों को करीब 40 करोड़ रुपए बोनस देगी। गौरतलब है कि मोहन कैबिनेट ने जनवरी में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। फिर मिलेट्स फेडरेशन का गठन किया गया। लेकिन तमाम जतन करने के बाद भी मप्र सरकार इस साल राज्य में किसानों से मिलेट्स की खरीदी नहीं कर पाई।

मप्र की प्रजनन दर गिरी

भारत की घटती प्रजनन दर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत द्वारा चिंता जताए जाने के बाद देशभर में यह मुद्दा बन गया है। जनसांख्यिकी के नियमों के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। भागवत के अनुसार आधुनिक जनसंख्या विज्ञान के अनुसार जब किसी समाज की संख्या वृद्धि (प्रजनन दर) 2.1 से कम हो जाती है तो वह समाज संसार से विलुप्त हो जाता है। यदि हम 2.1 जनसंख्या वृद्धि दर पर विचार करें, तो हमें दो से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। तीन तो होने ही चाहिए। जनसंख्या विज्ञान यही कहता है। भागवत ने कहा कि समाज के जीवित रहने के लिए संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। इन मापदंड़ों पर आंकलन किया जाए तो मप्र के प्रमुख शहरों में प्रजनन दर गिरी है। प्रदेश में भोपाल की प्रजनन दर सबसे कम है।

संघ प्रमुख के बयान के परिप्रेक्ष्य में यदि मप्र की स्थिति देखी जाए तो यहां भी प्रजनन दर वर्ष 2001 से लगातार कम हो रही है। जानकारी के अनुसार भोपाल की प्रजनन दर पिछले एक दशक से 2 पर स्थिर है। 2011-12 में भोपाल की प्रजनन दर 2.1 थी। एनएचएम के अधिकारियों के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत ज्यादा होने के कारण यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम ज्यादा सफल साबित हुआ है। दूसरी तरफ प्रजनन दर के मामले में मप्र की हालत बहुत खराब है। प्रदेश की टीएफआर 2.8 है जो देश (2.3) की तुलना में 0.5 ज्यादा है। इस प्रकार ज्यादा टीएफआर के मामले में हम बिहार (3.3), उप्र (3.1) के बाद तीसरे नंबर पर हैं। बीते तीन साल में प्रदेश की टीएफआर में एक पॉइंट का भी बदलाव नहीं आया है। यह स्थिति तब है जब मप्र में बीते पांच साल से टीएफआर को 2.1 पर लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-3) 2011 के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुस्वर, मप्र में प्रजनन दर वर्ष 2001 में 3.86 थी, जो वर्ष 2011 में 3 रह गई। यह आकड़े अभी भले ही संतोषजनक लगें, परंतु प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात की जाए तो आकड़े चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में टीएफआर राष्ट्रीय मानक 2.1 से भी कम केवल 2 हैं, जबकि ग्वालियर की 2.1, इंदौर की 2.2 और जबलपुर की 2.4 बताई गई है। इसके पीछे इन शहरों में लोगों का अधिक शिक्षित होना और परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देना माना जा रहा है। प्रदेश के छोटे जिलों शिवपुरी-श्योपुर और पन्ना आदि में यह चार से अधिक है। प्रदेश की कुल प्रजनन दर का आंकड़ा तीन के आसपास रहा है। महानगरों में प्रजनन दर और कम हो सकती है, क्योंकि एनएफएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट में मप्र को प्रजनन दर केवल 2 ही बताई गई है।

देश-प्रदेश व जिलों में युवाओं की संख्या कम होगी, बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी। कामकाज करने वाली आबादी के कम होने से आर्थिक व्यवस्था कमजोर होगी। सरकार पर स्वास्थ्य व पेंशन के भुगतान का बोझ बढ़ेगा। कुछ समय बाद देश से कई सामाजिक वर्ग कम हो सकते हैं। कुछ समय बाद जनसंख्या कम होने लगेगी। लिंगानुपात में भी अंतर बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार हमारा देश व प्रदेश विविध भौगोलिक क्षेत्र वाला है। यहां पहले से ही लिंगानुपात में अंतर है। बालिकाओं व महिलाओं की संख्या कम है। प्रजनन दर कम होने से इनकी संख्या और अधिक कम हो जाएगी। इससे भी सामाजिक असमानता बढ़ जाएगी। देश में प्रजनन दर कम होने के कारण की बात है तो वह कुछ वर्गों में अधिक कम हो रही है। कुछ की प्रजनन दर पहले से भी अधिक है।

प्रजनन दर में लगातार हो रही गिरावट का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। कम जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है, क्योंकि सीमित संसाधनों को कम लोगों में बांटना होगा। कम बच्चों के होने से परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक में बढ़ोतरी संभव है। कम जनसंख्या का मतलब कम संसाधनों का उपयोग होगा, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम होगा। हालांकि इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिसकी तरफ मोहन भागवत ने इशारा किया है। कम जन्म दर के कारण बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है। कम जन्म दर के कारण भविष्य में कार्यबल में कमी आ सकती है, जिससे उत्पादकता कम हो सकती है। लंबे समय में कार्यबल में कमी आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पारंपरिक परिवार संरचना में बदलाव और सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो सकते हैं। किसी विशेष समुदाय के सामने विलुप्त होने का खतरा भी आ सकता है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

कई देशों में कम हो रहा है प्रजनन दर

ईरान, यूनाइटेड किंगडम, चीन जैसे देशों में भी प्रजनन दर में तेज गिरावट हुई। जापान में सबसे कम प्रजनन दर देखने को मिल रही है। ताइवान, इटली, स्पेन, सिंगापुर में भी भारी गिरावट हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी इसे बढ़ावा दिया गया था। ईरान में प्रजनन दर प्रति महिला 6 से अधिक बच्चों से घटकर प्रति महिला 3 से कम बच्चों तक पहुंचने में केवल 10 साल लगाया। चीन में यह बदलाव 11 साल में आए। भारत में भी साल 2000 के बाद जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिली। अगर इन देशों के आर्थिक विकास को देखेंगे तो जनसंख्या दर में गिरावट के साथ ही भारत और चीन जैसे देश ने तीव्र आर्थिक विकास किया। हालांकि जानकारों का हमेशा से मानना रहा है कि तीव्र गिरावट का असर 2-3 दशक के बाद उत्पादकता पर देखने को मिल सकता है।

बजट की कमी...मिशन की रफ्तार थमी

घर-घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के मकसद से 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना अधर में लटकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए मार्च 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन बजट की कमी से जल जीवन मिशन की रफ्तार थमने लगी है। जल जीवन मिशन में केंद्र से भुगतान की देरी के कारण उप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्य भी जूझ रहे हैं। राज्यों के खजानों में राशि की कमी है। और इस प्रोजेक्ट को जारी भी रखना है। इसकी अर्थव्यवस्था में राज्यों के वित्त विभाग भी गहन विमर्श कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव ने केंद्र सरकार से दूसरे चरण की बकाया राशि के भुगतान के लिए पत्र लिखा है। दूसरे चरण के पहली किस्त में 600 करोड़ आ चुके है, अभी 1422 करोड़ का बकाया है।

यह स्थिति तब है जब केंद्रीय बजट में जलशक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन-हर घर जल योजना को बड़ा बूस्ट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाली हर घर नल से जल योजना को बजट में 2022-23 के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे वित्त वर्ष 2022-23 में 3.80 करोड़ नए ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण की तरफ से पेश आत्मनिर्भर भारत का बजट, 140 करोड़ भारतीयों को परिवर्तनकारी लाभ देगा।

केंद्रीय मंत्री शेखावत का कहना है कि नल से जल के 3.80 करोड़ नए कनेक्शन, रासायनिक मुक्त कृषि के लिए गंगा किनारे पांच किलोमीटर चौड़े गलियारा से लेकर केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए पानी, यह सब सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय की जरूरतों का बजट में पूरा करने का ध्यान रखा गया है। शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाने के वादे को पूरा करने की मजबूत कार्ययोजना प्रस्तुत करता है। शेखावत ने कहा कि देशभर के 19 करोड़ 27 लाख 76 हजार 015 ग्रामीण परिवारों में से करीब 8.91 करोड़ से अधिक (46 फीसदी से अधिक) घरों में नल से जल मिलने लगा है। योजना की घोषणा के ढाई साल पूर्व 17 फीसदी से भी कम ग्रामीण घरों में नल से जल मिल रहा था। बीते ढाई साल के कार्यकाल में करीब 5.67 करोड़ नए नल से जल कनेक्शन दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 50 हजार 11 करोड़ के मुकाबले करीब 10 हजार करोड़ रुपए अधिक हैं। पिछले वित्त वर्ष में 3.25 करोड़ नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। संशोधित बजट अनुमान 45 हजार 11 करोड़ रुपए के मुकाबले तो यह करीब 15 हजार करोड़ रुपए अधिक है।

दरअसल, केंद्रीय फंड की कमी और पहले से हो चुके काम का भुगतान न होने के कारण यह योजना अटक गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन की रफ्तार प्रदेश में अब मंद पड़ चुकी है। कारण बजट की कमी है। भुगतान नहीं होने से प्रदेश में करीब 70 फीसदी काम बंद हो चुका है। समय रहते राशि जारी नहीं होने पर शेष 30 फीसदी काम भी रुकने की आशंका है। यही वजह है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने राज्य के खजाने से 775 करोड़ रुपए मांगे हैं। मालूम हो, केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में 600 करोड़ की पहली किस्त अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि अब केंद्र से दूसरी और तीसरी किस्त भी जल्द जारी होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ।

केंद्र ने इस वित्त वर्ष में मप्र को मिशन के लिए 4,044 करोड़ रुपए और राज्य ने 7,671.60 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के मुताबिक वर्क ऑर्डर में केंद्र-राज्य का हिस्सा 50-50 प्रतिशत और व्यावसायिक गतिविधियों में 60-40 प्रतिशत होगा। बीते साल जल जीवन मिशन के तहत मप्र में 10,773.41 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिलहाल इस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान रुका हुआ है। पुराने आंकड़ों को देखते हुए 2024-25 में राज्य में इस योजना के लिए कम से कम 17,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अब जानकारी लगी है कि कम भुगतान के कारण छोटे ठेकेदारों ने काम समेटना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन बेहद सचेत हैं। सरकार चाहती है कि काम किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। यही वजह है कि दोनों ने ही क्रमशः राजनीतिक व प्रशासनिक तरीके से केंद्र से बकाया राशि की मांग की है।

● कुमार राजेंद्र

पुरानी योजनाओं जैसा हाल न हो जाए

बुंदेलखंड और विंध्य का क्षेत्र हमेशा से ही प्यासा रहा है। पहले भी योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन कभी गांव वालों को पानी नहीं मिला। अब जल जीवन मिशन योजना आई तो उम्मीद थी, लेकिन यह भी टूटती जा रही है। चित्रकूट जिले के गांव रैपुरा में जल निगम का पुराना प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तकरीबन 4 साल पहले यहां जल निगम ने कुछ घरों में पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचाया था। अब फिर से जल जीवन मिशन के तहत यहां दोबारा काम हो रहा है। गांव में छूटे हुए करीब 25 प्रतिशत घरों को आस जगी कि अब यहां इस नई योजना के तहत पानी पहुंच जाएगा। लेकिन, काम करने वाली कंपनी ने फर्जी रिपोर्टिंग करके जल जीवन मिशन की सरकारी वेबसाइट में यहां 100 फीसदी काम पूरा होना बताया। हकीकत में सिर्फ गांव में इधर-उधर खुदाई करके पाइप लाइन डाली गई, बाकी वैसे ही छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में प्रदेश को 4044 करोड़ और राज्य सरकार ने 7671 करोड़ रुपए दिए। गाइडलाइन में वर्क ऑर्डर में केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50 प्रतिशत और व्यावसायिक गतिविधियों में 60-40 प्रतिशत होता है। बीते साल प्रदेश में इस योजना में 10773 करोड़ खर्च हुए थे।

चुनौती बना लॉरेंस

अगला दाउद बन रहा लॉरेंस

तो क्या अब लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाउद इब्राहिम बन रहा है। जवाब है हां... वो उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की चार्जशीट कह रही है, जिसमें दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की एक फौज है। और इनमें भी 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब से ही हैं। दाउद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह से 90 के दशक में छोटे-मोटे अपराध करके दाउद इब्राहिम ने अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है।

साल 2024 में एक गैंगस्टर ऐसा भी रहा जिसके चर्चे देश से लेकर पूरी दुनिया में हुए। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई वही लॉरेंस जो कई आपराधिक मामलों में फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन उसके नाम का खौफ ऐसा है कि पुलिस भी खुद इससे परेशान रहती है। लॉरेंस को मुंबई का अगला डॉन भी कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूं तो पहले भी कई क्राइम में सामने आ चुका है। लेकिन साल 2024 में तीन केस ऐसे रहे जिनके कारण वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ये केस हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग का, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सांसद पप्पू यादव को धमकी के।

14 अप्रैल को सलमान खान के घर (गैलेक्सी अपार्टमेंट) पर फायरिंग हुई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। पुलिस ने इस मामले में विक्की गुप्ता (24 साल) और सागर पाल (21 साल) नाम के दो लड़कों को गिरफ्तार किया था। इन पर आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में एक अहम आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की हिरासत में ही फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। अनुज पर सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम था। इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। वो अमेरिका में था। उसने वहीं से इस वारदात को करने का ऑर्डर दिया था। बाद में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था। अमेरिका में पुलिस ने अनमोल को गिरफ्तार कर लिया। उसे फिलहाल आयोवा की एक ऐसी विशेष जेल में रखा गया है, जो घूमती है। लॉरेंस पिछले 6 साल से सलमान खान को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा है।

साल 2018 में लॉरेंस ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। लॉरेंस चाहता है कि सलमान उनके बीकानेर स्थित मंदिर में आकर हिरण को मारने का पश्चाताप करे और अपने किए पर माफी मांगे। इस घटना के बाद से कई बार लॉरेंस के नाम पर व्यापारियों से लेकर नेताओं को धमकियां आईं। फिर अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस हाईप्रोफाइल मर्डर केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने गत दिनों 13 गिरफ्तार आरोपियों को 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद दिसंबर महीने में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी एक धमकी भरा कॉल आया। उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम लिया गया। हालांकि बाद में इस बात का भी खुलासा हुआ कि पप्पू को धमकी देने की साजिश उन्हीं के प्रवक्ता ने रची थी। इस मामले में एक युवक को अरेस्ट किया गया है। उसी ने पुलिस के सामने पप्पू के प्रवक्ता राजेश यादव का नाम लिया। फिलहाल इस केस की जांच जारी है। लॉरेंस के नाम पर आए दिन इस तरह की धमकियों के केस सामने आते ही रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया का वो नाम बन गया है, जो कुछ सालों से हाई प्रोफाइल मर्डर में शामिल रहा है। पंजाब के फजिल्का जिले के दुतरांवाली गांव में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कई युवक बतौर शूटर उसके लिए काम करते हैं। लॉरेंस की गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। 11 राज्यों और 6 देशों में बिश्नोई गैंग खुलेआम वारदातों को अंजाम देता है। एक थ्योरी की मानें तो लॉरेंस को पॉवरफुल नेताओं का समर्थन प्राप्त है। साथ ही कनाडा कनेक्शन भी उसे भारत में ऐसी वारदातों को अंजाम देने की आजादी देता है। कनाडा से इस गैंग को लॉरेंस के खास गुर्गे ऑपरेट करते हैं। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई जैसे लॉरेंस के खास गुर्गे गैंग को चलाते हैं। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक, 12 साल में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 36 क्रिमिनल केस दर्ज किए जा चुके थे। ये केस पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दर्ज थे। 36 में से 21 मामलों में सुनवाई अब भी जारी है, जबकि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है। 6 मामलों में बिश्नोई को दोषी ठहराया जा चुका है।

लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई तो वकालत की की थी और उस पढ़ाई के दम पर या तो वो एक वकील बन गया होता या फिर उसने ज्यूडिशियरी की तैयारी की होती तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वो हनक इस सनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं आगे बढ़ता गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10-12 साल में पंजाब पुलिस के एक कॉन्सटेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक फौज है, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकती है। आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की है, जैसी हनक कभी 90 के दशक में दाउद इब्राहिम की हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम और नए-नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज कॉमन है। वो है दोनों के पिता का प्रोफेशन। दाउद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में। इसके अलावा एक और चीज कॉमन है और वो है दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क जो भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है।

● **बृजेश साहू**

पर्यटन का केंद्र बनेगा रातापानी टाइगर रिजर्व

तीन जिलों का आर्थिक विकास

रातापानी टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से तीन जिलों का भी आर्थिक विकास होगा। रातापानी में तीन हजार से अधिक वन्यप्राणी है। इनमें 96 बाघ, 70 तेंदुए, आठ भेड़िया, 321 चिंकारा, 1433 नीलगाय, 568 सांभर और 667 चीतल है। टाइगर रिजर्व से ग्रामीणों के वर्तमान अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर्यटन बढ़ेगा और नए रोजगार सृजित होने से ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से बजट प्राप्त होने से वन्यप्राणियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकेगा। स्थानीय ग्रामीणों को ईको विकास के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। राजधानी भोपाल की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइगर राजधानी के रूप में होगी। भोपाल तक फ्लाइट कनेक्टिविटी होने से पर्यटकों, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भोपाल से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित भोजपुर शिवमंदिर को भोजेश्वर लोक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार मास्टर प्लान भी तैयार कर रही है। यहा पर्यटकों का जमावड़ा सालभर बना रहा है। यहां प्राचीनकाल से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है।

मप्र में बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। यह राज्य का आठवां टाइगर रिजर्व है, जहां लगभग 90 बाघ रहते हैं। यह फैसला काफी समय से लंबित था। 2008 में एनटीसीए से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने में देरी की थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से राज्य सरकार को अधिसूचना प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। उन्होंने इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष और बाघों की आबादी की रक्षा की जरूरत का हवाला दिया था। अब रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। यह बाघों के एक महत्वपूर्ण आवास का हिस्सा है। हाल के वर्षों में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बाघ इस अभयारण्य और आसपास के वन क्षेत्रों में आने लगे हैं। बाघों के इन इलाकों में आने के बाद, 2007 में राज्य सरकार ने रातापानी और सिंघोरी अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

रातापानी टाइगर रिजर्व एकमात्र लैंडस्केप है, जहां 96 बाघ विचरण करते हैं। वन्यजीवों से भरपूर टाइगर रिजर्व और भोपाल शहर के मध्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। पुरापाषाण काल शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका और आस्था का केंद्र भोजपुर शिवमंदिर को विश्व पटल पर रखकर पर्यटन को बढ़ावा देने काम किया जाएगा। आस्था और संस्कृति के दर्शन के साथ पर्यटक अब राष्ट्रीय उद्यान सहित आठवां टाइगर रिजर्व भी घूम सकेंगे। इसके लिए वन विभाग, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और व्यापार, व्यवसाय भी बढ़ेगा। रातापानी टाइगर रिजर्व का झिरी गेट भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं औबेदुल्लागंज स्थित गेट की दूरी भोपाल से 50 किलोमीटर है। इस टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत बजट उपलब्ध कराएगी और 40 प्रतिशत राज्य का अंश होगा। यह टाइगर रिजर्व रायसेन, सीहोर और भोपाल जिले की सीमा तक फैला हुआ है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसको लेकर मप्र ईको पर्यटन विकास बोर्ड ने कार्ययोजना बनाई। पुरापाषाण काल शैलचित्रों और शैलाश्रयों के अलावा यहां देवीजी का प्राचीन मंदिर है। इसे धार्मिक दृष्टि से डेवलप किया जाएगा। वहीं भोपाल शहर के मध्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव और पर्यटकों के लिए पहले से ओर बेहतर डेवलप किया जा रहा है। यहां विलुप्त प्राय जेबरा, जिराफ व गेंडा जैसे वन्यजीवों को बसाया जाएगा। इसको लेकर दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से वार्ता की जा रही है। इसके अलावा यहां स्नेक पार्क (सर्प उद्यान) को भी विकसित किया जा रहा है। यहां किंग कोबरा सहित दुर्लभ प्रजाति के सर्पों को पर्यटक नजदीक से देख व समझ सकेंगे।

एनटीसीए ने 2008 में रिजर्व के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। राज्य वन विभाग को रिजर्व की सीमाओं और कोर क्षेत्रों के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, अंतिम अधिसूचना प्रक्रिया में कई देरी हुई। 2012 में, एनटीसीए ने राज्य सरकार को रिमाइंडर जारी किए, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। पीआईएल में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रातापानी टाइगर रिजर्व को अंतिम रूप देने में देरी के कारण बाघ-मानव संघर्ष में वृद्धि हुई है। बाघ भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में भटक रहे हैं। अतिक्रमण और आवास क्षरण के कारण अभयारण्य के भीतर पर्याप्त शिकार की कमी ने इस स्थिति को और बदतर बना दिया है।

2011 में, स्थानीय रिपोर्टों ने भोपाल के बाहरी इलाके में बाघों और तेंदुओं की उपस्थिति पर प्रकाश डाला था। बढ़ती मांसाहारी आबादी का समर्थन करने के लिए शिकार आधार की मांग की गई थी। संघर्ष तब एक दुखद मोड़ पर पहुंच गया जब 2012 में, एक बाघ भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में भटक गया और ग्रामीणों द्वारा उसे बेरहमी से मार डाला गया। एनटीसीए ने तुरंत इस स्थिति का संज्ञान लिया, लेकिन राज्य द्वारा रिजर्व अधिसूचना को पूरा करने में विफलता ने इस क्षेत्र को असुरक्षित छोड़ दिया। इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए, मप्र के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने रिजर्व के प्रस्तावित बफर जोन में कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट, 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन और एक रेलवे लाइन शामिल हैं। ये मंजूरियां बाघों के आवास पर संभावित प्रभाव पर विचार किए बिना दी गई थीं। उच्च न्यायालय में दायर पीआईएल ने इन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अदालत से राज्य सरकार को तुरंत रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

● **विकास दुबे**

नए सिरे से बनेगा सीपीए का सेटअप

राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) का फिर से गठन होगा। सीपीए अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल से ही शुरू हो पाएगा। इसके पहले सीपीए का सेटअप नए सिरे से तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार से सीपीए के पुनर्गठन के लिए आर्थिक व तकनीकी सहयोग मांगा है। यानी नवगठित सीपीए की शहर के विकास में भूमिका बढ़ भी सकती है। उधर, राजधानी परियोजना प्रशासन की संपत्तियों का आधिपत्य लोक निर्माण विभाग के पास ही रहेगा। सीपीए की संपत्तियां नगरीय विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित नहीं की जाएंगी।

गौरतलब है कि राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग केपीएस राणा को राजधानी परियोजना का प्रशासक बनाकर उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही सीपीए में और नियुक्तियां की जाएंगी। पुराना सीपीए सड़कों के साथ सरकारी भवन और पार्कों के निर्माण व मेंटेनेंस का काम करता था। सीपीए ने राजधानी बनने के बाद सरकारी मकानों और मंत्रालय व अन्य भवनों का निर्माण किया था। अब सीपीए का काम और क्षेत्र क्या होगा इसका फिर से निर्धारण किया जाएगा। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 3 मार्च, 2022 को कैबिनेट ने सीपीए को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सीपीए में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल विभाग वापस लौटा दिया गया था। शहर की सड़क और भवनों के मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी और पार्कों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंप दिया गया था। सीपीए दोबारा चर्चा में तब आया, जब गत मार्च में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सीपीए को दोबारा चालू करने की मांग की। इसके बाद शासन ने सीपीए के पुनर्गठन की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गत् 4 जुलाई को विधानसभा को बताया था कि सरकार का सीपीए को फिर से शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

दरअसल, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मंशा थी कि सीपीए की संपत्तियां उसे हस्तांतरित कर दी जाएं। विभाग ने सितंबर में पीडब्ल्यूडी को फाइल भेजकर इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा था। इस संबंध में जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभागीय मंत्री राकेश सिंह से चर्चा की, तो उन्होंने दो टूक कहा था कि सीपीए किसी विभाग को नहीं सौंपा जाएगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने नगरीय विकास विभाग को इस पर अपना अभिमत देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि वह सीपीए की संपत्तियां हस्तांतरित नहीं करना चाहता। पीडब्ल्यूडी ने अपने अभिमत में कहा था कि विभाग का मूल काम सिविल वर्क से जुड़ा है। हमारे पास इस कार्य के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों का बड़ा अमला है। विभाग दो साल से ज्यादा समय से सीपीए की संपत्तियों का मेंटेनेंस भलीभांति कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के रुख को देखते हुए फिलहाल शासन ने सीपीए का आधिपत्य उससे वापस लेने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार करीब पौने साल पहले सीपीए को बंद करने के बाद इसकी संपत्तियां (सड़कों-बड़े सरकारी भवनों का मेंटेनेंस) लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं। गत् 30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर से सीपीए को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। अधिकारियों का कहना है, चूंकि सीपीए की संपत्तियां पीडब्ल्यूडी के आधिपत्य में हैं, इसलिए यदि इसकी संपत्तियां नगरीय विकास विभाग को हस्तांतरित करना है, तो पीडब्ल्यूडी की एनओसी जरूरी होगी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

यह था सीपीए का सेटअप

सीपीए के पुराने सेटअप में एक प्रशासक, एक उप प्रशासक और एक सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, तीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक डीएफओ के साथ उनके अधीनस्थ अन्य इंजीनियर, वन अधिकारी आदि कार्यरत थे। अब सीपीए का सेटअप दोबारा बनेगा। सीपीए के पास 92.5 किमी सड़कों का रखरखाव था। मंत्रालय सहित करीब 24 सरकारी भवनों का रखरखाव सीपीए कर रहा था। शहर के अलग-अलग इलाकों में हुए पौधरोपण और सीपीए द्वारा निर्मित बड़े पार्कों का रखरखाव भी सीपीए कर रहा था। अब इन संपत्तियों की स्थिति का दोबारा परीक्षण होगा। इनमें से कितना सीपीए को वापस मिलता है और कितना पीडब्ल्यूडी व वन विभाग के पास रह जाएगा, इस पर निर्णय करना होगा। सीपीए के पास मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, विधानसभा, विधायक विश्रामगृह, शहीद स्मारक, पर्यावास भवन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, आवास के मेंटेनेंस के अलावा भोपाल के प्रमुख मार्गों और पार्कों को संधारित करने का काम सीपीए के जिम्मे था। सीपीए यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का काम देख रहा था। इन कार्यों का बजट करोड़ों में है। मंत्रालय का रेनोवेशन 107 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को तोड़कर करोड़ों की लागत से नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी यह काम पीडब्ल्यूडी के जिम्मे हैं। सीपीए दोबारा चर्चा में तब आया, जब गत् मार्च में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सीपीए को दोबारा चालू करने की मांग की। इसके बाद शासन ने सीपीए के पुनर्गठन की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी।

मोहन 'राज' का एक साल
विकास-सुशासन का कमाल

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 13 दिसंबर को एक साल पूरा कर लिया। मप्र में 2003 से लेकर अब तक के मुख्यमंत्रियों के शासनकाल का आंकलन किया जाए तो एक साल में मोहन 'राज' (मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शासनकाल) में जितना नवाचार, विकास हुआ है और कानून व्यवस्था सुधरी है, उतना पहले कभी नहीं देखा गया। मोहन 'राज' के एक साल में विकास और सुशासन का कमाल देखने को मिला है।

● राजेंद्र आगाल

किसी भी सरकार के कामकाज का आंकलन करने के लिए 365 दिन यानी एक साल का अरसा काफी कम होता है। लेकिन मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने एक साल के कार्यकाल में विकास, विश्वास, सुशासन और प्रशासनिक क्षमता की मिसाल पेश की है जिसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। 13 दिसंबर 2024 को डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने एक साल पूरा हो गया है। ऐसे में उनके बारह महीनों पर एक नजर डालें तो हम पाते हैं कि इस दौरान सरकार ने उन मुद्दों पर अधिक फोकस किया है जिसकी जरूरत सबसे अधिक महसूस की जा रही थी। 2023 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था। जिसमें उन्होंने 100 प्रतिशत सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया।

मप्र में भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं देशभर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मप्र की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने जीत हासिल की।

चुनौतियों का डटकर किया सामना

डॉ. मोहन यादव ने मप्र के मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली, तो उनके नेतृत्व पर सवाल उठे। पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से उनकी तुलना की जाने लगी। मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान सरकार में तीन साल तक उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। चौहान के 16 साल से ज्यादा के शासन के मुकाबले ये अनुभव बहुत थोड़ा था। इसके बावजूद, भाजपा ने अपने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री को उज्जैन दक्षिण से तीन बार के विधायक से बदल दिया। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कृषि वित्तपोषण, सिंचाई और अन्य सहायक योजनाओं के माध्यम से मप्र को बीमारू राज्य से एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य में बदल दिया। उन्होंने सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का भी सराहनीय काम किया। हालांकि, वे औद्योगिकीकरण और शहरी विकास में पिछड़ गए। शिवराज सिंह चौहान ने इन दिशाओं में प्रयास तो किए, लेकिन 2018 में चुनाव हारने के बाद 15 महीने के अंतराल और फिर मार्च 2020 में शपथ लेने के बाद शुरू हुए कोविड-19 काल के कारण उनके प्रयासों का ज्यादा फल नहीं मिला। 11 दिसंबर 2024 को जब उनके नाम का ऐलान हुआ था, तब कई बुद्धिजीवियों का सवाल था कि लगभग 20 साल सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। लेकिन अपने एक साल के कार्यकाल में ही डॉ. मोहन यादव ने यह साबित कर दिया है कि आलाकमान ने जो फैसला लिया था वह सौ टका टंच था। चाहे शिवराज सिंह चौहान हों या उमा भारती, स्व. बाबूलाल गौर हों या कमलनाथ, सबको मात देकर डॉ. मोहन आगे निकल गए हैं। डॉ. मोहन यादव ने अपने एक साल के कार्यकाल में कई काम ऐसे किए हैं, जो उन्हें शिवराज सिंह चौहान से आगे लाकर खड़ा करते हैं। मसलन छिंदवाड़ा की सीट, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था लेकिन उनके कार्यकाल में जीत नहीं पाए। वहीं, जब कमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथ में आई तो उन्होंने 26 साल बाद कमलनाथ के अभेद किले को ढ़हा दिया। लगता है कि उन्होंने सरकार चलाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। वो उद्योग, शहरी विकास और राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला निर्णय ही बना मील का पत्थर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभार ग्रहण करने के बाद पहली नस्ती पर हस्ताक्षर कर ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित करने का फैसला किया था। इसमें धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानि लाउड स्पीकर, डीजे के उपयोग की बात थी। यह 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉ. मोहन यादव द्वारा हस्ताक्षरित पहली नस्ती थी, जिसने मोहन यादव की विशेष छवि बनाई है। तो 13 दिसंबर 2023 को ही खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक लगाने का दूसरा फैसला डॉ. मोहन यादव ने लिया था। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में 15 दिसंबर से विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया था। इन दोनों ही फैसलों में एक बेहतर मप्र और डॉ. मोहन यादव की बतौर मुख्यमंत्री एक विशेष छवि की झलक सभी ने देखी थी। हालांकि दोनों ही फैसलों को इस नजर से भी देखा गया था कि यह एक संप्रदाय विरोधी हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सभी धर्म के धार्मिक स्थलों पर होता है। तो मांस की खुले में बिक्री में भी सभी धर्म के लोग शामिल हैं। और जब इन फैसलों पर अमल हुआ, तब लोगों में फील गुड का भाव देखा गया था। पर यह सख्ती लगातार देखने को नहीं मिली, जिसका लोगों को इंतजार है। राज्य शासन के किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदंड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि का उपयोग करने के निर्णय पर सख्ती से अमल होना चाहिए। सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित हों और उनकी कार्यवाही भी सबको नजर आनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, नारी, किसानों और गरीबों के अभावग्रस्त जीवन के आर्थिक उन्नयन के साथ उनमें आत्मविश्वास भरने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मप्र सरकार इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिए ठोस पहल कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए 1 जनवरी से 4 नए मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों से उपेक्षा के शिकार रहे समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के जनवरी-2025 में मिशन मोड में प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में एक जनवरी 2025 से 4 मिशन- युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मप्र पहला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि युवा शक्ति मिशन में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में गरीब और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नारी सशक्तिकरण मिशन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएंगे। किसान कल्याण मिशन में किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ कृषि को और अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में

साढ़े 3 लाख करोड़ से अधिक राशि का लोक कल्याणकारी बजट पारित किया गया। सरकार ने तय किया है कि आने वाले वर्षों में बजट को दोगुना किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि मप्र को देश में अग्रणी राज्य बनाने में प्रदेश की जनता का विश्वास हमें संबल प्रदान करता है। हमारे साढ़े 8 करोड़ प्रदेशवासी मिलकर विकास की दिशा में जब काम करेंगे, तो विकास के नए आयाम प्रदेश में रचे जाएंगे। जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़े, नए मुख्यमंत्री ने वहीं से अपना काम शुरू किया।

बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान

मोहन सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में कई नवाचार और बदलाव किए। संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी थी तो चुनौतियां भी कम नहीं थीं। इन सबमें सरकार ने सबसे अधिक ध्यान बुनियादी सुविधाओं यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर दिया। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को सौंपी गई, तो गृह विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद अपने पास रखा, जिससे कानून-व्यवस्था पर उनका सीधा नियंत्रण रहे। तीनों विभागों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गई हैं। मप्र में अभी विकास लक्ष्य के अनुरूप बजट की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था तीनों को बेहतर करने के लिए मानव संसाधन की कमी दूर करना, सरकार के लिए सबसे बड़ा काम है। सरकार का सबसे बड़ा निर्णय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का रहा। प्रदेश में लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टरों की कमी है। विशेषज्ञों के 3725 स्वीकृत पदों में से 2374 रिक्त हैं। इसी तरह चिकित्सा अधिकारी के 5329 में से 1054 पद रिक्त हैं। इसी वर्ष सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के अस्पतालों में मानव संसाधन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के अनुसार होंगे। इसके लिए नियमित, संविदा और आउटसोर्स मिलाकर 46,491 पदों पर भर्ती प्रारंभ की गई है। इनमें 885 पद डॉक्टरों के भी हैं। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। इसी वर्ष तीन नए सरकारी कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। पीपीपी से 14 कॉलेज खोलने की तैयारी है। प्रयोग के तौर पर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया गया है। संभाग स्तर पर मेडिसिटी बनाने की योजना भी सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर के मामले में प्रदेश सबसे ऊपर है। इसमें कमी लाने की रूपरेखा भी बनी है।

कानून-व्यवस्था

पिछले एक वर्ष में डॉ. मोहन यादव की सरकार के कई निर्णय साबित करते हैं कि कानून-व्यवस्था उसकी बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है। प्रदेश में कई बड़ी कार्रवाई कर सरकार ने संदेश दिया है कि लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। छतरपुर में थाना घेरने वालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई इसका बड़ा उदाहरण है। कानून-व्यवस्था में ढिलाई करने वाले अधिकारियों को हटाने में भी देरी नहीं की गई। साथ ही पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए उनके कल्याण की गतिविधियां भी चर्चा में रहीं। अभी बड़ी चुनौती पुलिस में रिक्त पदों की पूर्ति और उसकी छवि साफ-सुथरी बनाना है। एक लाख 26 हजार स्वीकृत बल में लगभग एक लाख ही पदस्थ हैं। डॉ. मोहन यादव ने एडीजी स्तर के अधिकारियों को संभागों का प्रभारी बनाया। एक बड़ी पहल, लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इंदौर, भोपाल के बाद जबलपुर और ग्वालियर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने

तबादलों, बढ़ते अपराध के कारण भी चर्चा में सरकार

सरकार ने एक साल में न केवल पीएस लेवल के अधिकारियों के तबादले किए बल्कि मैदानी अमले को भी बदला। एक साल में 22 जिलों के कलेक्टर बदले गए। इनमें से सबसे ज्यादा 11 कलेक्टर्स के ट्रांसफर लोकसभा चुनाव से पहले किए गए। इनमें सीधी, उमरिया, रतलाम, झाबुआ, विदिशा, दमोह, ग्वालियर, गुना, पन्ना, शहडोल, सिंगरौली जिले के कलेक्टर शामिल हैं। हालांकि 33 जिलों के कलेक्टर नहीं बदले गए हैं। 6 जनवरी 2025 तक मतदाता सूची का काम पूरा होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद इन जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे। वैसे भी मुख्यमंत्री पिछले महीने हुई कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जनवरी तक सभी का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। जानकार भी मानते हैं कि नए मुख्य सचिव भी अपने हिसाब से मैदानी जमावट कर सकते हैं। कलेक्टर्स के साथ जिलों के एसपी भी बदले गए। फरवरी और मार्च में 15 जिलों के एसपी के ट्रांसफर हुए। इनमें जनवरी में हरदा, बैतूल, दतिया, उज्जैन, नीमच, झाबुआ व दतिया और फरवरी में ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, अशोकनगर, खंडवा, शिवपुरी, खरगोन और राजगढ़ के एसपी बदले गए। इनमें से 4 जिले सिंगरौली, निवाड़ी, श्योपुर और डिंडौरी में 6-6 महीने में एसपी के दो बार ट्रांसफर किए गए। जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री इन जिलों के एसपी की कार्यप्रणाली से नाखुश थे। पुलिस अफसरों के ट्रांसफर करने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड बना है। यह बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2007 को आदेश जारी किया था। इस बोर्ड की अनुशंसा पर सरकार पुलिस अफसरों के ट्रांसफर करती है। बोर्ड में डीजीपी के अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसएएफ, गुप्त वार्ता, सीआईडी और प्रशासन सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर के लिए सरकार को बोर्ड की अनुशंसा को प्राथमिकता देना होगी। लेकिन सरकार को इसमें बदलाव करने का अधिकार हैं। पुलिस मुख्यालय एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव को भेजता है। सीएस उसे गृह विभाग में भेजते हैं। इसके बाद पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक होती है। इसकी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाता है। तब मुख्यमंत्री डीजीपी से चर्चा करते हैं। इसके बाद गृह विभाग आदेश जारी करता है। पीएचक्यू सूत्रों ने बताया कि आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना के लिए डीजीपी लिस्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं।

की तैयारी चल रही है। प्रदेश के तीन जिले बालाघाट, मंडला और डिंडौरी नक्सल प्रभावित हैं। इन जिलों में लगभग 75 नक्सली हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से नक्सली समस्या खत्म करने का लक्ष्य पुलिस को दिया है। इसके लिए अतिरिक्त बल स्वीकृत किया गया है। केंद्र से सीआरपीएफ की दो कंपनियां मांगी हैं।

शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री बनते ही डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा पर अधिक फोकस किया। मप्र के 55 कॉलेजों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की सबसे बड़ी पहल रही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवाचार करते हुए कुलपति को कुलगुरु नाम दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की जगह चार वर्ष का स्नातक (ऑनर्स) पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रदेश के शासकीय कालेजों में पांच हजार से अधिक और स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 80 हजार पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की है। इसके लिए सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। पहले चरण में 275 स्कूलों को सीएम राइज बनाया जा रहा है। प्रदेश के 400 से अधिक सरकारी स्कूलों का पीएमश्री स्कूल के रूप में चयन किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है। शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है।

हर कोने में कौशल की रौशनी

मप्र के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कौशल विकास के क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने बीते वर्ष कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयां छुई हैं। यह केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि हर युवा को रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का अभियान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के उन 22 विकासखंडों में आईटीआई की स्थापना हुई, जहां पहले कोई सुविधा नहीं थी। इससे न केवल प्रदेश के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिला, बल्कि उनके रोजगार के अवसर भी बढ़े। अब प्रदेश में शासकीय आईटीआई की संख्या 290 हो गई है, जो मुख्यमंत्री की शिक्षा और रोजगार के प्रति दूरदर्शिता को दर्शाता है। बदलते समय और बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन और फूड प्रोडक्शन जैसे नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्ष बना रहे हैं और उन्हें उद्योगों में सीधा प्रवेश दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पर्यावरण-अनुकूल दृष्टि के तहत देवास, धार और छिंदवाड़ा की आईटीआई को ग्रीन स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया गया। यहां युवा सोलर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। डॉ. मोहन ने यह सुनिश्चित किया कि कौशल विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार भी प्रदान करे। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना राज्य सरकार के उस विजन का प्रतीक है, जिसमें हर युवा को रोजगार के साथ व्यावसायिक अनुभव देने की योजना है। इस वर्ष 24 हजार से अधिक प्रतिष्ठानों ने योजना में भाग लिया और 22 हजार से अधिक युवाओं ने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह योजना युवाओं को न केवल आय का स्रोत प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें उद्योग के लिए तैयार भी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से प्रदेश में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी जैसे उन्नत कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। यह पहल प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मप्र में हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मप्र में हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन हो रहे हैं। उज्जैन के क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। यह बहुत बड़ी सफलता थी। जबलपुर में 17,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। इनमें से 5,000 करोड़ रुपए एमएसएमई से थे। इसी तरह ग्वालियर के सम्मेलन से 1.84 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। सागर से 23,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। इनमें डेटा सेंटर और स्टील प्लांट शामिल थे। रीवा का सम्मेलन भी सफल रहा। अक्टूबर में वहां 31,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेश लाने के लिए कई देश गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने निवेश पर फोकस किया है। हाल ही में यूके से उन्हें 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। शहरों के विकास में समय लगता है लेकिन मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी है। इंदौर और भोपाल में अभी मेट्रो नहीं है। शायद भोपाल में 2025 से मेट्रो शुरू हो जाए। इसके प्रयास भी तेजी से चल रहे हैं। इंदौर में नया बीआरटीएस बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल को महानगर बनाना चाहते हैं। वो दिल्ली-एनसीआर की तरह भोपाल को स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। मप्र में चिकित्सा शिक्षा की कमी भी एक चुनौती है। उप्र और राजस्थान में लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। मप्र में सिर्फ 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इसी तरह सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। लेकिन अभी तक विज्ञापनों के अलावा इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

438 अफसरों के तबादले

विकास और सुशासन के साथ ही मोहन सरकार का एक साल तबादलों और अपराध के लिए भी चर्चा में रहा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दो-ढाई महीनों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10 महीने में सरकार ने 79 फीसदी आईएएस और 73 फीसदी आईपीएस समेत कुल 438 अफसरों के तबादले किए हैं। इन तबादलों में 22 जिलों के कलेक्टर और 39 जिलों के

एसपी बदले गए हैं। खास बात ये है इनमें 109 अफसरों के तबादलों की 6 लिस्ट आधी रात को जारी की गई। इसके अलावा कई विभाग ऐसे हैं जहां 2 से 3 बार अफसरों की नियुक्ति की गई है। जानकारों का कहना है कि अफसरों का बार-बार तबादला करना अच्छी प्रक्रिया नहीं है। इससे न तो अधिकारियों की जवाबदेही तय हो पाती है और न ही उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है।

सरकार के एक साल पूरे होने से चार दिन पहले 8 दिसंबर को मोहन सरकार ने 15 आईएएस के ट्रांसफर किए। सरकार ने वरिष्ठ अफसर एसीएस केसी गुप्ता को पीडब्ल्यूडी से हटाकर राज्यपाल का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया। पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त प्रभार एसीएस ऊर्जा नीरज मंडलोई को दिया गया। राजभवन के पीएस मुकेश चंद्र गुप्ता को मानव अधिकार आयोग के सचिव के रूप में पोस्टिंग दी गई। एसीएस अनुपम राजन को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संसदीय कार्य विभाग दिया गया। वहीं रिटायर्ड आईएएस गोपाल चंद्र डांड को 1 साल के लिए सीएम सचिवालय में संविदा नियुक्ति दी गई। पिछले एक साल में पीडब्ल्यूडी को 3 अलग-अलग मुखिया मिल चुके हैं। सरकार बनने के बाद सुखबीर सिंह को (7 नंवबर 2023) पीडब्ल्यूडी का प्रमुख सचिव बनाया गया था, लेकिन वे 82 दिन ही रह पाए। उन्हें 28 जनवरी 2023 को हटाकर डीपी आहूजा की पोस्टिंग की गई। आहूजा भी छह महीने ही पदस्थ रह पाए। अगस्त में केसी गुप्ता को उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर पीडब्ल्यूडी की कमान सौंपी गई, लेकिन चार महीने में ही उन्हें राजभवन भेज दिया गया। जबकि एक आईएएस अफसर नियाज खान को इस विभाग में बतौर उप सचिव 5 साल चार महीने हो गए हैं। खान को अगस्त 2019 में पीडब्ल्यूडी में पदस्थ किया गया था। तब वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। दिसंबर 2022 में वे आईएएस प्रमोट हो गए। इसके बाद भी उन्हें अब तक इसी विभाग में रखा गया है। शायद वे एकमात्र आईएएस अफसर हैं, जो एक ही विभाग में इतने लंबे समय से पदस्थ हैं।

पीडब्ल्यूडी की तरह खनिज भी सरकार की प्राथमिकता वाला विभाग माना जाता है। यहां भी एक साल में तीन प्रमुख सचिव बदल गए।

शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले (10 मई 2023) इस विभाग की कमान राघवेंद्र सिंह को सौंपी थी, लेकिन नई सरकार आने के दो दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया। उनकी जगह निकुंज श्रीवास्तव को यहां पदस्थ किया गया, लेकिन वे चार महीने ही यहां रह पाए और उनके स्थान पर संजय शुक्ला की पोस्टिंग की गई। शुक्ला को चार महीने में ही हटाकर नवंबर में उमाकांत उमराव की यहां पोस्टिंग की गई है। वहीं राजभवन में भी एक साल में तीन प्रमुख सचिवों को बदला गया है। यहां पहली बार अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग की गई है। शिवराज सरकार ने जुलाई 2020 में डीपी आहूजा को राजभवन में पदस्थ किया था। वे यहां करीब साढ़े तीन साल रहे। मोहन सरकार के सत्ता में आने के दो महीने बाद जनवरी में आहूजा की जगह संजय शुक्ला को बतौर प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया, जबकि आहूजा को पीडब्ल्यूडी की कमान सौंपी गई। संजय शुक्ला राजभवन में दो महीने भी पदस्थ नहीं रह पाए। उनकी जगह मुकेश चंद्र गुप्ता को राजभवन भेजा गया। लेकिन एक सप्ताह पहले ही पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता की राजभवन में पोस्टिंग की गई। इसी तरह ऊर्जा विभाग में भी नई सरकार बनने के बाद तीन बार प्रमुख सचिव बदले जा चुके हैं। नई सरकार के गठन से पहले संजय दुबे इसके प्रमुख सचिव थे। 28 जनवरी को उनकी जगह मनु श्रीवास्तव को पीएस का जिम्मा सौंपा गया। सरकार के एक साल पूरे होने के 4 दिन पहले मनु श्रीवास्तव को हटा कर नीरज मंडलोई को ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसी तरह एमएसएमई विभाग में पी नरहरि तीन साल तक प्रमुख सचिव रहे। उनका 14 मार्च 2024 को ट्रांसफर किया गया। उनकी जगह नवनीत कोठारी को जिम्मेदारी दी गई, मगर कोठारी केवल 8 महीने विभाग में रहे उसके बाद 13 नवंबर को राघवेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई।

जानकार कहते हैं कि एक ही विभाग में अफसरों के ट्रांसफर से उस विभाग के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। मप्र सरकार के अफसर ये शुरू से शिकायत करते रहे हैं कि अफसरों को जमने का, उन्हें काम देखने का मौका नहीं मिलता, उससे पहले उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। सरकार अफसरों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पर भेजती है। इस पर जनता के पैसों की बरबादी होती है, क्योंकि जब अफसर ट्रेनिंग से लौटते हैं तो वो उस विभाग में ट्रेनिंग में सीखे हुए काम को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। हर काम में स्थिरता जरूरी होती है। इससे काम पर भी प्रभाव पड़ता है।

आगामी वर्षों के लिए भी मप्र का रोडमैप

विकसित भारत के सपनों को पूरा करने, विकसित मप्र के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया जाएगा। 1 लाख 25 हजार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले कृषकों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किए जाएंगे। अगले चार वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं। अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना (1 करोड़ हेक्टेयर) किया जाएगा। वर्तमान में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं तथा 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पीपीपी मोड पर 12 और 8 शासकीय मेडिकल कॉलेज चालू किए जाएंगे। वर्ष-2025 को उद्योग एवं रोजगार-वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जिसमें युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ स्वरोजगार से जोड़ने का वृहद स्तर पर कार्य होगा। एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भौपाल-सीहोर रायसेन विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा। श्रीराम-वन-पथ-गमन तथा श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण किया जाएगा। 10 दुधारू पशु पालने पर अनुदान तथा दुग्ध उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा।

कांग्रेस का दिग्गजों पर दांव

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपने-अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने गत दिनों दिल्ली की 21 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की। कांग्रेस ने अपने पहले ही कदम से सियासी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज और अनुभवी नेताओं को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारा है, उससे एक तरफ मुकाबला रोचक बनता दिख रहा तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सियासी टेंशन भी बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के दांव से किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है?

दिल्ली न्याय यात्रा के बहाने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद कांग्रेस ने अब अपने सिपाहसलारों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा नाम दिग्गज नेताओं के हैं, जो पहले दिल्ली में विधायक या फिर सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में तीन मुस्लिम और दो महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सियासी और जातीय समीकरण के लिहाज से पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, सिख, पंजाबी और ओबीसी समुदाय पर भरोसा जताया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा है। इस सीट से संदीप दीक्षित की मां और दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित तीन बार विधायक चुनी गई थीं। केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को शिकस्त देकर अपनी सियासी पारी का आगाज किया था और पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने से नई दिल्ली सीट का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। संदीप दीक्षित शुरू से ही केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरे रहे हैं। अगर केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस-आप की लड़ाई आर-पार की होगी। इस तरह कांग्रेस ने केजरीवाल को उनकी ही सीट तक सीमित रखने का दांव चला है। संदीप दीक्षित ही नहीं कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने अनुभवी चेहरों को उतारा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली सीट से किस्मत आजमाने उतरे हैं। पटपड़गंज सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी अनिल कुमार एक बार फिर ताल ठोंकेंगे। इसके अलावा शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हारून युसूफ को उनकी परंपरागत सीट बल्लीमरान से उतारा गया है। युसूफ इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और अब फिर से किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। सुल्तानपुर माजरा सीट से कांग्रेस ने जय किशन को उतारा है, जो पार्टी के दिल्ली में दलित चेहरा माने जाते हैं। साल 2013 में केजरीवाल के सियासी लहर में कांग्रेस के जो चुनिंदा नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, उसमें जय किशन का नाम भी शामिल था। आप के मुकेश अहलावत फिलहाल यहां से विधायक हैं। कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को प्रत्याशी बनाया है, जो एमसीडी में पार्षद रहे हैं और छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आए हैं। वह दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज और युवा नेता माने जाते हैं। पंजाबी वोटर पर अच्छी पकड़ है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे हैं। चांदनी चौक सीट पर आप ने मौजूदा विधायक प्रहलाद साहनी के बेटे पुनरदीप सिंह साहनी को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह चांदनी चौक सीट पर दो दिग्गज नेताओं के बीच इस बार मुकाबला होने जा रहा है। इसी तरह मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक अहमद हसन के बेटे अली मेहंदी को प्रत्याशी बनाया है, जहां पर आप ने अपने विधायक का टिकट काटकर आदिल खान को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उतार रखा है। कांग्रेस ने वजीरपुर सीट से अपनी तेज तर्रार प्रवक्ता रागिनी नायक को प्रत्याशी बनाया है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रसंघ की अध्यक्ष रही हैं। वो कांग्रेस के गुर्जर चेहरा अशोक बसोया की पत्नी भी हैं। अशोक बसोया भी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह कांग्रेस ने वजीरपुर सीट पर मुस्लिम-गुर्जर और ब्राह्मण समीकरण बनाने के लिहाज से रागिनी नायक को उतारा है। इसी तरह सदर बाजार से कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज को खड़ा किया है। कांग्रेस ने दो दिन पहले पार्टी में शामिल हुए सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान को सीलमपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है।

आम आदमी पार्टी ने इस बार तीन बार के विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद के बेटे जुबेर अहमद को टिकट दिया है। कांग्रेस ने द्वारका सीट पर आप से विधायक रह चुके आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है। इसके अलावा बुराड़ी सीट से मंगेश त्यागी, नरेला सीट से अरुणा कुमारी, आदर्श नगर से शिवांक सिंघल, नांगलोई जाट सीट से रोहित चौधरी, शालीमारबाग से प्रवीण जैन, तिलक नगर से पीएस बावा, छतरपुर से राजिंदर तंवर, अंबेडकर नगर से जयप्रकाश और ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है।

● **रजनीकांत पारे**

कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट के सियासी मिजाज और जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने तीन मुस्लिम, दो महिला को टिकट दिया है, लेकिन जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो पांच ब्राह्मण और एक पंजाबी ब्राह्मण समाज पर दांव लगाया है। ऐसे ही कांग्रेस ने दो गुर्जर, दो जाट और एक कायस्थ को प्रत्याशी बनाया है। इतना ही नहीं कांग्रेस ने वैश्य समुदाय से तीन प्रत्याशी उतारे हैं तो दलित समुदाय के दो नेताओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जैन और सिख समुदाय से एक-एक प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपने संजीदा और अनुभवी नेताओं को उतारा है, उसके चलते कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल तीन सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन ओखला और मटियामहल सीट पर सस्पेंस बनाए रखा। कांग्रेस ने जिन 3 सीटों पर मुस्लिम को टिकट दिया है, उन पर आम आदमी पार्टी से मुस्लिम ही कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से लेकर चांदनी चौक, बादली और वजीरपुर तक की सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है।

दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही अभी चुनाव आयोग ने कोई घोषणा न की हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से चुनावी घोषणाएं करने लगे हैं। हर राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर दिल्ली जीतना चाहता है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा की सुविधा को जारी रखा जाएगा। इसमें अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी बड़ी चुनावी घोषणा की है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही दिल्ली वालों को 400 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे।

अब दिल्ली फतह की जंग

दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने हाल में कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। केजरीवाल के इस बयान से साफ है कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय हो चुका है। इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों को छोड़कर, जब आप और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था और दोनों को मिलकर वोटर शेयर 43.1 प्रतिशत था। दोनों पार्टियों ने समान वोटबैंक होने के बावजूद हमेशा अलग-अलग विधानसभा चुनाव लड़ा है। हालांकि, 2013 में अपने पहले चुनाव के बाद से आप का वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा। जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या में काफी कमी आई है।

भाजपा को हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनावों तक शहर में आखिरी बार सरकार बनाई थी। कांग्रेस गरीबों, दलितों और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती थी। आम आदमी पार्टी ने 2013 में अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ, कुल मतदान का 29 प्रतिशत वोट प्राप्त किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आप ने कांग्रेस के वोटबैंक में सेंध लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5 प्रतिशत पर आ गया था और पार्टी सिर्फ आठ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर क्रमश: 9.7 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत तक गिर गया। वहीं, आप ने 54.6 प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भारी जनादेश हासिल किया।

राजनीति के जानकार भी आप के तर्क से सहमत हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रवि रंजन ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से आप को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रंजन ने कहा कि अब राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप उन राज्यों पर गठबंधन नहीं करना चाहेगी जहां वे राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। रवि रंजन के अनुसार अगर कांग्रेस और आप साथ नहीं भी होते हैं, तो भी भाजपा के लिए यह चुनाव मुश्किल होगा, क्योंकि आप अभी भी निम्न-मध्यम वर्ग और झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में काफी लोकप्रिय है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बार नई रणनीति के साथ दिल्ली की सत्ता फतह करने की रणनीति बनाई है। मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा के बजाय दिल्ली की सुरक्षा के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करना शुरू

2024 चुनाव में 52 सीटों पर भाजपा को बढ़त

वैसे तो आप और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा के उम्मीदवार सात संसदीय क्षेत्रों के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 52 पर आगे रहे हैं। वहीं, आप-कांग्रेस संयुक्त रूप से शेष 18 पर आगे हैं। हालांकि भाजपा ने 2020 के विधानसभा चुनावों के अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, लेकिन अगर 2019 के लोकसभा चुनावों से तुलना की जाए तो यह इंडिया गठबंधन के सामने बहुत पीछे रह गई है। उस समय भगवा पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबले में 65 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, उनमें अल्पसंख्यक समुदायों की अच्छी खासी आबादी थी। हालांकि, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल करने में विफल रही, लेकिन इसके उम्मीदवार 22 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि, एक साल बाद कहानी पूरी तरह बदल गई जब आप ने 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। भाजपा आठ सीटों पर विजयी हुई, जबकि कांग्रेस अपना खाता खोलने में विफल रही।

कर दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। आंकड़ों के जरिए केजरीवाल यह बताने में जुटे हैं कि दिल्ली अब महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिक तक के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। इस तरह भाजपा की सबसे कमजोर नस पर केजरीवाल हाथ रख रहे हैं।

अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद से ही केजरीवाल ने पूरी तरह से चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। दिल्ली के जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी कमजोर लग रही है, वहां दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को अपने साथ मिलाने का काम किया जा रहा है। मुफ्ती योजनाओं पर रेवड़ी चर्चा अभियान शुरू किया, लेकिन अब उसकी जगह पर दिल्ली की सुरक्षा को केजरीवाल ने सबसे अहम बना लिया है क्योंकि इस दांव से उन्हें सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने की उम्मीद दिख रही है। दिल्ली में चुनावी तपिश के बीच राजधानी में आपराधिक वारदात बढ़ी हैं। दिल्ली में आए दिन गैंगवार हो रहा है, रंगदारी वसूलने के मामले भी बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस लोगों के निशाने पर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बार-बार कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह और भाजपा ने पूरी दिल्ली को गुंडे और गैंगस्टर के हवाले छोड़ दिया है। इतना ही नहीं दिल्ली में जिन लोगों के साथ वारदात हो रही हैं, उनके परिवार से मिलने भी केजरीवाल पहुंच रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों दिल्ली के नारायणा में मारे गए युवक के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से उनका दर्द बांटा, फिर घर से बाहर निकलते ही भाजपा पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले ऐसा नहीं होता था, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार और पुलिस, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दे। हद है कि आरोपियों पर कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि गैंगस्टर्स के नाम सबको पता हैं। केजरीवाल खुद भी बिगड़ती कानून व्यवस्था का शिकार हुए, दिल्ली में पदयात्रा के दौरान उन पर हमले हुए हैं। केजरीवाल पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी यह बताने में जुटी है कि दिल्ली में राजनेता भी सुरक्षित नहीं, तो फिर आम आदमी की कौन बात करे। दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय संभालता है। केंद्र में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथों में है। पिछले 10 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस तरह दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर केजरीवाल ने सीधे भाजपा और अमित शाह को घेरने का प्लान बनाया है। इसके बहाने ये बताने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली के आवाम की सुरक्षा करने में मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। दिल्ली में बढ़ता अपराध और असुरक्षा पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बन चुका है।

आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ऐसे ही दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा नहीं बना रहे हैं बल्कि उसके पीछे की पूरी गणित है। दिल्ली में गैंगवार की छह बड़ी घटनाएं घटी हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में हर दिन 23 बच्चे, 40 महिलाएं और तीन सीनियर सिटीजन के खिलाफ अपराधिक मामले हो रहे हैं। दिल्ली में हर दिन औसतन एक हजार से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हर दिन औसतन तीन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इन आपराधिक आंकड़ों के जरिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को सियासी हथियार के तौर पर भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, उससे यह तय हो गया था। इसके बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था से पीड़ित लोगों और उनके परिवार से मुलाकात कर सियासी एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। इस तरह भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ बना रही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के बजाय अब दिल्ली कानून व्यवस्था पर सफाई देना शुरू कर दिया है। केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उनके सत्ता में वापसी के लिए अहम दांव साबित हो सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल खुलकर दांव खेल रहे हैं, लेकिन देखना है कि राजनीतिक नफा और नुकसान किसे होता है?

● **विपिन कंधारी**

कांग्रेस के वोटबैंक पर आप की जमीन

राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार आप ने खुद को मुख्य रूप से कांग्रेस और आंशिक रूप से भाजपा के वोटबैंक पर खड़ा किया है। अगर कांग्रेस और कमजोर होती है, तो इससे भाजपा और आप दोनों को ही फायदा होगा। हालांकि, कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ चुनावों की तुलना में दिल्ली में कांग्रेस अधिक मजबूत थी। आप के साथ गठजोड़ करने से वह बिहार और उप्र की तरह गठबंधन में जूनियर पार्टनर बन जाती। पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि एक स्वतंत्र राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में, कांग्रेस के फिर से उभरने और कुछ सीटें जीतने की संभावना अधिक है। गठबंधन ने दिल्ली में हमें पूरी तरह से खत्म कर दिया होता। आप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में हाथ मिलाने का विचार कभी भी पार्टी के विचार-विमर्श मंच पर नहीं था। आप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल का जवाब अचानक आया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी पार्टी ने राज्य चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कभी कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल की है। हमारे आंतरिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हम इस चुनाव में भी आसानी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हम किसी अन्य पार्टी को जगह क्यों देंगे? पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के विपरीत, जहां वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन समय की जरूरत थी, आप को विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का शहर में अपना वोट आधार बरकरार नहीं है। हम अपने दम पर भाजपा को हराने में सक्षम हैं। कांग्रेस का समर्थन करके, हमें पार्टी को अपना आधार फिर से बनाने में मदद क्यों करनी चाहिए?

कांग्रेस क्यों हारती है...?

दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। अरविंद केजरीवाल घर-घर पहुंच रहे हैं। अभी भी कांग्रेस दिल्ली में बहुत मजबूत है। यहां कोशिश करके सफलता हासिल की जा सकती है। पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के चुनावों के बजाय उप्र पर फोकस बनाए हुए है। दिल्ली की स्थानीय इकाई ने न्याय यात्रा निकाली हुई है, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

लोकसभा चुनावों में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस आश्वस्त थी कि अब नरेंद्र मोदी का करिश्मा मद्धिम पड़ गया है। साथ ही, हरियाणा में दस साल तक चली भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाओं की वजह से इस राज्य में चुनाव महज औपचारिकता है और उसकी सरकार बनना तय है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उम्मीदें धराशायी हो गईं तो इसके पीछे वजह है। पिछले दस साल में बुरी तरह कमजोर हो चुकी कांग्रेस के आलाकमान का इकबाल अब खत्म हो चुका है। राज्यों में क्षत्रप इसे आंख दिखाने से नहीं चूकते और अक्सर आलाकमान घुटने टेकने की मुद्रा में आ जाता है। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में सारे टिकट भूपिंदर सिंह हुड्डा के वफादारों के खाते में गए और बाकी दूसरे नेता नाराजगी में घर बैठ गए। जातीय समीकरणों पर भी इसका बुरा असर पड़ा और आखिर में नतीजे आए तो भाजपा ने इतिहास बनाते हुए हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। लेकिन जैसा कि पिछले 10 वर्षों से हमेशा होता आया है, कांग्रेस ने हार पर आत्ममंथन के बजाय इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। उसके प्रतिनिधिमंडल ने 20 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को 26 शिकायतों का पुलिंदा थमाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि उसकी हार कहीं न कहीं चुनावी हेराफेरी का परिणाम है न कि पार्टी में जारी गुटबाजी और सिरफुटौवल का। कांग्रेसी प्रचार तंत्र ने मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया मंचों तक जोर-शोर से ईवीएम की भूमिका को संदिग्ध ठहराने के लिए जोर-शोर से दुष्प्रचार शुरू कर दिया। ईवीएम की बैटरी को लेकर तमाम आरोप लगाए गए।

हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार के असल कारणों का हल ढूंढ़ने के बजाय कांग्रेस ने ईवीएम को दोषी ठहराकर अपनी लाज तो बचा लेती है पर आगामी चुनावों के लिए तैयार नहीं हो पाती है। अगर पार्टी हार के असल कारणों पर गंभीर होती तो अगले चुनावों में फिर वही गलतियां नहीं दोहराती जो पिछले चुनावों में पार्टी ने की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन तक कई सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) आपस में कैंडिडेट तय नहीं कर सके थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि एक दिन राहुल गांधी हरियाणा चुनावों की तरह कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। आनन-फानन में कांग्रेस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में लग जाएगी। नामांकन भरने के अंतिम दिन तक पार्टी के प्रत्याशी तय होंगे। पार्टी समय पर मेहनत करेगी नहीं और घर बैठे चुनाव जीत लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, इंडिया गठबंधन के दलों को भी मेहनत करते देखते हुए कांग्रेस नेताओं को कभी जीत के लिए कुछ करने की प्रेरणा शायद नहीं मिलती है। आइए देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को किस तरह हाईकमान लीस्ट प्रॉयोरिटी में अभी रखा हुआ है।

दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली में अपनी खोई हुई पकड़ को दोबारा पाने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुहिम दिल्ली न्याय यात्रा,

संगठन में बदलाव?

कांग्रेस में बड़े पैमाने पर बदलाव होना है, लेकिन अलग-अलग वजहों से ये बड़े बदलाव नहीं हो पा रहे। चर्चा है कि इन चुनावों के बाद संगठन महासचिव से लेकर मीडिया तक में बदलाव होने हैं। हालांकि बदलाव की बात काफी समय से हो रही है, लेकिन उस पर अमल को लगातार टाला जा रहा। आने वाले समय में पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी की भूमिका में बदलाव होना है। वह महासचिव हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रभार नहीं है। चर्चा है कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कई राज्यों में प्रभारी से लेकर अध्यक्ष पद पर भी बदलाव होना है। कांग्रेस की मंशा हार के कारणों पर किसी तरह लीपापोती की है। लोग पार्टी की नीतियों को स्वीकार नहीं कर रहे, पार्टी के नेता अलोकप्रिय हैं या गुटबाजी और क्षत्रपों की लड़ाई की वजह से पार्टी हार रही है, कांग्रेस इस पर मंथन और सार्वजनिक बहस से बचना चाहती है। कांग्रेस या किसी भी वंशवादी पार्टी के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि परिवार का वारिस राजनीतिक अखाड़े में चारों खाने चित हो रहा है। लिहाजा उसे चुनाव आयोग से कुश्ती लड़ना एक बेहतर विकल्प लग रहा है। लेकिन आत्ममंथन से बचने की यह कवायद पार्टी के लिए और भारी पड़ेगी।

जिसे एक महीने पहले लॉन्च किया गया था, कठिनाइयों का सामना कर रही है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में एक भी सीट जीतने में विफल रही कांग्रेस के लिए यह यात्रा एक बड़ा प्रयास था। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की यात्रा के शुभारंभ में उपस्थिति ने इसे शुरुआती गति दी थी, लेकिन इसके बाद से वरिष्ठ नेतृत्व की अनुपस्थिति ने इस अभियान की गति धीमी कर दी है। डीपीसीसी के नेताओं ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कई प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया था। इसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, और पूर्वांचली, जाट, मुस्लिम और दलित समुदाय के प्रभावशाली नेताओं को शामिल होने का बुलावा भेजा गया था। लेकिन किसी को भी इस यात्रा में आने की दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित हो रही यात्रा अब अपने चौथे और अंतिम चरण में है। कहा जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ दिनों में इसमें शामिल होने वाले हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा सांसद, और दिल्ली-एनसीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम रही। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के विस्तार के रूप में अकेले यह यात्रा आयोजित की है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी घर-घर घूम रही है। चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। पर वो किसी भी दूसरे प्रदेश में अपने को जाया न करके दिल्ली की गलियों की खाक छान रहे हैं। और दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस ने अपने आप को राज्य में पुनर्जीवित करने के लिए एक यात्रा शुरू की तो उसे पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट मिलना चाहिए था पर गांधी फैमिली भी नहीं आई इसलिए दूसरे और तीसरी श्रेणी के नेताओं के पास भी इस यात्रा के लिए समय नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कल्याण कैसे हो सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली में इस यात्रा को समय देना चाहिए था तो वो उप्र में जहां पार्टी उपचुनाव लड़ने तक की ताकत नहीं रखती, वहां समय जाया कर रहे हैं। बाद में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाएंगे तो कांग्रेसी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे।

हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार पर कांग्रेस कार्यसमिति में गंभीर चर्चा हुई है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन प्रदेशों में हार का ठीकरा राज्य की इकाइयों पर फोड़ दिया। राज्य की इकाइयों को मौके पर सहयोग मिलेगा नहीं और शीर्ष नेतृत्व हार का ठीकरा स्थानीय नेतृत्व पर थोपा जाएगा। एक-एक टिकट फाइनल करने की अथॉरिटी कांग्रेस में हाईकमान करती है, सारी प्लानिंग, कैंपनिंग आदि केंद्रीय नेतृत्व का दखल होता है और हारने पर जिम्मेदारी ली नहीं जाती है। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आखिर कब तक राज्यों के नेता राष्ट्रीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते रहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सलाह देने से पहले कोशिश ये करनी होगी कि कांग्रेस एजेंडा सेट करे और भाजपा को भी स्थानीय मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए घसीट लाए। जहां तक स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व खड़ा करने की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार उत्तम हैं। पर जब उन्हें सहयोग नहीं मिलेगा तो स्थानीय नेतृत्व पैदा होने से पहले मर जाएगा। दिल्ली में स्थानीय इकाई ने आगे बढ़कर कुछ किया तो उसे कहीं से समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। नामांकन दाखिल होने के दिन तक टिकट बांटे जाएंगे, सीट शेयरिंग पर बात होती रहेगी तो स्थानीय नेतृत्व क्या कर लेगी।

महाराष्ट्र में नतीजे आते ही पार्टी के भीतर आरोप-प्रत्यारोप और खींचतान शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य में अपनी हार के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा। उनका कहना था कि हमारी तो लीडरशिप ही खराब है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जहां भाजपा और उनके सहयोगियों ने जी-जीन लगा दिया, वहीं इतने अहम राज्य के बावजूद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और लीडरशिप प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वायनाड में डेरा डाले नजर आए। यही वजह थी कि बड़े नेता यहां तक कि राहुल गांधी भी जमीन पर इस बार वैसा कनेक्ट नहीं बना पाए, जैसा उन्होंने लोकसभा या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनाया था।

● इन्द्र कुमार

हार का ठीकरा ईवीएम पर

कांग्रेस आश्वस्त थी कि चुनाव आयोग उसके आरोपों की अनदेखी कर देगा लेकिन ब्यौरेवार जवाबों के साथ उसे तीखी टिप्पणियों की उम्मीद नहीं थी। पार्टी ने तत्काल हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। हम आमतौर पर इसे वहीं रहने देते लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का लहजा, भाव और इस्तेमाल की गई भाषा अहंकारी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को लगभग धमकी देते हुए कहा कि वह उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। इस प्रकरण में कांग्रेस का जवाब गौर करने लायक है। कांग्रेस ने अपने जवाब में कहा कि वह मामले को यहीं तक रहने देती अगर आयोग ने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणियां नहीं की होती तो। यानी यह एक तरह से आयोग के ब्यौरेवार जवाबों का स्वीकार है। लेकिन विचारणीय यह है कि आयोग को इतनी तीखी टिप्पणियां करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कांग्रेस हर हार के बाद ईवीएम पर हमलावर हो जाती है और अगर कहीं जीत गई तो ईवीएम निष्पक्ष हो जाती है। आमतौर पर पार्टी का रुख चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को संदेह के दायरे में घसीटने का रहा है। यहां तक कि अभी सितंबर महीने में ही अपने अमेरिका दौरे में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में हाल में हुए लोकसभा चुनाव स्वतंत्र नहीं बल्कि पूरी तरह से नियंत्रित थे। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो भाजपा किसी भी हाल में 240 सीटों तक नहीं पहुंच सकती थी और चुनाव आयोग वही कर रहा था जो सत्तारूढ़ दल चाहता था।

विष्णु के विरोधी भी हुए मुरीद...

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है। सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। वहीं, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी को भी पूरा करने में फोकस किया गया है। आइए जानते हैं एक साल के कार्यकाल में विष्णुदेव साय की सरकार ने कौन से 10 बड़े फैसले लिए हैं।

छत्तीसगढ़ की सियासत में किसान एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने धान किसानों से किया वादा पूरा किया। राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी हो रही है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के दो सालों के बकाया बोनस का भी भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में गेमचेंजर योजना कही जानी वाली महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए ट्रांसफर करती है। सरकार इस योजना की 10 किस्तें जारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है। राज्य के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है। एक साल में एनकाउंटर में 217 नक्सलियों को ढेर किया गया है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान कई घोटाले सामने आए थे। राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद घोटालों की जांच की जा रही है। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। कोयला परिवहन घोटाले की भी जांच हो रही है। सीसीपीएससी की जांच को सरकार ने सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति को लागू किया है। 1 नवंबर से नई औद्योगित नीति लागू हो गई है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गरीब लोगों के घर के निर्माण पर फैसला किया गया। राज्य में पीएम आवास योजना के दूसरे चरण का सर्वे चल रहा है। केंद्र सरकार ने 8,46,313 नए आवासों को स्वीकृति दी। राज्य में 1 लाख 74 हजार 585 लोगों को नए आवास सौंपे जा चुके हैं। वहीं, हाउसिंग बोर्ड के तहत 50 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। विष्णुदेव साय की सरकार ने युवाओं पर भी फोकस किया है। युवाओं को साधने के लिए सरकार ने होनहार छात्रों को ब्याजमुक्त कर्ज देने की घोषणा की है।

2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। साल 2028 तक सरकार ने यह संकल्प लिया है कि, हम प्रदेश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि, 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने शुरू की है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सुशासन और अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। मुझे आप लोगों को बताते हुए दर्द हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुपर रिटर्न संगठन है, जिसने पूरे विश्व में 20 गांव का चयन किया है। पर्यटन के क्षेत्र में उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मारास भी शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था। लेकिन जब भाजपा सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भविष्य कायम हो ऐसा काम किया। हमने सुशासन का वादा किया था। हम इसे पूरा भी कर रहे हैं।

नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के कई निकायों में हाइटेक लाइब्रेरी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से छत्तीसगढ़ को कई फायदे मिले हैं। बीते एक साल में प्रदेश में 31 हजार करोड़ रुपए के सड़क और राजमार्ग के कामों को स्वीकृति दी गई है। राज्य के चार प्रमुख शहरों में ई-बसों की शुरुआत का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। राज्य में भाजपा ने घोषणा की थी सरकार बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के श्रद्धालुओं को फ्री में अयोध्या का दर्शन कराया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की एक बार फिर से शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। हाल ही में बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव भी तारीफ कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने एक साल के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन से जुड़ी किताबें और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 1 साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं 96 से ज्यादा गांव को फोर्स की सुरक्षा मिली है। अपराधी किस्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। महिलाओं और किसानों के बीच सरकार का विश्वास बढ़ा है। सरकार ने जो वादा किया, उन्हें निभाया। जबकि कांग्रेस जब सत्ता में आई, तो उन्होंने जो वादे किए थे, उसे नहीं निभाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार के कामों को विफल बता रही है। एक साल में सरकार को फेल बताया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम महतारी वंदन योजना के जरिए 70 लाख महिलाओं तक पैसे पहुंचा रहे हैं। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। कांग्रेस ने जो वादा अधूरा छोड़ दिया था, उसे भी निभाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। इसके बावजूद विकास अगर और बेहतर काम कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें चश्मा पहनना चाहिए। तो कांग्रेस को अब कौन-सा चश्मा पहनाएं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

दो सियासी खानदानों पर प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महायुति की शानदार जीत ने दो सियासी खानदानों का सूपड़ा साफ कर डाला है- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेता शरद पवार और शिवसेना के उद्धव बालासाहब ठाकरे। दोनों नेताओं ने सूबे की उथल-पुथल भरी राजनीति के कई दौर देखे और झेले लेकिन इस चुनाव में हुई शर्मनाक हार ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। दोनों के दल कांग्रेसनीत महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थे। पवार की राकांपा को 10 और ठाकरे के शिवसेना वाले धड़े को महज 20 सीटें मिली हैं। यह दोनों का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। पवार के भतीजे युगेंद्र उन्हीं की परंपरागत सीट बारामती पर अपने चाचा अजित पवार से भारी अंतर से हार गए।

यह चुनावी हार इसलिए भी बहुत भारी है क्योंकि पहले ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बगावत के कारण दोनों दल दो फाड़ हो चुके थे। इस विभाजन के चलते शरद पवार और ठाकरे से उन्हीं की पार्टी का नाम और निशान दोनों छिन गया था और पार्टी की असली विरासत के तौर पर उनकी वैधता ही संकट में पड़ गई थी। आज स्थिति यह है कि शिंदे और अजित पवार के पार्टी तोड़ने और बगावत करने का मुद्दा मतदाताओं के बीच बहस से गायब हो चुका है। जानकारों की मानें, तो विधानसभा चुनावों के नतीजे साफ दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने शिवसेना और राकांपा के किन धड़ों को अपनी स्वीकृति दी है। तो क्या यह शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सियासी वजूद का अंत है? राजनीति के जानकारों की मानें, तो 83 वर्ष के पवार अब उम्र की ऐसी ढलान पर हैं कि यह चुनाव शायद उनका अंतिम चुनाव था। अपनी पार्टी 2012 से चला रहे ठाकरे भी अब अस्वस्थ रह रहे हैं। इसलिए सवाल बना हुआ है कि क्या दोनों नेता 2029 में होने वाले लोकसभा और असेंबली चुनावों में मोर्चा संभाल पाएंगे या नहीं। उद्धव ठाकरे के लिए राहत की बात बस इतनी सी है कि उनका बेटा आदित्य ठाकरे वर्ली से और चचेरे भाई वरुण सरदेसारी बांद्रा से जीत गए हैं। उन्हें शिवसेना की अगली पीढ़ी का नेतृत्व माना जा रहा है। चचेरे भाई राज ठाकरे के लिए भी चुनाव निराशाजनक साबित हुआ। शिवसेना के विकल्प के तौर पर 2006 में राज ने महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बनाई थी। उसे इस बार एक भी सीट नहीं मिली। राज के बेटे अमित ठाकरे माहिम से चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर रहे।

बंबई यूनिवर्सिटी में चुनाव और क्षेत्रीय राजनीति के जानकार संजय पाटिल मानते हैं कि उद्धव की शिवसेना और राकांपा के लिए यह चुनाव झटका साबित हुआ है लेकिन ऐसा भी नहीं कि उससे उबरा न जा सके। वे कहते हैं, सीमित वित्तीय संसाधनों और जबरदस्त दबाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है, खासकर तब जब कि आपकी मूल पार्टी और उसके नेताओं को ही तोड़ लिया गया हो। इसके बावजूद ठाकरे और पवार जमीन पर मजबूती से बने रहे और भाजपा के खिलाफ लड़े। पाटिल इस बात पर जोर देते हैं कि इस चुनावी नतीजे को दोनों दलों के टूटने के बाद निवर्तमान विधायकों की ताकत के संदर्भ में विश्लेषित किए जाने की जरूरत है। 2019 के असेंबली चुनाव में अविभाजित सेना के 56 विजयी विधायकों के बीच शिंदे 41 को लेकर निकल गए थे और ठाकरे के पास पंद्रह बचे थे। इसी तरह अजित पवार ने राकांपा के 54 विधायकों में से 41 को तोड़ लिया था और शरद पवार के खेमे में केवल तेरह विधायक बचे थे। इन बचे हुए विधायकों को भाजपा के खिलाफ लड़वाकर जितवाना कोई आसान काम नहीं था। पाटिल कहते हैं, इसलिए इस संख्या को कायम रखना, जबकि उनके पास अपने खेमे में कुछ भी प्रभावी नहीं बचा था, मामूली बात नहीं है। यह खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। अब दोनों दलों को जमीनी स्तर पर अपना पार्टी संगठन और काडर मजबूत करने की जरूरत होगी। तात्कालिक जरूरत यह है कि दोनों नेता अपने खेमों को एकजुट रखें और अपने किसी भी विधायक को सत्ताधारी खेमे में न जाने दें। बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना के लेखक वैभव पुरंदरे का कहना है कि उद्धव ठाकरे को विचारधारात्मक अंतर्विरोधों को भी हल करना होगा, जिसके चलते उनके जनाधार को चोट पहुंची है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव पैदा हुआ है। उद्धव की शिवसेना ने पार्टी के मूल वैचारिक एजेंडे (मराठी मानुष और आक्रामक हिंदुत्व) को हल्का कर दिया था जिसके चलते उसके बहुत से वोटर छिटक गए। मुंबई, नासिक और पुणे के शहरी इलाकों का परंपरागत मराठी वोटबैंक शिंदे के धड़े के साथ चला गया जबकि आक्रामक हिंदुत्व की चाह रखने वाले वोटर सीधे भाजपा के संग हो लिए।

वैचारिक मोर्चे पर संकट इसलिए भी गहरा गया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव के धड़े ने मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की, जिसके आधार पर महाविकास अघाड़ी को करीब तीस लोकसभा सीटों पर जीत मिली। पुरंदरे कहते हैं, ठाकरे का सेकुलर हिंदुत्व और मुसलमान समर्थक रवैया ही शिवसेना की छवि के लिए संकट पैदा कर रहा है। उन्हें इन छवियों से निपटने की जरूरत होगी। पुरंदरे के अनुसार अतीत में भी शिवसेना को नेताओं की बगावत झेलनी पड़ी है और चुनावी झटके लगे हैं, इसलिए इस बार वापसी कोई असंभव चीज नहीं है लेकिन कठिन बेशक है। ठाकरे के पास मुंबई के निकाय चुनावों के दौरान अपनी ताकत दिखाने का मौका है। लंबे समय से लंबित बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनावों की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है क्योंकि भाजपा को अब भारी बहुमत मिल चुका है। बीएमसी देश का सबसे पैसे वाला नगरीय निकाय है जिसका बजट 50 हजार करोड़ रुपए है। बीएमसी का पिछला चुनाव 2017 में हुआ था और मार्च 2022 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद से निगम आयुक्त के फैसलों पर ही बीएमसी काम कर रहा है। आयुक्त को राज्य सरकार नियुक्त करती है।

● **बिन्दु माथुर**

अब बीएमसी में होगी परीक्षा

अविभाजित शिवसेना ने निगम चुनावों के रास्ते ही पहली बार 70 के दशक में अपनी सियासी प्रतिस्पर्धा साबित की थी। 1985 के बाद से केवल चार मौकों को छोड़ दें तो शहर का मेयर लगातार शिवसेना का ही रहता आया था। बीएमसी में सेना की सत्ता होने का मतलब मुंबई पर राज होता था- यानी उस शहर पर राज, जो देश की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है। इसीलिए मुंबई को ठाकरे परिवार से मुक्त कराना भाजपा के एजेंडे पर बहुत पहले से रहा है। ऐसा 2019 से पहले मुमकिन नहीं हो सकता था क्योंकि तब तक दोनों गठबंधन में थे। अब भाजपा के लिए बीएमसी का चुनाव जीतना बहुत अहम होगा। उतना ही अहम यह उद्धव की शिवसेना यूबीटी के लिए भी होगा। भाजपा और शिंदे की शिवसेना बीते चुनावों की कामयाबी से फूले हुए हैं, तो वे बीएमसी जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं।

विवादों में 800 साल पुरानी दरगाह

राजस्थान की राजधानी जयपुर से 135 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर शहर सुर्खियों में है। यहां स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दरगाह शरीफ से जुड़ी एक याचिका अजमेर की स्थानीय अदालत में डाली गई है। इसके लिए अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा की 100 साल पुरानी एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया गया है। इस किताब को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ करीब 850 साल पुरानी है।

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा अजमेर न्यायालय में दायर किए गए दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने के मामले में कोर्ट ने वाद स्वीकार कर लिया है। मामले को लेकर न्यायालय ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर निर्धारित की है। वहीं इस वाद के खिलाफ अजमेर दरगाह से जुड़ी अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने एक बयान जारी कर कहा कि कभी मथुरा, कभी काशी, बाबरी मस्जिद के बाद अब कुछ नहीं होगा। उन्होंने वरशिप एक्ट का भी हवाला देते हुए अब अजमेर दरगाह मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बयान जारी किया है।

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के वाद पेश होने के बाद अजमेर दरगाह दिवान के उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि यह एक न्याय प्रक्रिया है और न्याय प्रक्रिया में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। न्यायालय में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। हम हमारे वकीलों से इस पर राय ले रहे हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया जो अपनानी होगी अपनाएंगे। साथ ही हम मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को खारिज कराया जाए और अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा कि यह जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठकर आ रहा है और हिंदुस्तान में मस्जिदों और दरगाहों पर ये क्लेम किया जा रहा है कि यह मंदिर थे। यह परिपाटी देश के और समाज के हित में नहीं है। मैं मोहन भागवत के 2022 के बयान से भी इत्तेफाक रखता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश न करें। उन्होंने कहा कि हरविलास शारदा की किताब का हवाला देकर वाद पेश किया गया है, लेकिन हरविलास शारदा कोई इतिहासकार नहीं थे और उन्होंने अपनी किताब में जो भी दावे किए हैं, उसमें किसी भी रिफरेंस का प्रयोग नहीं किया है। दरगाह के 800 साल पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। यहां हिंदू राजा-महाराजाओं ने भी अकीदत के फूल पेश किए हैं। दरगाह के अंदर जो चांदी का कटहरा है, जिसमें 42,961 टोला चांदी का प्रयोग किया गया है, यह जयपुर के महाराज का चढ़ाया हुआ है।

वहीं इस पूरे मामले पर दरगाह के बाहर देशभर से आए जायरीनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल ख्वाजा साहब की दरगाह है। जायरीनों ने कहा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत कर रहे हैं। हमारी मन्नत यहां कबूल होती है। ख्वाजा साहब की दरगाह का 800 साल पुराना इतिहास है, जिसमें कहीं भी शिव मंदिर होने का उल्लेख नहीं है। जायरीनों ने कहा कि पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। जल्द ही सच सामने आएगा। दरगाह गेट के बाहर दुकानदारों ने कहा कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने की बात पहली बार सुन रहे हैं। हमारा मानना है कि इसमें राजनीति हो रही है।

वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अजमेर सिविल न्यायिक कोर्ट में अजमेर दरगाह पर महादेव मंदिर के दावे के वाद पेश करने में बाद विष्णु गुप्ता के वकील रामस्वरूप विश्नोई और योगेश सिरोलिया ने बताया कि हमने परिवादी विष्णु गुप्ता के दिए तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। इस वाद में हरविलास शारदा की लिखी किताब में दिए तथ्यों को आधार बनाया गया है। वाद में एएसआई सर्वे और दरगाह में पूजा-अर्चना की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता का ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने के बाद अजमेर के भाजपा के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

1236 में ख्वाजा साहब ने दुनिया को कहा अलविदा

पूर्वी ईरान के शहर सजीस्तान में 536 हिजरी यानि 1143 ईस्वी को जन्में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ईरान से अफगानिस्तान होते हुए लाहौर पहुंचे। यहां से दिल्ली फिर अजमेर में अपना ठहराव किया। यहां रहकर वह खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। सूफिज्म पर लिखने वाले सुमन मिश्रा कहते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ 850 साल पुरानी है। इस दरगाह का निर्माण धीरे-धीरे हुआ है। तकरीबन 228 साल तक यह दरगाह कच्ची रही है। आईने-अकबरी के मुताबिक, सन् 1561 से 1568 ईस्वी तक सैन्य उद्देश्यों के लिए सम्राट अकबर को अजमेर की दरगाह जाना पड़ा था। अकबर के कोई संतान नहीं थी। 1570 में वह ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ पर पहुंचे और वहां पुत्र प्राप्ति के लिए दुआ की। उनकी इच्छा सलीम के रूप में पुत्र प्राप्ति के साथ पूरी हुई। ख्वाजा साहब का धन्यवाद करने के लिए अकबर आगरा से अजमेर दरगाह तक पैदल चलकर पहुंचे। आगरा से अजमेर चलकर आने में उन्हें 15 दिन लगे। उसी वर्ष अकबर ने दरगाह परिसर में एक शानदार मस्जिद का निर्माण किया। वर्तमान में इस मस्जिद को अकबरी मस्जिद कहते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित मुख्य मेहराब 56 फीट ऊंची है।

मुलायम वाले तेवर में अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) ने साल 2012 के उप्र चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर सूबे में सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही थे। मुलायम की बात करने के पीछे दो कारण हैं। एक ये कि पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव की जयंती थी और दूसरा ये कि उप्र की नौ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वे पुरानी सपा की लीक पर लौट रहे हैं?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उप्र की नौ सीटों पर वोटिंग के दिन 20 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निशाने पर रखा ही, पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को भी नाम, इज्जत, पीएफ और पेंशन जाने की चेतावनी दे दी। अखिलेश यादव जिस तरह से आक्रामक अंदाज में नजर आए, उससे वह पांच संकेत दे गए। सपा की इमेज ऐसी पार्टी की रही है जो किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी रहती है। कई बार सपा इस इमेज की वजह से राजनीतिक गलियारों में आलोचनाओं से घिरी और विपक्षी दलों ने अपराधियों की पार्टी वाली इमेज भी गढ़ी। अखिलेश ने उप्र का मुख्यमंत्री रहते सपा की इमेज बदलने की कोशिश में नई सपा की बात की थी।

अखिलेश की नई सपा इमेज क्लीन करने की कोशिश में कार्यकर्ताओं से दूर होती चली गई और नतीजा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के दो धड़े में बंटने, मुलायम को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने और चुनावी टेस्ट में फेल होने के रूप में सामने आया। सपा अब फिर से किसी भी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी हो जाने वाली पार्टी की लीक पर लौटती नजर आ रही है। अनुजेश यादव एनकाउंटर या देवरिया कांड पर सपा का स्टैंड हो या अब उपचुनाव में मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में धांधली के आरोप पर अखिलेश के तेवर, संकेत यही है।

मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के जमाने में यानि पुरानी सपा के दौर में साइकिल निशान वाली पार्टी ग्राउंड पर फाइट करने वाली पार्टी की इमेज रखती थी। 2012 में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में क्या आई, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ग्राउंड पर फाइट मानो भूल ही गए। सत्ता में रहते हुए धरना-प्रदर्शन तो कोई दल नहीं करता लेकिन गायत्री प्रजापति केस समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने में सपा के नेता-कार्यकर्ता विफल साबित हुए। 2017 में चुनावी बाजी हारने के बाद 2019 के आम चुनाव से पहले अखिलेश एक्टिव हुए भी तो ग्राउंड पर फाइट से अधिक नैरेटिव की लड़ाई और गठबंधनों का गणित सेट करने पर ही अधिक फोकस किए नजर आए।

आम चुनाव 2019 के बाद सपा का फोकस इस तरफ शिफ्ट होता नजर आया और पहले 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्साहजनक नतीजों के बाद अब पार्टी पुराने फॉर्मूले पर आती दिख रही है। वोटिंग के दिन अखिलेश यादव ने यह कहा कि हमारे लोग पुलिस-प्रशासन जो कर रहा है, उसकी वीडियो-फोटो जुटा रहे हैं। अब सपा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पिस्टल ताने पुलिस अधिकारी के सामने खड़ी हो गई महिला तोहीदा को सम्मानित करने की बात कर रही है तो यह भी इसी तरफ इशारा करता है कि अखिलेश यादव अब ग्राउंड पर फाइट के मुलायमकालीन फॉर्मूले पर लौट रहे हैं।

अखिलेश यादव जब उप्र के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव ने सूबे में संगठन की कमान शिवपाल यादव को सौंप दी थी। शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना बेटे और भाई में पावर बैलेंस करने की कोशिश के रूप में भी देखा गया लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि मुलायम सिंह यादव को पता था कि अपने भाई की क्षमता का सबसे सही इस्तेमाल किस जगह कर सकते हैं। शिवपाल उन नेताओं में हैं जिन्होंने स्थापना के बाद सपा का संगठन खड़ा करने में, उसे मजबूत करने में मुलायम के साथ पसीना बहाया। शिवपाल की इमेज शुरू से ही कुशल संगठनकर्ता की रही है। अखिलेश ने भी अब शिवपाल का संगठन में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शिवपाल को लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रभारी बनाया गया जहां वह सफल साबित हुए। अब नौ सीटों के उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें कटेहरी का प्रभारी बनाया था। मुलायम सिंह यादव की इमेज धरतीपुत्र की रही है। छुआछूत का विरोध करते हुए मुलायम में दलित समाज के लोगों को अपने भाई की शादी में आमंत्रित कर सबको गले लगाया था, अपने सामने भोजन कराया था। उप्र की दलित पॉलिटिक्स में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उभार और गेस्टहाउस कांड के बाद सपा की पकड़ इस वोटबैंक पर कमजोर पड़ती चली गई। अब अखिलेश पीडीए के नारे के साथ सपा का वोट बेस यादव-मुस्लिम से आगे बढ़कर अन्य पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग तक बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं और लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले के अच्छे नतीजे भी उप्र की विपक्षी पार्टी को मिले।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

2027 की पिच तैयार करने की रणनीति

उप्र उपचुनाव 2027 की चुनावी जंग से पहले सेमीफाइनल की तरह भी देखा जा रहा था। लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में भाजपा से बीस साबित हुई सपा हर हाल में 2027 चुनाव तक आम चुनाव के समीकरण और मोमेंटम बनाए रखना चाहती है। सभी नौ सीटों के उपचुनाव में सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से उम्मीदवार उतारने का फैसला हो या मतदान को लेकर शिकायतों पर अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब भी सपा के मिशन 2027 से ही जोड़कर देखे जा रहे हैं। अखिलेश ने अधिकारियों के नाम लेकर, इज्जत-नौकरी-पीएफ-पेंशन जाने को लेकर आगाह कर एक तरह से सपा समर्थकों को यह संदेश भी दिया कि पार्टी सत्ता में आई तो ऐसे अधिकारी हिट लिस्ट में होंगे जिन पर समर्थकों के उत्पीड़न का आरोप होगा।

कृषि में बदलाव से सुधरेगी देश की अर्थव्यवस्था

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए इसे कृषि उद्योग कहना ही सही होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। देश की लगभग 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि उद्योग पर निर्भर है। पूरी दुनिया में कुल वानस्पतिक भू-भाग के लगभग 11 प्रतिशत भू-भाग पर ही कृषि की जाती है, जबकि हमारे देश में पूरे देश की कुल वानस्पतिक भूमि के लगभग 51 प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है।

हमारे देश में कृषि से दुनिया की कुल 17.2 प्रतिशत जनसंख्या के भरण-पोषण के लायक खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं, जबकि हमारे देश की कुल जनसंख्या 145 करोड़ के हिसाब से दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17.78 प्रतिशत है। इस हिसाब से हमारे देश में लगभग सभी लोगों के लिए अनाज, दालें, सब्जियां और फल उपलब्ध हैं। जिन 0.76 प्रतिशत के लिए इसकी कमी है, उसकी चिंता की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि देश में 79 प्रतिशत लोग मांसाहारी भी हैं, जिसे जोड़कर हमारे देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन भुखमरी सूचकांक-2023 में हमारे देश का स्थान 111 है, जो कि 125 देशों के हिसाब से 100 देशों में 88.8वां स्थान है। हमारे देश की केंद्र सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है और भुखमरी की अति गंभीर और चिंताजनक स्थिति दिखा रहा है। उसे 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन मुफ्त देने से बाहर निकलकर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और लोगों को पांच किलो राशन लेने के लिए लाइन में न लगाना पड़े। इसके लिए सरकार को बहुत कुछ न करके सिर्फ कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ाना होगा और किसानों से उनकी एमएसपी वाली 23 फसलें उचित मूल्य पर सी2+50 के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से खरीदना होगा।

कृषि के विकास से लोगों के पोषण में सुधार होगा, भुखमरी मिटेगी, कुपोषण नहीं रहेगा, कृषि और कृषि उत्पादों से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हमारे देश की सभी सरकारों को समझना होगा कि हमारे देश में कृषि असीमित रोजगार देने में समर्थ है और आर्थिक-सामाजिक विकास की यह प्रधान कुंजी है। कृषि क्षेत्र में हमारा देश प्राचीन-काल से आर्थिक समृद्धि का गवाह रहा है; लेकिन इस क्षेत्र का बड़ा लाभ पहले जमींदारों को जाता रहा और आज पूंजीपतियों को जाता है, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय बनी रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता के हजारों साल पहले के कृषि साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दुनिया में सिर्फ हमारे देश में कृषि का विकास मानव सभ्यता के पुरातन-काल से है और इसका विकास दुनिया के सभी देशों के विकास से हजारों साल पहले हो चुका था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा देश ही कृषि में पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि और कृषि क्षेत्र का पूंजीपतियों को हाथ में जाना तो है ही, कृषि उपजों का दूषित होना है। खाद्य उत्पादों की बर्बादी भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जिसमें एफसीआई के गोदामों में खाद्य उपजों की बड़ी मात्रा में बर्बादी चिंता का विषय है।

आज कृषि एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, बागबानी, फसल उत्पादन, पशु-पक्षी पालन और मछली पालन आदि आते हैं। कृषि क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत जन-श्रम शक्ति लगी है। खाद्य उत्पादों से संबंधित कई छोटे-बड़े उद्योग कृषि पर ही निर्भर हैं, जिनमें जूट उद्योग, लकड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी उद्योग, मसाला उद्योग, चाय-कॉफी उद्योग, शराब उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग, चिकित्सा उद्योग, फल और जूस उद्योग, मादक पदार्थ और तम्बाकू उद्योग सब कृषि क्षेत्र की ही देन हैं। पशु-पक्षी उद्योग पर डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, मांस उद्योग, हड्डियों से बनने वाले पदार्थों के कई उद्योग, दवा उद्योग और कॉस्मेटिक उद्योग आदि निर्भर हैं। अगर कृषि उद्योग को बढ़ावा देकर इन सभी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाए, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा।

हमारे देश में कृषि उत्पादों पर निर्भर उद्योगों से देश की कुल अर्थव्यवस्था की लगभग 35 प्रतिशत आपूर्ति होती है। जबकि कृषि अर्थव्यवस्था की देश की कुल अर्थव्यवस्था में सिर्फ 6.5 प्रतिशत ही भागीदारी है। 1950 के दशक में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उद्योग की भागीदारी लगभग 53 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था में विकास की गति बढ़ाने और कृषि उद्योग पर ध्यान न देने से सन् 1995 आते-आते सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी सिर्फ 25 प्रतिशत रह गई और वित्त वर्ष 2011-2012 में ये भागीदारी और घटकर 13.3 प्रतिशत ही रह गई।

● **विनोद बक्सरी**

रबी की बुवाई के समय डीएपी की किल्लत

रबी की फसलों की बुवाई शुरू होने से पहले ही इस बार उत्तर भारत के कई राज्यों में डीएपी की किल्लत से किसान परेशान हैं। दिन-रात सहकारी खाद वितरण केंद्रों पर किसान लाइन लगाकर दिन-दिनभर खड़े रहते हैं और फिर भी डीएपी मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके अलावा शिकायतें हैं कि सहकारी केंद्र डीएपी के साथ जबरन नैनो यूरिया और जिंक किसानों को दे रहे हैं। इससे किसानों को पैसे भी ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं और नैनो यूरिया तथा जिंक किसानों के काम की भी नहीं है। क्योंकि जिंक धानों में पड़ती है और नैनो यूरिया के कई नुकसान भी फसलों को हो सकते हैं। प्राइवेट खाद विक्रेता डीएपी ब्लैक में बेच रहे हैं और उसके ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। डीएपी न मिलने से किसानों को रबी फसलों, विशेषकर गेहूं बोने में देरी हो रही है। बुवाई में देरी होने से कई किसानों के खेतों की नमी सूख चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसानों की इस परेशानी को समझना चाहिए। आज किसानों को न तो ज्ञान आधारित खेती करने की जानकारी दी जाती है और न ही उनके आर्थिक विकास पर विचार किया जाता है।

ड्रैगन की नापाक चाल

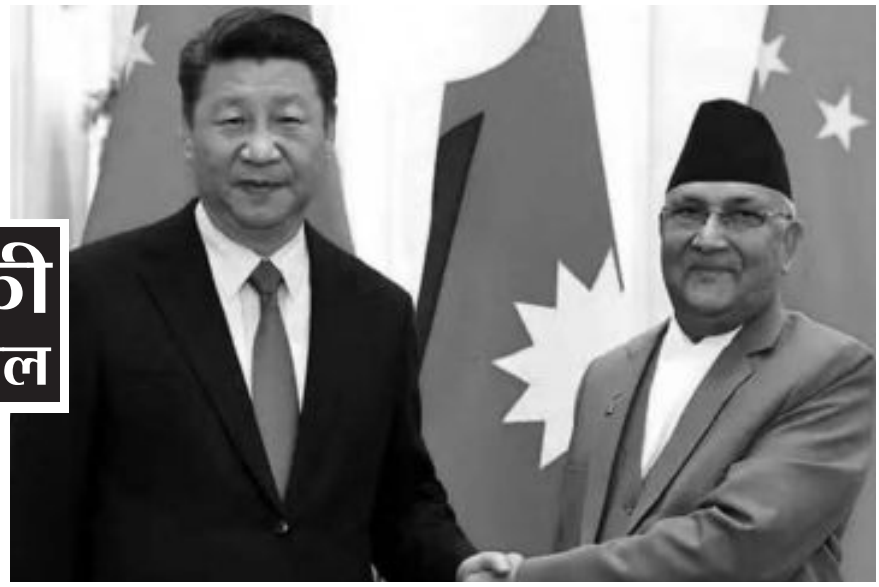

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन पहुंच गए हैं। इस यात्रा को नेपाल को चीन के और नजदीक ले जाने का सूचक माना जा रहा है, क्योंकि परंपरागत तौर पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री पहली विदेश यात्रा पर भारत आते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत विरोध और चीन से मित्रता ओली की व्यक्तिगत रुचि रही है।

ओली हमेशा चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने भारत विरोध का सहारा लेकर ही अपनी राजनीति मजबूत की है, फिर चाहे वह 2015 में की गई सीमा की नाकाबंदी हो, 2019 में सीमा-विवाद का राजनीतिकरण करना हो या फिर नेपाल का एक विवादित नक्शा लाना हो, जिसमें नेपाल ने भारत के कुछ संप्रभु क्षेत्रों को अपना दिखाया। ओली का राजनीतिक झुकाव चीन की ओर होना भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन उनकी इस यात्रा को नेपाल का भारत से दूर जाना मान लेना भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को कमजोर करार देने के बराबर है। तथ्य बताते हैं कि जितनी भी बार ओली और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एमाले) ने चीन के साथ समझौते या राजनीतिक संबंधों की वकालत की है, वह मुख्यत: प्रतीकात्मक ही रही है और परिणामों पर कम खरी उतरी है। चूंकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता एक सामान्य बात है और हर छह-आठ महीनों में एक नई सरकार आती है, ऐसे में हर प्रधानमंत्री का भारत आना नेपाली विदेश नीति के लिए दूसरे पड़ोसी देश की अनदेखा करने का संकेत माना जा सकता है। इससे उसके हित प्रभावित हो सकते हैं। यहां यह भी देखना जरूरी है कि ओली नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ एक गठबंधन वाली सरकार चला रहे हैं और नेपाली कांग्रेस भारत के साथ मजबूत संबंधों की वकालत करती रही है।

चूंकि मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री नेपाली कांग्रेस से हैं, ऐसे में नेपाली कांग्रेस भारत के साथ इतना बड़ा जोखिम लेने से बचेगी। इसलिए नेपाल दो पड़ोसियों के बीच संतुलित विदेश नीति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ओली का चीन के प्रति झुकाव नेपाल के लिए फायदे का सबब बना है? उत्तर नकारात्मक ही है, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच जितने भी बड़े समझौते पिछले दस वर्षों में हुए हैं, उनमें ज्यादातर ठंडे बस्ते में पड़े हैं और यह बात चीन को सताती रही है।

मई 2017 में चीन ने नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर समझौता किया, जिसे चीन की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा गया, क्योंकि भारत लगातार बीआरआई के अंतर्गत बने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आलोचना करता रहा है। बीआरआई समझौते के तहत चीन को नेपाल में बड़े बुनियादी ढांचे वाली तमाम परियोजनाओं में निवेश करना है, जिनमें ट्रांस-हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क खास है, जो नेपाल को रेल एवं सड़क मार्ग से तिब्बत प्रांत से जोड़ने वाला है। इससे ऐसा लगा कि नेपाल चीन के रास्ते भारत पर अपनी निर्भरता कम करने का मार्ग खोज रहा है, लेकिन करीब सात वर्ष बीत जाने के बाद भी नेपाल में ऐसी एक भी परियोजना लागू नहीं हो सकी है। इसके दो कारण हैं। पहला, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के चलते परियोजनाओं की पहचान नहीं हो पाई है। दूसरा, नेपाल लगातार चीन से बीआरआई के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए सहयोग वित्तीय सहायता के तौर पर चाहता है। जबकि चीन कर्ज देने में रुचि रखता है। श्रीलंका का उदाहरण देखते हुए नेपाल इससे डर रहा है। बड़े कर्ज के चलते श्रीलंका को अपने हंबनटोटा जैसे बंदरगाह का नियंत्रण चीन के हाथों में देना पड़ा है। अगर नेपाल चीन से कर्ज लेता है तो भविष्य में उसे नेपाल पर दबाव बनाने का अवसर मिलेगा, जो बीआरआई का मुख्य वैश्विक उद्देश्य रहा है। वर्ष 2016 में ओली ने अपनी चीन यात्रा के दौरान उसके साथ परिवहन एवं परिगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत नेपाल चीन के छह बंदरगाहों के रास्ते अन्य देशों से व्यापार कर सकता है।

नेपाल पूरब में चीन से और तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। वह भारत के बंदरगाहों का उपयोग कर अन्य देशों से व्यापार करता रहा है। यह उसके लिए हर तरह से फायदेमंद है, लेकिन 2015 में भारत के साथ सीमाबंदी का मुद्दा सामने आने के बाद ओली ने चीन को एक विकल्प के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो चीन के बंदरगाह नेपाल से कम से कम 3,000 किलोमीटर दूरी पर हैं। जबकि भारत का कोलकाता बंदरगाह मात्र 700 किलोमीटर दूर है। समझौते के छह साल बाद भी नेपाल ने चीन के बंदरगाहों के रास्ते केवल एक ही बार व्यापार किया है। इसकी वजह यह है कि नेपाल के लिए भारत के रास्ते व्यापार करना आसान और किफायती है।

● **कुमार विनोद**

आज भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार

भारत के साथ नेपाल के संबंधों पर प्रकाश डाला जाए तो हाल में नेपाल ने भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली बेची है, जो क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण पहल है। बांग्लादेश को बिजली बेचने से नेपाल को न केवल आर्थिक फायदा होगा, बल्कि उसके लिए भारत के रास्ते अन्य देशों को भी बिजली बेचने के रास्ते खुलेंगे। भारत और नेपाल पनबिजली क्षेत्र में एक और मजबूत साझेदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके अलावा आज भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सीमा विवाद जैसे मुद्दे के बावजूद भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है। दोनों देश विज्ञान और तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में, इस नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा कि ओली की चीन यात्रा भारत के लिए बुरी खबर है।

आतंकी से विद्रोही तक

सीरिया में विद्रोह के बिगुल के बीच तख्तापलट हो चुका है। इस्लामिक विद्रोहियों ने हालात ऐसे कर दिए कि राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होना पड़ा और इस तरह सीरिया में असद परिवार के 50 सालों का वर्चस्व खत्म हुआ। रूस का कहना है कि असद और उनके परिवार ने मॉस्को में शरण ली है। उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। असद ने इससे पहले विद्रोही समूहों के साथ बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के लिए हामी भर दी थी। इस तरह इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) की अगुवाई में विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क तक पहुंचे और असद सरकार का तख्तापलट कर दिया। बता दें कि अल-कायदा के पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी हगयात तहरीर अल शाम ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं। यह सीरिया का सबसे बड़ा विद्रोही धड़ा है और फिलहाल देश की बागडोर इसी के हाथ में है। जोलानी का कहना है कि असद की सरकार का पतन इस्लामिक राष्ट्र की जीत है। इस समय सीरिया में हालात ऐसे हैं कि सीरियाई नागरिकों ने बशर अल असद के दिवंगत पिता हाफीज अल असद की देशभर में लगी मूर्तियों को तोड़ दिया।

कुख्यात आंतकी संगठन के जिहादी आंदोलन में एक खास भूमिका अदा करने वाले विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी का नाम सीरिया के जटिल संघर्ष में एक अहम किरदार के रूप में उभरा है। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के सदस्य से लेकर स्थानीय विद्रोही बल के नेता बनने तक का सफर जोलानी ने यूं ही पूरा नहीं किया, बल्कि सीरिया की जंग में उसकी भूमिका और बहुआयामी शक्ति के साथ-साथ जनता के साथ जुड़ाव ने भी इसमें खास रोल अदा किया है। सीरिया के डेयर एज-जोर प्रांत में 1981 में अहमद हुसैन अल-शरा के रूप में उसका जन्म हुआ था। कुछ जगहों पर उसके जन्म के स्थान को सऊदी अरब के रियाद में बताया गया है और जन्म के साल को 1982। अहमद हुसैन अल-शरा को बाद में अबू मोहम्मद अल-जोलानी के नाम से जाना गया। अहमद हुसैन अल-शरा के रूप में जन्मे अल-जुलानी ने कम उम्र में ही उग्रवाद की राह पकड़ ली थी। उसका परिवार गोलान हाइट्स से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसने अपना बचपन दमिश्क में बिताया। जोलानी ने एक ऐसा करियर अपनाया जो उसे चरमपंथी हलकों में ले गया। साल 2000 के दशक की शुरुआत में, वह अबू मुसाब अल-जरकावी के नेतृत्व में इराक जाकर आतंकी संगठन अल-कायदा में शामिल हो गया। साल 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद, जोलानी ने एक्यूआई के भीतर खास मुकाम हासिल किया, और अराजकता का लाभ उठाकर उसने एक उग्रवादी रणनीतिकार के रूप में अपनी साख बनाई।

साल 2006 में जरकावी की मौत के बाद, अबू मोहम्मद अल-जोलानी आईएसआईएस के भावी नेता अबू बकर अल-बगदादी का करीबी सहयोगी बन गया। कथित तौर पर उसे इराक में अमेरिकी सेना द्वारा कैद कर लिया गया था और 2008 में रिहा किया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उसे जिहादी रैंकों में फिर से शामिल होने का मौका दे दिया। साल 2011 में, बशर अल-असद के खिलाफ सीरिया के विद्रोह के बीच, अबू मोहम्मद अल-जोलानी सीरिया में अल-कायदा शाखा स्थापित करने के मिशन के साथ अपने वतन लौट आया। उसने 2012 में अल-कायदा नेता अयमान अल-जवाहिरी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए जबात अल-नुसरा (द सपोर्ट फ्रंट) की स्थापना की। अल नुसरा समूह असद की सेनाओं के खिलाफ युद्ध के मैदान में अपनी सफलता और आत्मघाती बम विस्फोटों और फांसी सहित क्रूर रणनीति के लिए जल्दी ही कुख्यात हो गया था। जानकार मानते हैं कि अबू मोहम्मद अल-जोलानी की महत्वाकांक्षाएं अल-कायदा की विचारधारा से आगे बढ़ गईं थीं, क्योंकि वह सीरिया की बिखरी हुई विपक्षी ताकतों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। साल 2016 में, उसने जबात अल-नुसरा को जबात फतह अल-शाम के रूप में पुनः स्थापित किया और अल-कायदा से औपचारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया। यह कदम रणनीतिक था, जिसका उद्देश्य सीरियाई विद्रोहियों और स्थानीय आबादी के बीच व्यापक सहमति और समर्थन हासिल करना था। एक साल बाद, जेएफएस ने अन्य गुटों के साथ विलय करके हयात तहरीर अल-शाम का गठन किया, जिसका नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी ही था। एचटीएस ने खुद को असद के शासन से लड़ने वाले विद्रोही समूह के रूप में स्थापित किया। इस समूह ने खुद को वैश्विक जिहादी उद्देश्यों और आंदोलन से दूर कर लिया था। अबू मोहम्मद अल-जोलानी के नेतृत्व में, एचटीएस सीरिया के उत्तर-पश्चिम में, विशेष रूप से इदलिब प्रांत में प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। उसने एक व्यावहारिक नेता की छवि बनाई, जो एचटीएस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शासन, सार्वजनिक सेवाओं और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता था।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

आसान नहीं जोलानी की राह

जैसे-जैसे सीरिया का युद्ध आगे बढ़ता रहा, अबू मोहम्मद अल-जोलानी का संघर्ष उसे मुश्किल रास्ते का अहसास भी करता रहा, जिसने उग्रवाद, विद्रोह और शासन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। अब देखना ये है कि सीरिया की सत्ता में वह एक प्रमुख खिलाड़ी बने रहेंगे या गुमनामी में खो जाएंगे। हालांकि यह सब सीरिया में चल रहे संकट के बदलते हालात, गठबंधन और जमीनी राजनीति पर निर्भर करेगा। सीरिया में अलकायदा से जुड़े सुन्नी विद्रोही गुट एचटीएस का कब्जा हो गया है। बशर के रूस भाग जाने के बाद इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया की सीमा के भीतर घुस गई। 1994 के एग्रीमेंट के बाद यह पहली बार है, जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीं पर कदम रखा है। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के नजदीक 10 किलोमीटर भीतर सीरियाई जमीन पर कब्जा करके बफर जोन भी बना दिया है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इजरायल ने सीरियाई इलाकों पर कब्जे की योजना बनाई है और अपनी इसी प्लानिंग को वह बहुत जल्द अंजाम देने वाला है।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

अदालती पेंचों में फंसी युवतियां

आज भी कानून द्वारा थोपी जा रही पौराणिक पाबंदियों और नियम-कानूनों के चलते युवतियों का जीवन दूभर है। मुश्किल तब ज्यादा खड़ी हो जाती है जब कानून बनाने वाले और लागू कराने वाले असल नेता व जज उन्हें राहत देने की जगह धर्म का पाठ पढ़ाते दिखाई देते हैं। 2020 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने सिंदूर और चूड़ी को लेकर एक फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पत्नी के सिंदूर लगाने और चूड़ी पहनने से इनकार करने का मतलब है कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी आगे जारी नहीं रखना चाहती है और यह तलाक दिए जाने का आधार है।

एक आदर्श स्त्री की परिभाषा क्या है, आजकल अदालतों में इसका खूब बखान हो रहा है। कुछ वर्षों पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस परिभाषा को स्पष्ट किया था और कहा था कि आदर्श स्त्री वही है जो बलात्कार के बाद सोए नहीं, बल्कि तुरंत इस अपराध की इत्तिला करे। बनारस की एक स्टार्टअप कंपनी ने लड़कियों को आदर्श बहू बनने की ट्रेनिंग देने की पेशकश कर डाली। ऐसी ट्रेनिंग गीताप्रैस वाले कई सालों से दे रहे हैं। उनकी पुस्तकों के नाम पढ़कर ही आप समझ जाएंगे, जैसे नारीधर्म, स्त्री के लिए जीवन के आदर्श, दांपत्य जीवन के आदर्श, गृहस्थ में कैसे रहें... आदि, आदि। ऐसा ही एक आदेश गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी सुना डाला कि अगर एक विवाहित महिला सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती तो इसका मतलब है वह अपने शादीशुदा जीवन में खुश नहीं है।

2018 में पुणे में एक महिला से एक पुलिस वाले ने पूछताछ की कि आप ने कोई गहना क्यों नहीं पहना है? सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? एक पारंपरिक गृहिणी की तरह कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? वह उस औरत के विवाहित होने पर संदेह क्यों कर रहा था, इसलिए कि वह औरत ढकोसलों में भरोसा नहीं करती। 2018 में ही आंध्रप्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के गांव थोकलापल्ली की औरतों को दिन में नाइटी न पहनने का फरमान सुनाया गया था। एक बार किसी ने कहा था कि शादी के बाद लड़कियां सिंदूर और चूड़ियां नहीं पहनतीं तो लगता ही नहीं है कि वे शादीशुदा हैं। यानी, लड़कियों के लिए शादीशुदा दिखना जरूरी है। यह दिखाना जरूरी है कि उनके शरीर पर एक पुरुष का कब्जा है। सिंदूर और मंगलसूत्र के जरिए यह दिखाना होता है कि उक्त महिला किसी की संपत्ति है। सो, वह किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है। अदालत ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया है कि शादी के बाद महिलाओं को सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना ही पहनना है, वरना माना जाएगा कि उन्हें शादी में विश्वास नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा-5 के अनुसार विवाह के लिए किसी भी व्यक्ति या पार्टी को पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, यानी कि शादी के समय किसी भी पार्टी में पहले से ही जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, यह अधिनियम बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है। शादी के समय यदि कोई पक्ष बीमार है तो उस की सहमति वैध नहीं मानी जाएगी, भले ही वह वैध सहमति देने में सक्षम हो लेकिन मानसिक विकारग्रस्त नहीं होना चाहिए जो उसे शादी के लिए और बच्चों की जिम्मेदारी के लिए अयोग्य बनाता है। दोनों में से कोई पक्ष पागल भी नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों में किसी की उम्र विवाह के लिए कम नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सपिंडों या निषिद्ध संबंधों की डिग्री के भीतर नहीं होना चाहिए, जब तक कि कोई भी कस्टम प्रशासन उन्हें इस तरह के संबंधों के विवाह की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा एक्ट में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यदि कोई विवाहित महिला मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं पहनती है तो यह पति के साथ क्रूरता का प्रतीक है और इसका यह मतलब हुआ कि महिला शादी को नहीं मानती है।

मनुस्मृति में महिलाओं के लिए लिखा गया है कि एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह पश्चात पति द्वारा उसका संरक्षण होना चाहिए और पति के बाद अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। यह बात मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखी गई है। इसके अलावा मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में काफी कुछ लिखा गया है जो अक्सर विवादों को जन्म देता है। वैदिक पद्धति और उपनिषदों में कहीं पर भी मंगलसूत्र का जिक्र नहीं है। लेकिन इसे बाद में रूढ़िवादी पुजारियों द्वारा पेश किया गया जब हम हिंदू बन गए। इस प्रणाली को पौराणिक पद्धति या पुराणों/पौराणिक शास्त्रों द्वारा अपनाई गई प्रणाली के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के बाद के हिस्से में वैदिक धर्म की उपेक्षा की गई और हिंदुओं ने इसे पौराणिक में बदल दिया। हां, विवाह में सात फेरों और सिंदूर का वर्णन जरूर मिलता है। एक विवाह में बंधे रहने के लिए चूड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र से ज्यादा आपसी समझ, प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। मंगलसूत्र और चूड़ी जैसी चीजें प्रेम की गारंटी नहीं होतीं।

● ज्योत्सना

बलात्कारी से करो शादी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद एक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी ताकि वह शिकायतकर्ता, जिसका उसने रेप किया था, से शादी कर सके। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील के बावजूद आरोपी को जमानत की अनुमति दे दी कि लड़की की अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी केवल 17 साल की है। बलात्कार कानून का एक नियम है जिस के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, वैधानिक बलात्कार, अपहरण या इसी तरह का कोई अन्य कृत्य करने वाले व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाता है यदि वह पीड़ित महिला से विवाह कर लेता है या कुछ अधिकार क्षेत्रों में कम से कम उससे विवाह करने की पेशकश जरूर करता है। बलात्कारी से विवाह करो कानून अभियुक्त के लिए अभियोजन या दंड से बचाने का एक कानूनी तरीका है। सहमति से बनाए गए संबंधों के बाद अगर कोई शादी से इनकार कर दे तो इसे रेप नहीं माना जाएगा, यह टिप्पणी केरल हाईकोर्ट की है। रेप के आरोप में गिरफ्तार एक वकील की जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बैंच ने यह बात कही थी। साथ ही, आरोपी को जमानत भी दे दी थी।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BS200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

दिखा महिला टीम का दम...

भारत ने चीन को 1-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यह जीत कई मायनों में अहम है। भारत ओलंपिक इतिहास में सबसे सफल हॉकी राष्ट्र है। इसके बावजूद यह एक बड़ी चोट थी कि पेरिस 2024 ओलंपिक में केवल पुरुष हॉकी टीम ने ही हिस्सा लिया। टोक्यो 2020 में चौथे स्थान पर रहने के कारण भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। अगर भारत 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लेता, तो वे क्वालीफाई कर लेता। लेकिन मेजबान चीन ने 4-0 से महिला हॉकी टीम को हरा दिया। हालांकि टीम ने कांस्य पदक जीता, लेकिन यह ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी चोट पर भारतीय महिलाओं ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर मरहम लगाया है।

बिहार के राजगीर में 10 से 20 नवंबर के बीच महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के आठवें संस्करण का आयोजन किया गया। चूंकि बिहार प्रायोजक भी था, इसलिए टूर्नामेंट को बिहार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कहा गया। फाइनल में चीन के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत का श्रेय दीपिका कुमारी को 31वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को जाता है, जो टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। दीपिका ने पूरे टूर्नामेंट में अपने कौशल का बराबर उपयोग भी किया और विश्व हॉकी जगत को यह भी बताया कि क्यों उन्हें श्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है। बता दें कि टूर्नामेंट नवनिर्मित राजगीर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो विशाल आईएससी का हिस्सा है। राजगीर ने छह टीमों की मेजबानी की, जिनमें भारत, चीन, मलेशिया, जापान, थाईलैंड और कोरिया शामिल रहे। यह भी अपने आप में एक कहानी है कि शुरुआत में आलोचकों को राज्य की इस टूर्नामेंट को आयोजित करने की क्षमता पर संदेह था। लेकिन, बिहार ने न सिर्फ इसका सफल आयोजन किया, बल्कि टूर्नामेंट के प्रचार-प्रसार की अहम जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। बाकायदा बिहार सरकार के खेल विभाग, बीएसएसए, हॉकी इंडिया और एशियाई हॉकी महासंघ ने सहयोग किया। 20 नवंबर को बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर भारत को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया। फाइनल का एकमात्र गोल तीसरे क्वार्टर में आया, जब दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर के बाद दूर कोने में बैक-हैंड स्ट्राइक करके भारत को आगे कर दिया। हालांकि, कुछ ही मिनट बाद दीपिका ने चीनी गोलकीपर के शानदार बचाव के बावजूद पेनल्टी स्ट्रोक गंवा दिया। लेकिन भारत ने अपना धैर्य बनाए रखा और लगातार खिताब जीते। नए कोच हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम को यह पहली जीत हासिल हुई है। यह उनका पहला खिताब है। हालांकि, चीन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन वे भारतीय डिफेंस को भेदने में असफल रहे, क्योंकि मेजबान टीम लगभग सभी चार क्वार्टरों तक मजबूत स्थिति में रही। अपने मुख्य कोच एलिसन अन्नान के बिना, उन्होंने काफी साहस दिखाया, लेकिन बिहार में उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा।

साल की शुरुआत में ओलंपिक क्वालीफाइंग मैच में मिली हार के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए यह जीत बहुत जरूरी थी और हरेंद्र सिंह ने उन्हें असफलता को स्वीकार कर, आगे देखना और प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाया। गौरतलब है कि यह भारत का तीसरा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब था, जिसने उन्हें प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र के रूप में कोरिया गणराज्य के बराबर ला खड़ा किया। भारतीय महिलाओं ने 2016 में अपना पहला खिताब जीता और 2023 संस्करण भी अपने नाम किया। इसके अलावा, जापान ने मलेशिया को 4-1 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में तीसरा स्थान हासिल किया था। इधर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के आधिकारिक रूप से समाप्त हुई और उधर बिहार में एक साल से भी कम समय में होने वाले एक और बड़े आयोजन की योजना की तैयारी शुरू हुई। राज्य में पहली बार आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की संगठनात्मक सफलता से उत्साहित, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगले साल पुरुषों के एशिया कप की मेजबानी करेगा। 27 अगस्त से 7 सितंबर तक होने वाला यह आयोजन 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग इवेंट भी होगा और इसलिए यह बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित आयोजन होगा।

उल्लेखनीय है कि एशिया कप आठ टीमों का आयोजन है, जिसमें विजेता को बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले 2026 विश्व कप का टिकट मिलेगा। भारत के अलावा, इसमें जापान, कोरिया, मलेशिया, चीन और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के अलावा एएचएफ कप के कुछ क्वालीफायर भी शामिल होने की संभावना है। पाकिस्तान की मौजूदगी से निश्चित रूप से रोमांच और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे देश में जहां क्रिकेट को अथाह प्रेम मिलता है, हॉकी का ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करना अच्छा है। भारत के शहरी केंद्रों से दूर इस तरह के टूर्नामेंट निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल की वापसी में मदद करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में हॉकी इंडिया ने इस खेल को भारत के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाया है। 2023 एफआईएच विश्व कप का एक हिस्सा राउरकेला में आयोजित किया गया था, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर दूर है। यह जगह राज्य में हॉकी के केंद्र सुंदरगढ़ जिले के मध्य में है। एफआईएच महिला ओलंपिक क्वालीफायर रांची में आयोजित किए गए थे, जबकि राजगीर ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की।

● आशीष नेमा

साल 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म से जुड़े कई किस्से हैं। ये मूवी शोले का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई लेकिन दिलों दिमाग पर छा गई। इस फिल्म के गाने काफी पसंद किए गए। आज भी जब अंताक्षरी खेली जाती है तो य अक्षर आते ही लोगों की जुबान पर जो गाना आता है वो यम्मा-यम्मा भी इसी फिल्म का था।

1980 की वो कल्ट फिल्म, संजीव कुमार थे पहली पसंद

शशि कपूर ने 44 साल पहले जीता था फैंस का दिल

शाकाल ने भी लोगों को खूब डराया। यह वो रोल था जिसे पहले संजीव कुमार करने वाले थे, लेकिन फिर पहला दिल का दौरा पड़ा और कथित तौर पर नासाज सेहत की वजह से वो अलग हो गए और फिल्म उनके हाथ से चली गई। फिल्म का नाम था शान। जिसे आज भी लोग खूब पसंद करते हैं।

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी ने काट ली थी कन्नी... रमेश सिप्पी शोले की स्टारकास्ट रिपीट करना चाहते थे। सब कुछ सेट था लेकिन धर्मेंद्र को अपना रोल कुछ जंचा नहीं और उन्होंने किनारा कर लिया। देखते देखते हेमा ने भी कन्नी काट ली। इस जोड़ी को रिप्लेस किया शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी ने। संजीव कुमार भी फिल्म से बाहर हो गए थे और कुलभूषण खरबंदा ने फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी। गब्बर के बाद शाकाल खलनायकों का सरताज बन गया।

आरआरआर-दृश्यम 2 के बीच चुपके से आई 1 मूवी, एक्टर रातोंरात बन गया स्टार, सबको पछाड़ जीता नेशनल अवॉर्ड

जब हर कोई आरआरआर और दृश्यम 2 की बात कर रहा था, तब अचानक एक फिल्म ने सबको अपना ऐसा मुरीद बनाया कि वे लीड एक्टर के गुणगान गाने लगे। दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स भी उनके फैन बन गए। वे 1 फिल्म से रातोंरात स्टार बन गए थे। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसे आईएमडीबी ने 8.2 रेटिंग दी है और इसके लीड हीरो ने अजय देवगन, जूनियर एनटीआर और अनुपम खेर जैसे स्टार्स को पछाड़कर नेशनल अवॉर्ड जीता था।

एक्टर ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से सिनेमा की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। कांतारा जैसी सिनेमाई मास्टरपीस देने वाले ऋषभ शेट्टी आज भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक बन गए। उन्होंने 2022 में कांतारा के रूप में जो ब्लॉकबस्टर हिट दी, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 2024 में ऋषभ शेट्टी ने अपने फैंस को कई बड़े सरप्राइज दिए, जिन्हें उनकी उपलब्धियों के रूप में याद किया जाएगा।

कांतारा का ओरिजिनल वर्जन 30 सितंबर 2022 को कन्नड़ में रिलीज हुआ था। इसे फिर हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और तुलु भाषाओं में डब किया गया। इस फिल्म ने न केवल साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने का खिताब जीता, बल्कि ऋषभ शेट्टी ने अपने अपने शानदार अभिनय से 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता।

अगर पार्टनर को नहीं पसंद तो..., नयनतारा ने शादीशुदा एक्टर के लिए छोड़ दी थी इंडस्ट्री, 13 साल बाद भी है अफसोस

साउथ फिल्मों की लेडी सुपरस्टार नयनतारा बीते दिनों अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बियॉन्ड द फेरीटेल के चलते सुर्खियों में छाई हुई थीं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नयनतारा के लेडी सुपरस्टार बनने के सफर को बखूबी दर्शाया गया, लेकिन एक्ट्रेस के जीवन में एक समय ऐसा आया था कि प्यार के लिए उन्होंने अपने पहले प्यार एक्टिंग से ही दूरी बना ली थी। एक्ट्रेस ने साल 2011 में उस दौरान अपने बॉयफ्रेंड प्रभुदेवा की वजह से एक्टिंग छोड़ दी थी और तकरीबन दो साल तक वो सिल्वर स्क्रीन से पूरी तरह दूर थीं।

नयनतारा ने द हॉलीवुड रिपोर्ट को दिए इंटरव्यू में उन वक्त अपने बॉयफ्रेंड प्रभुदेवा की सलाह पर फिल्मों से ब्रेक लेने के अपने फैसले के बारे में बात की। एक्ट्रेस कहती हैं, मैं अपनी जिंदगी में उस दौर से गुजर रही थी जब मुझे लगा था कि मुझे प्यार पाने के लिए कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने बताया कि इंडस्ट्री में जिस तरह से रिश्ते थे उसने उनकी सोच पर काफी गहरा प्रभाव डाला था।

वो कहती हैं, हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे अलग तरह के रिश्ते हैं। मैं इसे गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन हम सबने इस इंडस्ट्री को बहुत लंबे समय तक ऐसे ही देखा, जैसे कि दूसरी शादी और भी बहुत कुछ। उस वक्त मुझे लगता था कि वो ठीक था। मेरे अंदर की छोटी सी लड़की को लगता था कि अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी।

लुटेरों के बीच किसान

गूगल गुरु से जब ये पूछा गया कि लुटेरा शब्द का विलोम क्या है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए वह निरुत्तर हो गया और यही कहा कि लुटेरा शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं होता, क्योंकि यह एक गणनीय संज्ञा है। यह तो कोई उचित और तर्कपूर्ण उत्तर नहीं हुआ। अर्थात् जो किसान, सबका अन्नदाता है : लुट तो सकता है, ठगा जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है; वह किसी को लूट पाने के गुण से वंचित होता है। उसे सब लूट सकते हैं; किन्तु वह किसी को भी लूटने की क्षमता से शून्य होता है। ये विचित्र विडम्बना है!

जब कोई व्यक्ति बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो उसके मूल्य का निर्धारण और वाचन विक्रेता दुकानदार ही करता है। सोना, चांदी, लोहा, बर्तन, कपड़ा, बाइक, कार, ट्रक, बस, टिकट, सीमेंट, बालू, सरिया, जमीन, मकान, प्लॉट, फ्लैट आदि संसार की समस्त वस्तुओं का मूल्य बताने या मांगने वाला उसका विक्रेता ही होता है। कोई दुकानदार कभी किसी ग्राहक (क्रेता) से यह नहीं पूछता कि क्या भाव खरीदोगे? क्या दाम दोगे? बेचारे किसान को ही मंडी या बाजार में पूछना पड़ता है कि सेठ जी गेहूं किस भाव खरीदोगे? आलू किस भाव क्रय करोगे? बैंगन, मिर्च, टमाटर, अरबी, मिर्च, टिंडा, गोभी, गरमकल्ला, भिंडी, बंदगोभी, जौ, चना, मटर, सरसों, अरहर, उर्द, मूंग आदि किस भाव लोगे? किसान के साथ समाज देश और दुनिया ने ये कैसा मजाक बना रखा है कि जो उसका उत्पादक और मालिक है; वह खरीददार से पूछ रहा है कि मूल्य क्या लगाओगे! कैसी मूर्खतापूर्ण बात है!

जब किसान मंडी में अपनी सब्जी लेकर पहुंचता है तो साफ और साबुत आढ़तिया छंटनी कर लेता है और थोड़ा सा भी खराब होने पर उसे निकालकर सड़क पर ऐसे फेंकता है, जैसे यह सब कुछ उसके पिताजी के खेत से बिना लागत, बिना खाद पानी, बिना निराई-गुड़ाई और बिना श्रम के ही आ विराजा हो। बड़े नखरे और रौब दाब के साथ किसान से व्यवहार क्या दुर्व्यवहार ही किया जाता है और उधर किसान की सेहत पर कोई असर ही नहीं। उसमें भी नकद गिनने पर हजार बहाने! परसों आना, एक हफ्ते बाद ले जाना! या माल बिकने पर मिलेगा आदि आदि। जिधर भी देखिए किसान के लुटेरे बैठे हैं। सारा बाजार और मंडियों में बैठे ठग उसे ठग रहे हैं और वह निरीह प्राणी बना हुआ सबकुछ सहन किए जा रहा है। यह किसान का वीभत्स अपमान है। सबसे बड़ी और बुरी बात ये भी है कि इस मुद्दे पर समाजसेवी, धर्म धुरंधर, नेता, अधिकारी, शासन-प्रशासन सरकारें मौन बैठी हैं, कानों में तेल और मुंह पर फेविकॉल लगाए हुए! जैसे किसी को कोई मतलब नहीं है। जबकि सारा देश सामाज और व्यक्ति उसी किसान के पसीने का

बेचारे किसान को ही मंडी या बाजार में पूछना पड़ता है कि सेठ जी गेहूं किस भाव खरीदोगे? आलू किस भाव क्रय करोगे? बैंगन, मिर्च, टमाटर, अरबी, मिर्च, टिंडा, गोभी, गरमकल्ला, भिंडी, बंदगोभी, जौ, चना, मटर, सरसों, अरहर, उर्द, मूंग आदि किस भाव लोगे? किसान के साथ समाज देश और दुनिया ने ये कैसा मजाक बना रखा है कि जो उसका उत्पादक और मालिक है; वह खरीददार से पूछ रहा है कि मूल्य क्या लगाओगे! कैसी मूर्खतापूर्ण बात है!

अन्न, फल-सब्जी आदि खाता है। वह तो गनीमत है कि गाय-भैंस या बकरी आदि के दूध का मूल्य उसका मालिक ही लगाता है अन्यथा यदि चाय के चुक्कड़ों पर छोड़ दिया जाए तो मुफ्त में ही दुह ले जाएं!

किसान की उक्त लूट और देश की लुटेरी प्रवृत्ति का कारण ढूंढने चलें तो उसके मूल में किसान की गरीबी और धनहीनता ही है। यदि देश के किसान की हालत सुधरी हुई और सम्पन्नता की रही होती तो ये सभी लुटेरे लूट स्थल मंडियों में नहीं बुलाते! जरूरतमंद को किसान के पास ही तेल लगाने जाना पड़ता। शासन-प्रशासन भला क्यों चाहने लगा कि किसान को उसकी फसल का कुछ ऐसा मूल्य मिले कि वह सम्पन्न हो सके! यदि किसान सम्पन्न हो गया तो सब भूखे मर जाएंगे। वह बराबर कर्जदार बना रहे, यही बैंकों, शासन और सरकारों के हित में है! लड़की-लड़कों की विवाह शादी में ऋण के बिना उसका काम नहीं चल सकता। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। विदेश नहीं जा सकते।

गलत काम किए बिना कोई अमीर नहीं बनता। जो ईमानदार और स्वच्छ है उसी को सब लूट रहे हैं। इस दिशा में सत्य ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। जहां झूठ, बेईमानी, दुराचार, असत्य, अनाचार, अत्याचार और शोषण का बोलबाला है, वही फल-फूल रहा है। पैसा कठिन परिश्रम से अर्जित नहीं होता, तिकड़म और तड़क-भड़क से होता है। जो जितना बड़ा बेईमान, वह उतना ही सम्मानवान। दुनिया और समाज में उसका उतना ही बड़ा वितान। वही सबसे बड़ा पहलवान, धनवान।

किसान होना एक अभिशाप से कम नहीं। किसान जैसा संतोषी और सर्वाधिक दुखी कोई नहीं। क्योंकि सब उसे लूट खाने के लिए बैठे हैं। लूट खा ही रहे हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या देना? अपने-अपने कुर्ते में झांक लेना। एक अनार सौ बीमार। सब उसे चूसने के लिए अहर्निश तैयार। इसलिए हे किसानों! हे अन्नदाताओं! हो जाओ होशियार। इन लुटेरों से बच के रहो! खबरदार! क्योंकि मानवमात्र के तुम्हीं हो पालनहार। अपने अस्तित्व और अस्मिता को पहचानो। किसान संगठन बनाओ और एकता का शंख गुंजाओ। तभी तुम्हें इस लुटेरी व्यवस्था से निजात मिल सकेगी। राजनेताओं और राजनीति के जाल में मत फंस जाना। अन्यथा पड़ेगा तुम्हें बहुत-बहुत पछताना। अब समय आ गया है कि किसान अपने को जानें, पहचानें।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

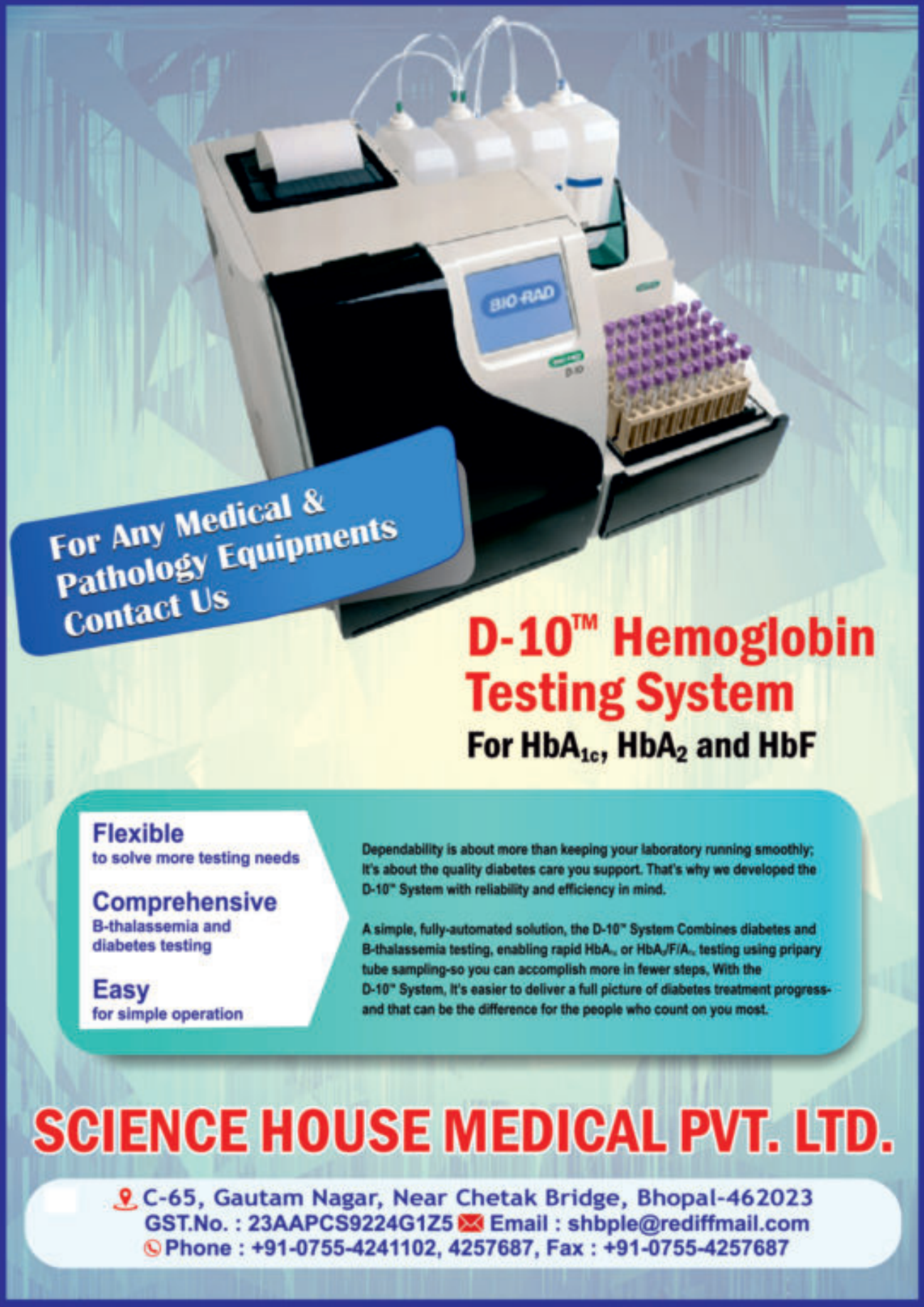

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

प्रकृति के सम्मान का उत्सव

गौ-संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिनव पहल

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रदेशभर की गौ-शालाओं में गोवर्धन पर्व का सामुदायिक आयोजन

प्रगति और पर्यावरण के प्रति सजगता की मिसाल बनता मध्यप्रदेश

- प्रदेश में संचालित 1,500 से अधिक गौ-शालाओं में 3.30 लाख गौ-वंश का पालन। शीघ्र ही लगभग 2,500 नई गौ-शालाएं प्रारंभ होंगी जिनमें 4.50 लाख गौ-वंश का पालन हो सकेगा।
- गौ-वंश के बेहतर आहार हेतु प्रति गौ-वंश 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये की जा रही है।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू। आगामी 5 वर्षों में लगभग 12,000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करेंगी।
- देश में सर्वाधिक 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती करने वाले मध्यप्रदेश में गौ-वंश को प्रोत्साहन देने की पहल से जैविक खेती उत्पादन बढ़ेगा।
- दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
- गौ-शालाओं का बजट 150 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2024